असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

20 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा | मंगलवार, तिथि 20 फरवरी, 2024 ई॰

एकादश सत्र | 01 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य स्थगन है ।

अध्यक्ष : कार्य स्थगन अभी हो सकता है ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इसीलिये दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों की बुरी हालत हो गयी है ।

अध्यक्ष : शून्यकाल में उठाइयेगा ।

(व्यवधान जारी)

समय पर उठाइयेगा । अभी प्रश्नोत्तर काल है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

कोई बात इस तरह से आपकी नहीं सुनी जायेगी, अपने स्थान पर जाकर बोलिये । स्थान पर जाकर अपनी बात कहिये, जो विषय रखना होगा वह शून्यकाल में रखियेगा ।

(व्यवधान जारी)

अभी प्रश्नोत्तर काल है । दूसरी चर्चा नहीं हो सकती है ।

(व्यवधान जारी)

अभी कोई बात आपकी कार्यवाही में दर्ज नहीं की जायेगी । विषय रखना होगा तो शून्यकाल में आपको मौका देंगे ।

(व्यवधान जारी)

बैठिये, शून्यकाल में बोलने का मौका देंगे । अभी बैठिये।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देना है । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाकर बोलिये, यहाँ से कोई बात दर्ज नहीं की जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । आप तो समझदार आदमी हैं, पुराने आदमी हैं । आप तो जानते ही हैं कि कब कौन-सा विषय रखना है, आप जानकार हैं । शून्यकाल में आपको मौका देंगे । बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

सत्यदेव जी, शून्यकाल में आपको मौका देंगे । अभी बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है तो समय पर उठाइयेगा न । समय पर उठाइयेगा तो आपको बोलने का मौका देंगे । अपने स्थान पर जाकर बैठिये । बैठ जाइये, बैठ जाइये, मान जाइये ।

(व्यवधान जारी)

आप भी बैठ जाइये । आमने-सामने बैठ जाइये, क्या दिक्कत है ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गए)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-9 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार जायसवाल जी का प्रश्न परिवहन विभाग से था, वह ट्रांसफर होकर पथ निर्माण विभाग में चला गया है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-10 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)

अध्यक्ष : यह प्रश्न भी परिवहन विभाग से था, वह ट्रांसफर होकर पथ निर्माण विभाग में चला गया है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-11 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-82, दरभंगा ग्रामीण)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-640, दिनांक-19.01.2015 के द्वारा महिला कर्मचारियों

को समस्त सेवा अवधि काल के दौरान केवल दो संतान तक दो वर्ष (यानी 730 दिन) की शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है । उक्त प्रावधान से बी॰पी॰एस॰सी॰ से चयनित महिला शिक्षक भी आच्छादित हैं । ज्ञातव्य हो कि शिशु देखभाल अवकाश साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाती है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया हुआ है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, जिस तरह से बी॰पी॰एस॰सी॰ के शिक्षक के संबंध में कहा गया है, इसमें नियोजित शिक्षक के संबंध में कोई उत्तर नहीं है तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक के बारे में उत्तर में स्पष्ट नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वे सही कह रहे हैं कि ये 730 दिन जो मातृत्व से लेकर शिशु पालन अवकाश मिलता है, वह सरकारी कर्मियों को ही देय होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक होने का रास्ता भी बना ही दिया है । ये लोग भी सरकारी शिक्षक बन जायेंगे, हमने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको 730 दिन का जो मातृत्व से लेकर शिशु देखभाल अवकाश मिल रहा है, बी॰पी॰एस॰सी॰ से नियुक्त शिक्षकों को भी मिल रहा है और नियोजित शिक्षक जैसे ही सरकारी शिक्षक हो जायेंगे, उनको भी उपलब्ध हो जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री अचमित ऋषिदेव ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, ये जो अभी हमसे आकर पूछ लिये तो शिक्षकों के बारे में डिपार्टमेंट ने उनका कर दिया था सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक, तो हमने पहले ही कहा है कि सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक नहीं होना चाहिए, यह तो सुबह 10 बजे से शाम 04 बजे तक होना चाहिए । यह हमने कहा है और अगर अभी उसको नहीं माना है....

(व्यवधान)

आप लोग देख रहे थे तो कहते कि आपकी बात नहीं माना । अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही देख रहे थे, कहते कि नहीं सुना । उसी समय हम कार्रवाई

करते, अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुलाकर बात करेंगे और जो बात है पहले से, यह तो हम शुरू से बोलते हैं ।

(व्यवधान)

बैठिये न ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, महबूब साहब । सत्यदेव जी, बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, हम भी तो पढ़ते ही न थे, यह जो तरीका है भला बताइये सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक, यह ठीक नहीं है । अगर यह गलत किया है तो उसे तुरंत सुधार करवा देते हैं । हम आज ही देख लेते हैं । बैठ जाइये आराम से । आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ । आज ही हम बात कर लेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । सुन तो लीजिये न । माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । महबूब साहब, बैठ जाइये । महबूब साहब, आपको तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो सवाल सत्यदेव जी उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी पूर्ति करने का काम किया है । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न</u>

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-217 (श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र संख्या-47, रानीगंज (अ०जा०))</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-218 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र संख्या-62, पूर्णियाँ)</u>

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1-उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत इंदिरा गाँधी स्टेडियम, रंगभूमि मैदान, पूर्णियाँ में एथलेटिक्स गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

3- उत्तर खण्ड-2 में सन्निहित है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया हुआ है । खंड-क में उत्तर स्वीकारात्मक है और हम सबसे पहले, यह जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : जी, महोदय । पूरक से संबंधित है । प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया लाने का काम किया और पूरे देश में, विश्व में ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी जा कर गोल्ड मेडल लाने का काम किये और बिहार में मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने खेल विभाग अलग बनाया और खेल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में जो गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है । खंड-2 में, हमारे यहाँ पूर्णियाँ में जो स्टेडियम, रंगभूमि मैदान है, उसकी स्वीकृति मिली है लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम आसन के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि हमारे देश में जो दो खेल हैं, जो भारतीय खेल हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूरक से संबंधित है । कबड्डी खेल भारतीय उप महाद्वीप में खेला जाता है और जो कुश्ती खेल है, उसका तो जन्म ही भारत में हुआ है ।

अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ?

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूरक से संबंधित है । हमारे पूर्णियाँ में भी जो गुनगुन चौहान है, लवली कुमारी है, मनीषा कुमारी है, विश्वजीत सिंह है....

अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ?

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, ये जो खिलाड़ी हैं, ये सब नेशनल खेले हैं, स्टेट खेले हैं । इसलिए हमारा आग्रह है कि मुंसीबाड़ी, गुलाबबाग हाँसदा, बनवासी कल्याण आश्रम का जो खेल मैदान है, वे सारे मानक को पूरा करते हैं । इसलिए हम आग्रह करेंगे कि 38 जिले में 50 इस तरह के केन्द्र होने हैं । इसलिए पूर्णियाँ में भी इस केन्द्र की स्थापना हो ताकि ये दोनों खेल जो हैं इसको प्रोत्साहन मिले, हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में खेल सकें, यह मेरा सरकार से आग्रह है ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-219 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र संख्या-165, मुंगेर)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिला मुख्यालय में अवस्थित श्री कृष्ण सेवा सदन को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1966 में जिला

केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी थी । वर्तमान में जिला पदाधिकारी मुंगेर से प्रस्ताव प्राप्त कर विभागीय ज्ञापांक–728, दिनांक–30.12.2023 द्वारा उत्क्रमित करते हुए प्रमण्डलीय पुस्तकालय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है । निदेशानुसार श्री कृष्ण सेवा सदन प्रमण्डलीय पुस्तकालय, मुंगेर के जर्जर भवन के जीर्णोद्धार हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर से तकनीकी अनुमोदन सहित प्रस्ताव की माँग की गयी है । उनके द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पुस्तकालय का प्रस्ताव एक माह के अंदर उपलब्ध करा दी जायेगी । जिला पदाधिकारी, मुंगेर ने भी प्रतिवेदित किया है कि इस पुस्तकालय में लगभग प्रतिदिन 160 से 170 की संख्या में छात्र एवं छात्राएं अध्ययन करते हैं । इन पाठकों की सुविधा हेतु पुस्तकालय में 06 पुस्तकाध्यक्ष प्रतिनियुक्त हैं ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है । बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर वर्ष 1966 में केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में अवस्थित है । आज स्थिति यही है कि वह जर्जर अवस्था में है । कई दुर्लभ पुस्तकों को दीमक खा गया है, उसका रख–रखाव करने का नहीं है....

अध्यक्ष : ये तो प्रश्न आपने किया ही है, सरकार ने जवाब दिया है उसके आलोक में कोई पूरक है तो पूछिये ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, जब भी अधिकारी को लिखते हैं तो वह यही कहता है कि एक महीना के अंदर में हो जायेगा लेकिन यह एक महीना कब तक आयेगा ? हम यह जानना चाहते हैं ।

टर्न–2/संगीता/20.02.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि यह एक महत्वपूर्ण संस्था है और श्री बाबू के नाम पर संस्था है और इसीलिए सरकार ने इसकी अहमियत को समझते हुए इसे प्रमंडलीय पुस्तकालय का भी दर्जा दिया है और हमलोगों ने कहा है कि एक महीने के अंदर हमलोग इसका प्राक्कलन मंगाकर इसकी मरम्मति आदि का काम करायेंगे । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि एक

अधिकारी कोई बाहर में बोलता है और सरकार जो सदन में बोलती है इन दोनों में फर्क होता है यह समझना चाहिए ।

अध्यक्ष : दोनों में अंतर है, ठीक है ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह है कि उस पुस्तकालय को ई-लाइब्रेरी के रूप में, सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ई-लाइब्रेरी के रूप में उसको परिणत किया जाय ।

अध्यक्ष : चलिए, अलग से पूछिएगा तब इसका जवाब मिलेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-220 (श्री मुरारी मोहन झा, क्षेत्र संख्या-86, केवटी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा अंतर्गत मध्य विद्यालय सिरहुल्ली अवस्थित है । उक्त विद्यालय के भवन को नदी के कटाव से बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पूर्व में किया गया है । जियो बैग डालकर सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है । वर्तमान में भवन एवं चहारदीवारी की स्थिति सही है । पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-286 दिनांक-17.02.2024 द्वारा कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा को मध्य विद्यालय सिरहुल्ली के कटाव से बचाव हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, सिरहुल्ली, सिंघवाड़ा प्रखंड में है, वहां एक स्कूल है । महोदय, पिछले साल वहां...

अध्यक्ष : पहले ये तो बोलिए कि पूछता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : जी पूछता हूं । अध्यक्ष महोदय, वह स्कूल जो है उस स्कूल के लास्ट दीवार तक पानी का जोर मारता है और धौंस नदी है । धौंस नदी के कारण पिछली बार करोड़ों रुपया का उसमें सिंचाई विभाग के द्वारा काम करवाया गया...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, वह काम कब तक हो जाएगा हम यह मंत्री जी से जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें तो माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं सरकार ने तो सबको माना है । माननीय सदस्य ने भी कहा है कि पिछले वर्ष उसमें बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराकर विद्यालय को सुरक्षित रखा गया है और आपने प्रश्न में भी यही पूछा है कि इस विद्यालय के कटाव से सुरक्षित रखना चाहती है । हमने कहा है कि आगामी कटाव या बाढ़ के समय को देखते हुए जो आवश्यक कार्य होगा, चाहे कटाव निरोधक काम या बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, वह सरकार करेगी और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस विद्यालय का भवन सुरक्षित रहे ।

अध्यक्ष : चलिए, बढ़िया है ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, उसको रिटेनिंग वॉल करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : हो गया, सरकार ने कहा जो आवश्यक होगा वे करेंगे ।

श्री मुरारी मोहन झा : जी, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-221 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र संख्या-67, मनिहारी (अ0ज0जा0))

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए मनोहर जी ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : इनको उत्तर नहीं मिला है । मंत्री जी, उत्तर बता दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के कुमारीपुर पंचायत के मध्य विद्यालय कुमारीपुर में कुल 610 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं तथा कुल 15 शिक्षक-शिक्षिका कार्यरत हैं । विद्यालय में कुल 9 कमरे हैं, जिसमें से 5 वर्ग कक्ष में पठन-पाठन संचालित है और एक वर्ग कक्ष का आंशिक मरम्मति कार्य भी प्रगति में है । 4 वर्ग कक्ष पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, उसको तोड़कर उसके स्थान पर 4 वर्ग कक्ष एवं 602 फीट चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए 12 लाख 59 हजार 824 रुपये का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है । महोदय, इसको अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिए, ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-222 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र संख्या-165, मुंगेर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि BRM कॉलेज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए छात्रावास जर्जर एवं मरम्मती योग्य नहीं होने के कारण वर्ष 1993 से संचालित नहीं है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुंगेर जिला में अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, आर0डी0 एण्ड डी0जे0 कॉलेज तथा अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, हरि सिंह कॉलेज, खड़गपुर संचालित है ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : पहले पूछिए कि मैं पूछता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, जवाब मिला है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री प्रणव कुमार : पूरक पूछ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय । जवाब मिला है, वर्ष 1993 से महिला छात्रावास है अनुसूचित जाति के लिए वह बंद है और दूसरा जो जवाब दिया है वह अनुसूचित जाति छात्र के लिए छात्रावास है तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रा के लिए जो 1993 से बंद है, क्या सरकार पुनः उसको डिसमैटलिंग करके उसको छात्रावास बनाना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है और अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । आगे वित्तीय वर्ष में ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो जरूर सरकार इसपर विचार करेगी ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, वह मुंगेर प्रमंडल का सबसे प्रतिष्ठित महिला कॉलेज है और मुंगेर प्रमंडल में अनुसूचित वर्ग की बहुत सी छात्राएं हैं जिनको पढ़ने में असुविधा होती है । वे प्राईवेट लॉज में रहती हैं इसलिए हम चाहेंगे कि शीघ्र से शीघ्र उसको बनाया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री अजय यादव ।

(व्यवधान)

उन्होंने कहा है कि अभी नहीं है लेकिन उसपर आगे विचार करेंगे तो बनायेंगे ।

(व्यवधान)

कब से बंद है ?

श्री अखतरूल ईमान : 1993 से ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है संज्ञान लिया मंत्री जी ने, करेंगे । बैठिए । सत्यदेव जी बैठिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री अजय यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-223 (श्री अजय यादव, क्षेत्र संख्या-233, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-224 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र संख्या-214, अरवल)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1- अस्वीकारात्मक ।

जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-131, दिनांक-16.02.2024 से प्रतिवेदित है कि अरवल जिलान्तर्गत वर्तमान में सोन नदी में मात्र 04 बालूघाट (कलेर प्रखण्ड के मौजा-सोहसा-मैनपुरा, अरवल प्रखण्ड के मौजा-मखदुमपुर, सोनवरसा एवं कोरियम) से बालू का खनन एवं प्रेषण का कार्य किया जा रहा है । खनन कार्य खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान, वन एवं पर्यावरण विभाग, सिया, बिहार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के शर्त्तों एवं बंधेजों के साथ निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित मात्रा पर नियमानुसार किया जा रहा है ।

2- अस्वीकारात्मक ।

उपरोक्त कंडिका-01 में वर्णित बालूघाटों से निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित मात्रा पर नियमानुसार बालू का उत्खनन एवं प्रेषण वन एवं पर्यावरण विभाग, सिया, बिहार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के शर्तों एवं बंधेजों के साथ किया जाता है । उत्खनन कार्य के कारण चापाकल के पानी का सूखने एवं सांस की बीमारी का मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

3- उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब मिला है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, पूरक में सबसे पहले तो मैंने जो सवाल किया था, उस सवाल के सही जवाब नहीं दिए गए हैं । महोदय, यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जो भी सवाल किए जाते हैं उसके अनाप-शनाप और उलटा-पुलटा जवाब दिये जाते हैं।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, वही मैं कह रहा हूं । ये वहां दो सवाल हमने उठाया था कि बालू खनन से जो प्रभाव पड़ रहा है उस इलाके में, उसमें स्वास्थ्य पर और जल स्तर पर लेकिन ये दोनों मामले में जो जवाब दिए गए हैं बहुत ही उलटा-पुलटा जवाब, बिना जांच-पड़ताल किए हुए । महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को खांसी और सांस की बीमारी बढ़ गई है इधर । जबसे बालू की ढुलाई शुरू हो गई है, इतना धूल उड़ता है उस वजह से फसल की बर्बादी होती ही है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर होता है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न पूरक ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, वही सवाल है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो जल स्तर भी नीचे गया है और वजह से दर्जनों गांवों में ये सोहसा से लेकर कमता मठिया और कमता और अरवल के शाही मोहल्ला दूना छपरा कई दर्जनों गांव हैं जहां से बालू उठाव का केंद्र है । महोदय, वहां जल स्तर नीचे होने से दर्जनों चापाकल बंद हो गए हैं महोदय...

अध्यक्ष : आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप पूरक पूछिए ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, इसका जिला प्रशासन ने चापाकल गड़वाने का निर्णय भी लिया था लेकिन अभी तक नहीं गाड़ा गया और उसका जवाब अस्वीकारात्मक दिया गया है एक तो यह है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री महा नंद सिंह : और दूसरा, दूना छपरा में करीब 9-10 लोगों को असमय खांसी की बीमारी हो गई है, मेरे पास लिस्ट है महोदय । सोहसा में 7-8 लोगों को खांसी की बीमारी हो गई है...

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री महा नंद सिंह : दमा की बीमारी हो गई है महोदय । फसल बर्बाद हो जाते हैं महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, इसके बचाव के लिए...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, इसके बचाव के लिए सरकार से मैंने मांग की थी कि वहां जो 2-3 दिक्कतें हो रही हैं, जल स्तर नीचे जा रहा है, इसके लिए चापाकल गड़वाने का...

अध्यक्ष : सरकार बोल रही है न, आप बैठिएगा तब न ।

श्री महा नंद सिंह : जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न था उसका जवाब स्पष्ट तौर पर विभाग ने दिया है और जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-131 दिनांक-16.02.2024 से प्रतिवेदित है, अभी करेंट मंगाया गया है । अरवल जिलान्तर्गत वर्तमान में सोन नदी में मात्र 04 बालूघाट (कलेर प्रखण्ड के मौजा-सोहसा-मैनपुरा, अरवल प्रखण्ड के मौजा-मखदुमपुर, सोनवरसा एवं कोरियम) से बालू का खनन एवं प्रेषण का कार्य किया जा रहा है । खनन कार्य खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान, वन एवं पर्यावरण विभाग, सिया, बिहार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के शर्तों एवं

बंधेजों के साथ निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित मात्रा पर नियमानुसार किया जा रहा है । अब इनका कहना है कि अगर जो उल्लंघन है तो वह पर्टिकुलर बताएं वैसे जगह का, हमलोग उस विभाग से उसको दिखवा लेते हैं ।

टर्न–3/सुरज/20.02.2024

श्री महा नंद सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : एक काम करिये आप माननीय सदस्य...

श्री महा नंद सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : सुन लीजिये मेरी बात, सुन तो लीजिये । विषय गंभीर है अगर किसी कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं, यह हम सबके लिये चिंता का विषय है । मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो रिपोर्ट कलेक्टर का आया है इन्होंने बताया है, माननीय मंत्री महोदय ने और यह भी कहा है कि कोई विशेष बात आती है कहीं ध्यान में तो उसको देखा जायेगा । मेरा आपसे निवेदन है...

श्री महा नंद सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट सुन लीजिये न...

श्री महा नंद सिंह : महोदय मैंने सवाल...

अध्यक्ष : पूरी बात सुनिये न भाई, सुन तो लीजिये, बैठ जाइये । मेरा आपसे आग्रह है कि जो लोग बीमार पड़े हैं, बाकी हैं आप एक बार उनकी सूची माननीय मंत्री जी को दे दीजिये जरूर इसको दिखवाया जायेगा । क्योंकि लोग किसी कारण से बीमार पड़ते हैं तो उसकी चिंता करना सरकार का काम है । ठीक है ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, मैंने इसमें सवाल ही किया था विशेष सर्वे के आधार पर जांच करवायी जाय, एक कमेटी के जरिये जांच करवायी जाय । महोदय, जो रिपोर्ट दिया गया है, वह ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार किया गया है ।

अध्यक्ष : आपको समाधान तो बता रहे हैं न । अगर कोई बीमार पड़ा है तो उसकी सूची दे दीजिये जरूर सरकार देखेगी, उसकी चिंता करेगी । बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : नहीं महोदय, यह विषय चिंता का है...

अध्यक्ष : कर रहे हैं चिंता । सरकार भी चिंता कर रही है, हमलोग भी कर रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : जिला समाहर्त्ता आफिस में बैठे-बैठे रिपोर्ट बनाता है...

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये ।

श्री सत्यदेव राम : और लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी उसको चिंता नहीं है ।

अध्यक्ष : उनको अगर नाम दे देंगे तो कोई दिक्कत है क्या । माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, कब तक यह होगा ?

अध्यक्ष : आप दीजियेगा सूची तो तुरंत कार्रवाई करेगी सरकार, बैठिये । कृष्णनंदन पासवान जी । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : हो तो गया, अब क्या है ?

श्री सत्यदेव राम : माननीय सदस्य सवाल करेंगे और जिला समाहर्त्ता ऑफिस में बैठे-बैठे रिपोर्ट लिख देगा...

अध्यक्ष : हो गया । कृष्णनंदन पासवान जी...

श्री सत्यदेव राम : और मंत्री जी पढ़ देंगे तो आपकी जनता का क्या होगा ?

अध्यक्ष : सब सही होगा, बैठिये ।

श्री सत्यदेव राम : नहीं महोदय, यह बैठने वाली बात नहीं है...

अध्यक्ष : मैंने बताया आपको कि दे दीजियेगा अगर बीमार पड़ा है तो देखेगी सरकार । अब यहां जबरदस्ती थोड़े ही हो सकता है...

श्री सत्यदेव राम : इस पर माननीय मंत्री जी को बोलना चाहिये ।

अध्यक्ष : उन्होंने भी कहा, मैं खुद कहा रहा हूं यहां से । मैंने खुद कहा है माननीय मंत्री जी को दिखवाने के लिये, लिस्ट दे दीजिये उनको ।

श्री सत्यदेव राम : माननीय सदस्यों के सवालों का...

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये । यह भाषण का समय नहीं है । श्री कृष्णनंदन पासवान जी । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक निवेदन था...

अध्यक्ष : बैठिये, आगे बढ़ गये हैं हम । उनको कहा है वे लिस्ट दे देंगे, सूची दे देंगे, जांच करायेंगे तुरंत ।

श्री सत्यदेव राम : गंभीर सवाल है महोदय..

अध्यक्ष : बैठिये न, हो तो गया । अच्छा क्या होगा बोलिये, क्या किया जाय । हमको एक बात बताइये सत्यदेव जी...

(व्यवधान)

सत्यदेव जी, दूसरे की भी बात सुनिये न । चलिये जवाब दीजिये । नहीं आपको सुनना है तो । बताइये मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-225 (श्री कृष्णनंदन पासवान, क्षेत्र सं0-13, हरसिद्धि(अ0जा0))

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर दिया हुआ है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के यादोपुर पंचायत, वार्ड नंबर 8 में स्थित अनुसूचित जाति बस्ती से लगभग 2.4 किलोमीटर की दूरी पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, चैनपुर है । यादोपुर पंचायत, वार्ड नंबर 8 के अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक के लिये उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय यादोपुर है, जो यादोपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 से लगभग 2.4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार मध्य विद्यालय यानी 01 से 08 तक की स्थापना किसी बसाव-क्षेत्र में 03 किलोमीटर तक की सीमा में करने का प्रावधान है और जैसा कि अध्यक्ष महोदय हमने कहा कि इस अनुसूचित जाति के बस्ती के बच्चे जो ढाई किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्कूल

है, उसमें अध्ययन कर रहे हैं और तीन किलोमीटर से अधिक होता है अभी, तभी कोई दूसरे विद्यालय की स्थापना की बात होती है इसलिये फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि जो जांच रिपोर्ट वहां से आया है, जांच रिपोर्ट सही नहीं है । तीन किलोमीटर दूरी से चूंकि हमारा क्षेत्र है, घूमते हैं तीन किलोमीटर की दूरी से अधिक है ऐसा रिपोर्ट आया है । फिर भी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अनुसूचित जाति बस्ती में केवल एक ही विद्यालय है और वहां दलित के बच्चे पढ़ते हैं । इसका ध्यान रखते हुये माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय में परिणत किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है दिखवा लेंगे । श्री अजय कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या–226 (श्री अजय कुमार, क्षेत्र सं0–138, विभूतिपुर)

श्री अजय कुमार : सर, जवाब नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, यादव टोल, सिरसी अवस्थित है । उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निविदा की कार्रवाई पूर्ण करते हुये राज्य द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से प्राथमिक विद्यालय, यादव टोल, सिरसी का भवन निर्माण करा लिया जायेगा । इसका निर्माण हमलोग अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे अजय जी का ।

श्री अजय कुमार : धन्यवाद सर । श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–227 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र सं0–79, गौड़ाबौराम)

श्रीमती स्वर्णा सिंह : महोदय, जवाब नहीं मिल पाया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अब पीछे की स्थिति तो काफी लंबी है लेकिन उसका ऑपरेटिव पार्ट इतना ही है कि इस प्रश्नगत विद्यालय में तीन अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में यह काम करा दिया जायेगा ।

वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड गौड़ाबौराम में प्राथमिक विद्यालय बिनोवा नगर, गौड़ाबौराम में 02 वर्ग कक्ष के अतिरिक्त 01 प्रधानाध्यापक कक्ष उपलब्ध है, जो जर्जर स्थिति में है । उक्त विद्यलाय में नामांकित बच्चों की सं0-89 है । जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-260 दिनांक-13.02.2024 द्वारा उक्त विद्यालय को निकटतम मध्य विद्यालय, भदौन गौड़ाबौराम में शिफ्ट किया गया है ।

प्राथमिक विद्यालय बिनोवा नगर के लिये 03 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुये भवन निर्माण कार्य शीघ्र ही करा लिया जायेगा ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : महोदय, एक चीज मैं बताना चाहूंगी मंत्री महोदय से...

अध्यक्ष : हो गया, अब क्या ?

श्रीमती स्वर्णा सिंह : सिर्फ एक चीज कि वहां दो दिन से इंजीनियर भवन तोड़ रहे हैं तो इसको थोड़ा जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जाय । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : तोड़ेंगे तब तो नया बनेगा । श्री रामविलास कामत । जवाब मिला है न ।

तारांकित प्रश्न संख्या-228 (श्री रामविलास कामत, क्षेत्र सं0-42, पिपरा)

श्री रामविलास कामत : महोदय, जवाब नहीं मिला है । ऑनलाईन भी उपलब्ध नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय गोढ़ियारी के भवन निर्माण हेतु 170 डी0 भूमि उपलब्ध है । परन्तु वह भूमि कोशी नदी के कटाव क्षेत्र में अवस्थित है । वहां पक्का मकान बनाना संभव नहीं है, वर्तमान में टीन के शेड में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, नामांकित छात्र/छात्रा की संख्या 160 है । भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये प्री-फैब संरचना का निर्माण कराया जायेगा ।

पिपरा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय झिटकियाही में कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या 448 है, कुल शिक्षकों की संख्या 09 है । विद्यालय में 04 कमरे एवं 01 प्रधानाध्यापक कक्ष है । प्राक्कलित राशि 29.59

लाख से 03 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण की भी यहां योजना है जो अगले वर्ष करा लिया जायेगा ।

श्री रामविलास कामत : बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री जी ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-229 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156, भागलपुर)

श्री अजीत शर्मा : महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : आप भी संज्ञान महोदय ले लीजिये, बैठे-बैठे बोल दिये तो ।

अध्यक्ष : नहीं, मैंने सुना नहीं, आवाज केवल आयी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, एक चीज और आसन से हम आग्रह करेंगे कि हमारे कुछ साथी बहुत ऊंची आवाज रखने वाले हैं, जिनको माइक की आवश्यकता ही नहीं होती है, बैठे भी बोलते हैं तो सारे सदन को लगता है कि वह माइक से ही बोल रहे हैं ।

महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति दर्ज करने के अतिरिक्त सभी शिक्षकों को नोटकैम ऐप के माध्यम से फोटो खींचकर विद्यालय में ससमय उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य भेजनी पड़ती है । बायोमैट्रिक की मशीन अभी विद्यालयों में नही लगायी गयी है । अभी जो व्यवस्था है यह कारगर व्यवस्था है और वैसे विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के अतिरिक्त नोटकैम ऐप से फोटो खींचकर भेजने का कर दिया है । जहां तक शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का प्रश्न है शिक्षक दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसरों पर निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को सरकार पुरस्कृत करती है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मेरा पूरक है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि शिक्षकों को सरकारी स्मार्ट मोबाईल दिया गया है या नहीं जिससे कि वे सेल्फी लेकर भेजें । दूसरा, मेरा पूरक है । मेरा मूल प्रश्न यही है कि सरकार कब तक सभी स्कूलों में बायोमैट्रिक सिस्टम लगवाने पर विचार रखती है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जिस बायोमैट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसके जो फायदे होते हैं या उससे जो काम होता है । हमने जो कहा है कि सरकार नोटकैम ऐप से शिक्षकों की तस्वीर खींचकर भेजने की व्यवस्था प्रणाली लागू है । वह बायोमैट्रिक से भी कहीं एडवांस है । बायोमैट्रिक में तो सिर्फ समय दर्ज होता है, इसमें फोटो भी दर्ज होता है, समय भी दर्ज होता है, जी0पी0एस0 मैपिंग से लोंगिट्यूड, लैटिट्यूड सब निकाल के कि वह विद्यालय में उपस्थित है कि नहीं हं । इसलिये उससे ज्यादा एडवांस सिस्टम से हमलोग शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहे हैं ।

टर्न-4/राहुल/20.02.2024

श्री अजीत शर्मा : महोदय, कब तक यह सिस्टम सब स्कूलों में लग जायेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो सूचना है उसके अनुसार यह काम कर रहे हैं, वैसे अगर आप किसी विद्यालय के बारे में बतायेंगे कि जहां नहीं है तो हम लोग लगवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-230 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र संख्या-239, वारिसलीगंज)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । नवादा जिलांतर्गत पकरीबरावां पुलिस अनुमंडल नवादा अनुमंडल का ही क्षेत्र है जहां पूर्व से के0एल0एस0 कॉलेज, नवादा एवं आर0एम0डब्ल्यू0 कॉलेज, नवादा अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है । अतः नवादा जिलांतर्गत पकरीबरावां

पुलिस अनुमंडल के धमौल बाजार में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना नहीं है ।

श्रीमती अरूणा देवी : महोदय, मुझे कहना है कि धमौल पकरीबरावां से 30 किलोमीटर दूर है और पुलिस अनुमंडल भी है वहां ओ0पी0 थाना भी है और वहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है इसलिए बच्चे-बच्चियों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है अगल-बगल भी कॉलेज नहीं है तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां डिग्री कॉलेज खोला जाय । माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या जो कह रही हैं सरकार उससे इनकार नहीं करती है । हो सकता है वे कह रही हैं तो वह बात सही हो लेकिन हमने सरकार की नीतिगत बात को बताया है कि अभी प्रथम चरण में राज्य के सभी अनुमंडलों में कम से कम हर अनुमंडल में एक डिग्री महाविद्यालय रहे इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और अब लगभग कुछ ही अनुमंडल बचे हुए हैं । पहले तो हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज हो जाये तो उसके बाद अगले चरण में एक अनुमंडल में दो खोलने की आवश्यकता है या फिर प्रखंड में खोलने की आवश्यकता है तब सरकार उस पर विचार करेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-231 (श्री सूर्यकान्त पासवान, क्षेत्र संख्या-147, बखरी (अ0जा0))</u>

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलांतर्गत नावकोठी प्रखंड में उर्दू मकतब नहीं है । शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वैसे सभी बसाव-क्षेत्र जहां 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कम से कम 40 हो, के एक कि0मी0 की सीमा के अंतर्गत की जायेगी तथा मध्य विद्यालयों की स्थापना किसी बसाव क्षेत्र के 3 कि0मी0 की सीमा के अंतर्गत की जायेगी । जैसे हमने पिछले उत्तर में भी बताया था और सबसे मूल बात यह है कि महोदय, अब कोई मकतब करके सरकार नहीं खोलती है बल्कि किसी भी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर कोई उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू जानने वाले बच्चे या इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं । 40 बच्चे तक

हो जाते हैं तो सरकार वहां एक उर्दू शिक्षक देती है और जहां तक नावकोठी प्रखंड की बात है तो इसमें एक अनुदानित मदरसा शमशूल उलूम भी है और इसके साथ ही, नावकोठी प्रखंड के 12 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कुल 21 उर्दू विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं । इसलिए सरकार उर्दूभाषी बच्चों या परिवारों के बच्चों की तालीम के लिए संवेदनशील है और उसके लिए मकतब की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर उर्दू पढ़ने या जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं तो आवश्यकतानुसार सरकार उर्दू शिक्षकों को वहां पदस्थापित करती है ।

श्री शकील अहमद खां : महोदय,...

अध्यक्ष : पहले उनको पूछने दीजिये न वे प्रश्नकर्ता हैं । प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, मेरा प्रश्न है कि नावकोठी प्रखंड में उर्दू मकतब खोलने का विचार सरकार रखती है या नहीं ?

अध्यक्ष : सरकार ने तो आपको बताया ही है ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, सरकार ने कहा प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों बहाली कर दी गयी है जबकि वह अल्पसंख्यक बहुल हमारा प्रखंड है और वहां एक भी उर्दू मकतब नहीं है । हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उर्दू मकतब हो, उर्दू विद्यालय हो इसकी मांग हम करते हैं ।

अध्यक्ष : सरकार ने तो कहा है कि अब उर्दू मकतब नहीं खोला जाता है बल्कि जिस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वहां उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षक की बहाली की जाती है । सरकार ने साफ-साफ यह कहा है ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, पूरे प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने कहा है । मेरा कहना है कि जो हमारी उर्दू बहुल पंचायत है वहां प्रखंडस्तरीय एक विद्यालय खोलने की कृपा की जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पता नहीं सूर्यकान्त जी उर्दू पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए प्रश्न किये हैं कि विद्यालय के लिए प्रश्न किये हैं । चाहे किसी मकतब में या मदरसा में तो उर्दू पढ़ने के लिए ही लोग जाते हैं और हमने आपको

बताया कि नावकोठी प्रखंड के 12 विद्यालयों में 21 उर्दू शिक्षक पदस्थापित हैं और सरकार अब अलग से मकतब और सच पूछते हैं तो अलग से सरकार कभी मकतब न खोली है और न खोलने का कोई प्रावधान है वर्ष 1971 में प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर के शिक्षकों के लिए सरकार ने शिक्षा संस्थानों का अधिग्रहण किया था उसी वक्त जो पहले मतकब के रूप में चल रहे थे आज भी मकतब कहे जाते हैं । वर्ष 1971 के बाद कोई मकतब नहीं खोला जाता है अब कहीं भी अगर उर्दू जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं तो सरकार वहां उर्दू शिक्षक देती है । आखिर उर्दू विद्यालय में भी उर्दू ही पढ़ने की मंशा होती है तो वह काम तो सरकार कर ही रही है ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय,...

अध्यक्ष : सूर्यकान्त जी, हो गया अब । मंत्री जी ने साफ-साफ जवाब दिया है अब क्या ? उसके बाद विषय कहां है । आगे बढ़िये ।

श्री शकील अहमद खां : सर, एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा जो आप उर्दू शिक्षक चाहते हैं या उर्दू विद्यालय चाहते हैं या उर्दू पढ़ने वाले लोगों के लिए क्या चाहते हैं ? महोदय, हम उर्दू विद्यालय चाहते हैं ।

अध्यक्ष : सूर्यकान्त जी बैठिये । बैठ जाइये । मेरी बात सुनिये । मंत्री जी ने इतना साफ-साफ कहा है कि उर्दू के नाम से कोई विद्यालय होना आवश्यक नहीं है किसी भी विद्यालय में अगर उर्दू पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं हैं तो उनकी व्यवस्था सरकार वहां उर्दू टीचर देकर करती है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ।

श्री शकील अहमद खां : मंत्री जी असल में हमारे यहां जो सरकारी स्कूल था वहां उर्दू...

अध्यक्ष : नावकोठी के बारे में बात कीजिये । नावकोठी के बारे में पूरक पूछिये और नहीं तो बाद में पूछ लीजिये ।

श्री शकील अहमद खां : इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछें ?

अध्यक्ष : नहीं, नावकोठी के बारे में पूछिये ।

श्री शकील अहमद खां : ऐसा तो कहीं...

अध्यक्ष : यहीं है । जिस बात के लिए प्रश्न किया गया है आप उससे संबंधित ही पूरक पूछ सकते हैं ।

श्री शकील अहमद खां : चूंकि जवाब इस तरह का था कि उससे सवाल बनता है...

अध्यक्ष : नहीं । दूसरी बात बाद में करेंगे । श्री कुमार शैलेन्द्र ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न मैंने किये थे एक प्रश्न का जवाब आया है...

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इसमें नियम की बात है...

अध्यक्ष : अब नहीं । अब आगे बढ़े गये हैं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : एक प्रश्न का जवाब अभी नहीं आया है इसलिए माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूं...

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । कुमार शैलेन्द्र जी का जवाब ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सबसे पहले तो एक नियमन दे दिया जाय कि एक सदस्य प्रश्नकाल में कितने सदस्यों के सवालों पर पूरक प्रश्न के लिए खड़े होंगे क्योंकि सत्यदेव राम जी हर प्रश्न में खड़े हो रहे हैं ।

अध्यक्ष : यह हम बंधन नहीं डाल सकते हैं, यह अधिकार उनका है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह तो पहले से नियमन है कि कोई माननीय सदस्य सवाल उठायेंगे तो वह पूरे सदन का सवाल हो जायेगा ।

अध्यक्ष : आप बैठिये । वह तो हम स्वयं कह रहे हैं आपकी बात । बताइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-232 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र सं0-152, बिहपुर)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सिंहपुर पश्चिम पंचायत में प्लस टू शिवधारी सुखदेव उच्च विद्यालय, मोजमा गनौल नारायणपुर अवस्थित है । इस विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या-614, कुल वर्ग कक्ष-12 एवं पदस्थापित शिक्षकों की संख्या-20 है । उक्त विद्यालय में 6 कमरे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं एवं मरम्मति योग्य भी नहीं हैं । फलतः 6

अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण का प्राक्कलन तैयार किया गया है जो लगभग 70,58,200 रुपये का है । उसे बी0एस0ई0आई0डी0सी0 मतलब बिहार शिक्षा आधारभूत संरचना निगम को दिया गया है आगे की कार्रवाई निविदा आदि की जा रही हैं । अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ।

टर्न-5/मुकुल/20.02.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने कह दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में इसको करवा दिया जायेगा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मेरा पहला प्रश्न है । यह बिल्कुल सही बात है कि 614 बच्चे हैं और जो 12 कमरा जवाब में बताया गया है वह 6 कमरा ही है । महोदय, 2 कमरा, बाउन्ड्री और बच्चियों के लिए शौचालय मैंने अपनी निधि से बनवाया है तो कुल मिलाकर 6 कमरा ही है । मंत्री महोदय के द्वारा कहा गया है कि वहां पर 12 कमरा है तो ये इसको थोड़ा दिखवा लें । यह हमारे क्षेत्र का मामला है, हमलोग दिन-रात क्षेत्र में भी जाते हैं । हमलोगों ने 2 कमरा अपनी खुद की निधि से बनवाया है ।

अध्यक्ष : आपने यह बिल्कुल ही अच्छा काम किया है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : जी महोदय । इसलिए यह जो 12 कमरों का जवाब आया है, मंत्री जी इसकी जांच करवा लें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न-233 (श्री सुधाकर सिंह, क्षेत्र संख्या-203, रामगढ़)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न-234 (श्री विश्व नाथ राम, क्षेत्र संख्या-202, राजपुर (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न-235 (श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, क्षेत्र संख्या-10, रक्सौल)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की

योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । राज्य सरकार महाविद्यालयों में सह-शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है । पूर्वी चम्पारण जिला के सभी अनुमण्डलों में डिग्री कॉलेज वर्तमान में संचालित हैं, जहां समान रूप से छात्र एवं छात्रा दोनों अध्ययन करते हैं ।

अतः पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल विधान सभा क्षेत्र में फिलहाल महिला डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

इसलिए माननीय सदस्य जो कह रहे थे कि अलग महिला कॉलेज करने के लिए तो महोदय, अब सरकार महिला कॉलेज करके नहीं खोलती है, सह-शिक्षा को प्रोत्साहित करती है ।

तारांकित प्रश्न-236 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र संख्या-213, काराकाट)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न-237 (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र संख्या-135, मोरवा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न-238 (श्री मोहम्मद अनजार नईमी, क्षेत्र संख्या-52, बहादुरगंज)

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित 339 श्रेणी के मदरसों की स्थलीय जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराई गयी थी । मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के समीक्षाक्रम में कतिपय त्रुटियां पाई गई हैं जिस कारण पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है और अभी जो महोदय, प्रतिवेदन आया है उस पर भी कुछ आपत्तियां आई थीं उन आपत्तियों का सत्यापन कराया जा रहा है । जैसे ही सत्यापन करके अंतिम प्रतिवेदन आयेगा, सरकार उसपर निर्णय लेगी ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, यह कब तक करवाया जायेगा ।

अध्यक्ष : अभी तो रिपोर्ट आयी है ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, इसमें एक-दो बार पहले भी जांच हो गयी थी, इससे पहले भी एक बार जांच हुई थी । फिर जुलाई, 2021 में भी जांच करके जमा कर दिया गया है, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है तो यह कब तक होगा यह मंत्री जी हमें बता दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस पर भी कोई आपत्ति दिखाई पड़ रही है तो उसकी भी समीक्षा हो रही है ताकि उसका भी निष्पादन हो जाय ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, यह काफी समय से मामला चल रहा है तो इसे जल्दी से जल्दी करवाया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी इसको जल्दी करवा देंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षकों से संबंधित मामला है, मदरसों की बार-बार जांच हुई है और इस जांच को उलझाते हैं डी0ई0ओ0 और बी0ई0ओ तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और जांच में बार-बार त्रुटि हो रही है तो क्या सरकार ऐसे डी0ई0ओ0 और बी0ई0ओ0 पर, कोई लिखता 3 कि0मी0 दूर है, कोई कहता है कि डेढ़ कि0मी0 दूर है । सच्चाई तो एक ही है तो क्या ऐसे विभाग के कुकर्मी कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : इसके लिए आप अलग से प्रश्न कीजिए, यह मामला तो भर्ती के लिए है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला डी0ई0ओ0 और बी0ई0ओ0 ने उलझाया है । रिपोर्ट किसने भेजी, रिपोर्ट तो इनके पदाधिकारियों ने ही भेजी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के पदाधिकारी तो रिपोर्ट बनायेंगे ही । आप बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मदरसा के शिक्षकों को उलझाया गया है, यह माइनोरिटी का मसला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, चाहे दूरी के बारे में हो या वहां जो आधारभूत संरचना या जो भी वहां संसाधन उपलब्ध हैं ।

उसके बारे में कोई भी पदाधिकारी चाहे डी0ई0ओ0, डी0पी0ओ0 या आर0डी0डी0 हो, किसी पदाधिकारी ने अगर कोई गलत रिपोर्ट दी है तो माननीय सदस्य उसके बारे में लिखकर दे दें । हम जांच कराकर जो गलत रिपोर्ट देंगे उस अधिकारी पर निश्चित कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न-239 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र संख्या-83, दरभंगा)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नेट पर उपलब्ध नहीं है, अभी भी मैंने चेक किया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 तक कुल 36 जिलों यानी अरवल और रोहतास को छोड़कर के 790 विद्यालयों में 2466 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं और गड़बड़ियों का प्रकार निम्नलिखित है कि 218 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के लिए जो संबंधित विद्यालय शिक्षा समितियों को जो राशि दी गई थी, उसे उन्होंने फिर वापस कर दिया बिना उपयोग किये हुए, ऐसे 218 हैं । शेष जो 2248 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के विरुद्ध 1477 के निर्माण कार्य किये जाने वाले संबंधित विद्यालय शिक्षा समितियों के विरुद्ध अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और सर्टिफिकेट केस भी किया गया है । इसके अलावा 295 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण किये जाने वाले संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की मृत्यु अथवा अन्य कारणों से निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जा चुका है, उसकी विभाग समीक्षा करके जहां निर्माण कार्य अधूरा है, उसको हम पूरा करेंगे । शेष 476 अतिरिक्त वर्ग कक्षों जिसका निर्माण कार्य संबंधित शिक्षा समितियों द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है, ऐसे जो बच गये हैं इनके संबंध में भी जांच अंतिम स्थिति में है और उसकी रिपोर्ट जैसे ही आयेगी इसके लिए जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वह सरकार करेगी, पैसे वापस लेने के लिए और जिन्होंने पैसा लेकर काम नहीं किया है । उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान की राशि...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए, माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ जवाब दे दिया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही प्रश्न पूछ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैंने विवरण में सुना है कि 1477, मतलब 7 साल से यह काम चल रहा है और इसमें लोकायुक्त ने संज्ञान लिया है कि अभी तक यह जो गबन की राशि है उसकी वसूली में कोताही क्यों बरती जा रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से साफ-साफ पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो 1477 बताया है उसमें अभी तक कितनी राशि सरकार की अपव्यय हुई या गबन हो गयी और उसमें कितना पैसा अभी तक वसूला गया । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें जांच चल रही है, इस मामला का 7 साल हो गया है, इसमें कितनी राशि वसूली की गई है, टोटल कितनी राशि की इसमें गड़बड़ी हुई यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । चूंकि लोकायुक्त महोदय ने भी कहा है कि वसूली में कोताही क्यों बरती जा रही है और राशि क्यों नहीं वसूली जा रही है । इसलिए मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने कहा है कि 218 विद्यालयों को जो राशि दी गई थी उनसे राशि वापस ले ली गई है और सब विद्यालयों को लगभग 90 लाख रुपया दिया गया था तो उस हिसाब से वापस हुई है । हमने जो बताया कि 2248 में जो राशि नहीं लौटाई उनके विरुद्ध जो एफ0आई0आर0 दर्ज करना होता है, सर्टिफिकेट केस करके पैसा वापस लेने की कार्रवाई वह चल रही है । कुछ 295 लोग ऐसे हैं जिनमें किसी की मृत्यु हो गई है जिनसे एग्रीमेंट हुआ था, उनके वारिस से पैसा वसूलने से लेकर के और जो काम अधूरा है उसको पूरा करने की कार्रवाई चल रही है । महोदय, हमने कहा 476 इसके अलावा जो बचते हैं उनकी पूर्णता से जांच नहीं हुई थी, हमलोग फिर से जांच करके उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 476 की जांच चल रही है तो कबतक यह जांच पूरी हो जाएगी क्योंकि यह 7-8 साल पुराना मामला है । लोकराशि का मामला है तो कबतक यह 476 की जांच पूरी हो जाएगी, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम निदेश देंगे कि तीन महीने के अंदर सारी कार्रवाई पूरी की जाय ।

अध्यक्ष : श्रीमती स्वर्णा सिंह, जवाब आपका उसमें लिखा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-240 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, राज्य के निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना संचालित की जा रही है । वर्तमान में इस योजनान्तर्गत राज्य के 06 जिलों (पटना, पूर्णिया, गया, भागलपुर, रोहतास एवं पश्चिम चम्पारण) में वृद्धाश्रम संचालित हैं ।

दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल अन्तर्गत बिरौल प्रखंड में वृद्धाश्रम संचालन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह बताना चाहती हूं मंत्री जी से कि पूरा दरभंगा जिला में एक भी वृद्धाश्रम नहीं है और आसपास के एरिया में भी नहीं है तो जो बेसहारा वृद्ध हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनको बच्चे ने निकाल दिया है उनके लिए बहुत सहारा हो जाय अगर एक वृद्धाश्रम भी दरभंगा जिला में खोला जाय । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-241 (श्री ललन कुमार, क्षेत्र संख्या-154, पीरपैंती (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) स्वीकारात्मक है । जिला मुख्यालय भागलपुर से मिर्जाचौकी तक का मार्ग निर्माणाधीन होने के कारण यह मार्ग

अधिसूचित नहीं है । अधिसूचित नहीं होने के कारण सरकारी बसों का परिचालन नहीं होता है ।

(2) उपरोक्त कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

(3) जिला मुख्यालय भागलपुर से मिर्जाचौकी तक का निर्माणाधीन मार्ग पूर्ण होने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर की अनुशंसा के आलोक में विषयांकित मार्ग को अधिसूचित किये जाने की कार्रवाई की जाएगी । तत्पश्चात् सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा ।

अध्यक्ष : श्री ललन कुमार, जवाब संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न था कि भागलपुर से घोघा, कहलागांव, पीरपैंती होते हुए मिर्जाचौकी झारखंड बॉर्डर तक बस चलाने के लिए लेकिन प्रश्नकाल के प्रथम दिन ही इसका सकारात्मक जवाब मिल गया था, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जल्द ही वहां रोड का निर्माण हो जाएगा, जल्द बस चलाएंगे । आज फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मंत्री जी बताएंगे, शायद मिस्टेक हो गया है ।

अध्यक्ष : इसका जवाब तो हो गया था न ।

श्री ललन कुमार : हां हो गया था, शायद आज फिर से आ गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, मैं दिखवाता हूं कैसे यह गलती हो गई है ।

श्री ललन कुमार : हम सरकार का धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : उत्तर तो आप इसके पहले सुन चुके हैं, मुझे याद है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमें भी यह जानकारी है कि वह एक ही प्रश्न दो बार दो तरीके से किए थे और लगभग वही उत्तर है कि अधिसूचित नहीं है इसमें हमने कहा है ।

अध्यक्ष : वह ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : और सड़क की मरम्मती होकर अच्छा आवागमन सुगम हो जाएगा तो वह अधिसूचित करके बस चलायी जायेगी ।

अध्यक्ष : श्री प्रहलाद यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या–242 (श्री प्रहलाद यादव, क्षेत्र संख्या–167, सूर्यगढ़ा)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 एवं 2 स्वीकारात्मक है । खंड–3 पंचायत टौरलपुर में मध्य विद्यालय टौरलपुर को पूर्व से ही 10+2 विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है जहां अध्यापन कार्य चल रहा है । इस उत्क्रमित 10+2 विद्यालय से मध्य विद्यालय, निस्ता की दूरी मात्र–3 कि0मी0 है । सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रत्येक पंचायत में फिलहाल एक ही माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जानी है । इसीलिए अभी निस्ता में दूसरा विद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विद्यालय वहां खोला गया है वह खोला गया है, उसमें जमीन नहीं है, जो शर्त है विद्यालय को 10+2 करने की शर्त के अनुसार वह विद्यालय नहीं है । शर्त के अनुसार वहां हर चीज फुलफिल कर रहा है । जमीन भी है, विद्यार्थी भी है और बिल्डिंग भी है, सारी चीज है और जो विद्यालय जहां पर खोला गया है वह तीन कि0मी0 में, पांच कि0मी0 से ज्यादा है और सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो है जो निस्ता गांव जहां का हम प्रपोजल माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि 1600 विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं तो यहां पर बहुत जरूरी है और जहां तक माननीय मंत्री जी एक बात बोले कि एक विद्यालय प्रावधान है एक पंचायत में एक ही खोला जाएगा, आपको माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र सूर्यगढ़ा में एक कुंदर पंचायत है एक पहले से हाईस्कूल चल रहा है, एक दूसरा हाईस्कूल बना है । उसी तरह से कईएक मेरे जिला में पंचायत है जो दो–दो एक पहले से बना हुआ है, एक बाद से चल रहा है तो उसमें कौन नियम है । मैं चाहता हूं कि यहां विद्यालय होना बहुत जरूरी है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अभी तो हमने सरकार की नीति की बात कही है, माननीय सदस्य का कहना है कि उस पंचायत में जिस विद्यालय को उत्क्रमित किया गया +2 विद्यालय में उससे ज्यादा उपयुक्त

विद्यालय दूसरा था, वहां पर जो आवश्यक प्रावधान होने चाहिए थे पहली जगह पर जहां टौरलपुर में बनाया गया है उससे ज्यादा उपयुक्त यह जो कहते हैं निस्ता वाले वहां पर हैं तो अभी तो जो सूचना थी वह हमने दिया है लेकिन जो कह रहे हैं वह पूरी डीटेल लिखकर दे दें हम जरूर इसकी जांच कराकर उचित निदान कराने का प्रयास करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या-243 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र संख्या-116, तरैया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-244 (श्री विनय कुमार चौधरी, क्षेत्र संख्या-80, बेनीपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक । श्री गंगेश कुमार राय (रजिस्ट्रेशन आई0डी0-4894494) का शिक्षा ऋण के दो किस्तों का भुगतान किया जा चुका है । छात्र द्वारा तीसरे किस्त हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं किया गया है । आवेदन करने के पश्चात् नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जायेगी । शेष छात्र/छात्राओं का भी लंबित भुगतान इस वित्तीय वर्ष में कर दिया जायेगा ।

(4) उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, जवाब आ चुका है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए । प्रहलाद जी, आप बैठ जाइये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, जवाब में आया है कि द्वितीय किस्त मिल गया है छात्र को, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इससे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पता नहीं प्रहलाद जी जब-जब खड़े होते हैं जब-तब ललित जी कहते हैं कि इधर थे, इधर थे । मजबूरी की जगह में और इच्छा वाली जगह में फर्क तो होता है न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : सर, जवाब आ गया है, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका लाभ छात्र बहुत उठा रहे हैं, सवाल उठता है कि जो प्रश्नगत मेरा प्रश्न है इसमें कहा गया है कि सरकार का जवाब है कि द्वितीय किस्त मिल गया है लेकिन सच्चाई यह है कि द्वितीय किस्त भी नहीं मिला है । मेरा सरकार से सिर्फ आग्रह है कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जिन सबका प्रथम किस्त मिल गया है उनलोगों को द्वितीय और तृतीय किस्त जो आवश्यक है ताकि वहां पर छात्रों को पढ़ने में असुविधा नहीं हो समय पर मिल जाय, यही मेरा आग्रह शिक्षा मंत्री जी से है, आपके द्वारा ।

अध्यक्ष : आग्रह है केवल । एक मिनट मंत्री जी । माननीय सदस्यगण, एक बात का ध्यान रखिए, आप आग्रह कीजिएगा तो सरकार के द्वारा जवाब देना बाध्यता नहीं है, आप अगर पूछिएगा तब सरकार जवाब देती है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, जवाब से ज्यादा काम होना महत्वपूर्ण है न ।

अध्यक्ष : केवल आपको नहीं कह रहा हूं, सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूं, सबलोग सुझाव दे देते हैं, आग्रह करते हैं तो सरकार जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है । अपने प्रश्नों के बारे में और कोई पूरक पूछना पड़ेगा तब सरकार बोलती है । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार तो स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड में जो हम छात्रों को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए राशि देते हैं उसमें तो सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, उन्होंने दो बात कही है, एक तो हमने उत्तर में ही कहा है कि तीसरे किस्त का भी भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब फरवरी खत्म हो रहा है मार्च तक में हमलोग करा देंगे लेकिन अगर उन्होंने

कहा है कि खासकर इस छात्र के बारे में, गंगेश राय के बारे में बाकी किन्हीं का दूसरा किस्त बाकी हो वह अभी हम नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर गंगेश राय को दूसरे किस्त की राशि नहीं दी गई है तो आप लिखकर दीजिए, जरूर गलत जवाब देनेवाले की हम जिम्मेदारी फिक्स करके कार्रवाई करेंगे । कोई अधिकारी गलत जवाब सदन में देकर के सदस्य और सदन को कैसे गुमराह कर सकता है ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 फरवरी 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री अजय कुमार, श्री महा नंद सिंह, श्री राम रतन सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री मो0 इजहार असफी और दूसरा श्री अजीत शर्मा । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों की अनुदानों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

टर्न–7/अंजली/20.02.2024

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मामला सब गंभीर होता है । माननीय सदस्य कोई विषय अगंभीर होकर नहीं पूछते हैं, सब गंभीर विषय होता है ।

(व्यवधान)

आपलोग सत्यदेव जी को बोलने नहीं दे रहे हैं । बोलने दीजिए उनको, क्या बोलना चाहते हैं ? बैठिये । सत्यदेव जी, क्या कह रहे हैं आप ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पढ़ के सुना देते हैं ।

अध्यक्ष : देखिये क्या है, आप सुन लीजिए मेरी बात सत्यदेव जी । थोड़ा इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वह पढ़ दीजिए, बहुत लंबा है । बाकी और भी काम आपके यहां है । बोलिये ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के अलोकतांत्रिक फैसले से शिक्षक समुदाय में चरम आक्रोश है । सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रहे नियोजित शिक्षकों को परीक्षाओं के मकड़जाल में उलझा दिया गया है । नियमावली के अव्यावहारिक पहलुओं यथा तीन जिले के विकल्प को विलोपित करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण एवं अन्य जरूरी संशोधनों के सवाल पर अपनी आवाज उठाने के लिए उनके ऊपर लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है । महोदय, स्कूलों की समय–सीमा 9 से 5 बजे तक का फरमान पूरी तरह अमानवीय और अव्यावहारिक है । महिलाएं, दिव्यांग शिक्षकों को इसके कारण भारी परेशानी हो रही है । उनकी कई छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है । महागठबंधन सरकार में शिक्षकों की स्थाई बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन दूसरी ओर सरकार ने विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए निजी कंपनियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त और संचालन का अधिकार दे दिया है । यह शिक्षकों के विनाश का कारण बनेगा । विश्वविद्यालय शिक्षकों तक के लिए फरमान लागू कर दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते हैं, महोदय, यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है । पहले से कार्यरत संघ या संगठन की मान्यता समाप्त कर पत्र जारी कर दिया गया है । इस अलोकतांत्रिक फैसले का विरोध करने पर

उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं । महोदय, हमारी समझ है कि शिक्षा की व्यवस्थागत कमियों पर ध्यान देकर और उससे संबद्ध सभी तबकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करके ही एक स्वस्थ, लोकतांत्रिक, शैक्षणिक माहौल का निर्माण किया जा सकता है । अन्यथा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल और दयनीय हो जाएगा ।

अत: बिहार के लाखों शिक्षकों के, लाखों शिक्षकों की वाजिब मांगों और शिक्षा में जनपक्षीय सुधार के अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करके बहस की मांग करते हैं, महोदय । इसमें शिक्षा का सवाल है । शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है । अगर शिक्षकों को ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी । अपना कार्यस्थगन पढ़िये ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए, बैठ जाइए । सुन लिया जाय । बोलिये अजीत जी ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, नियोजित शिक्षकों की शैक्षणिकता परीक्षा की घोषणा से उत्पन्न भीषण स्थिति पर चर्चा हो । उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2006 से नियोजित शिक्षकों की शैक्षणिकता परीक्षा आयोजित की जाती है, इससे नियोजित शिक्षक उद्वेलित हैं और सड़कों पर उतर गए हैं । सरकार की दंडात्मक नीति के कारण आंदोलित शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है । प्रशासन निर्मम हो गया है, शिक्षा व्यवस्था पूर्णत: चरमरा गई है ।

अत: आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए नियोजित शिक्षकों की सक्षमता पर प्रश्न की घोषणा से उत्पन्न भीषण स्थिति पर चर्चा कराई जाय ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित समस्त बिहार में मदरसा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त 75 प्रतिशत मदरसों में शिक्षक का पद रिक्त हो जाने के कारण पठन-पाठन का कार्य ठप है ।

मैं सरकार से 1128 कोटि के मदरसों में रिक्त शिक्षकों के पद पर शीघ्र बहाली की माँग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 1990, 1997, 2010, 2012 तक कुछ जिलों में सेवानिवृत्त दफादार चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति कर ली गई है । लेकिन पूरे बिहार में 50 प्रतिशत के करीब चौकीदारों के आश्रित इस लाभ से वंचित हैं ।

करीब 5000 (पाँच हजार) आश्रितों को अविलम्ब नियुक्त करे सरकार ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखंड-डोभी के ग्राम पंचायत-बजौरा के ग्राम-जोलहबिगहा नवोदय विद्यालय के समीप फल्गु नदी में पुल नहीं रहने से ग्रामीणों को बाराट्टी, मोहनपुर प्रखंड जाने हेतु दस किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ।

अत: उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने की माँग करती हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के रंगरा के गुण्डों द्वारा एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर दी गई । एस0पी0 व थानेदार की इस घटना में घोर लापरवाही रही है । गुण्डों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने साथ ही एस0पी0 व थानेदार पर भी कार्रवाई करने की माँग करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भारत सरकार देवतुल्य किसान भाईयों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है, उसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा अपने कोष से प्रदेश के सभी देवतुल्य किसान भाईयों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में देने की माँग करता हूँ ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा-1 प्रखंड में 24 पंचायत एवं 21 वार्ड हैं । जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है ।

अत: मैं इसे विभाजित कर परसौनी फार्म प्रखंड कार्यालय स्थापित करने हेतु सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के रंगरा में अतिपिछड़ा समाज की एक महिला के साथ दबंग ताकतों के जरिए कथित बलात्कार और हत्या मामले में जिसके

डी0एम0 एस0पी0 को जिम्मेवार ठहराते हुए कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी की माँग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रधानमंत्री वित्त पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत रसोईया को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय का भुगतान करने एवं तत्काल प्रतिमाह 10000 रुपये मानदेय देने हेतु मैं सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 के बाद सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को अनुकम्पा पर बहाली करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC नं0-10092/2005, दिनांक-16.01.2006 के आलोक में निर्गत किया गया है । बक्सर सहित विभिन्न जिलों में शेष बचे आश्रितों को शीघ्र बहाली करने की माँग करता हूँ ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड में मात्र तीन ही पावर सब-स्टेशन हैं । जिससे विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है ।

अतः मैं सरकार से कोचाधामन प्रखंड में चौथा पावर सब स्टेशन डेरामारी में स्थापित करने की माँग करता हूँ ।

श्रीमती निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के बिचकोरी से तीनडोभा पथ में तीनडोभा नदी पर पुल निर्माण होने से अनेकों गाँव के साथ-साथ दो संपर्क पथ आपस में जुड़ेगा ।

अतः सरकार से उक्त नदी पर पुल निर्माण की माँग करती हूँ ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड-बाराचट्टी में कस्तूरबा विद्यालय में छात्रावास एवं प्रखंड-मोहनपुर के ग्राम पंचायत केवला के ग्राम जेठुआडाहा में लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है जिसके निर्माण में संवेदक द्वारा गुणवत्ता में अनियमितता बरती गयी है, जिसकी जाँच हेतु सदन से माँग करती हूँ ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज नगर परिषद् वार्ड नं0-2 कजलामनी में मनोज मास्टर के घर से जन्नत कॉलोनी, मंदिर होते हुए बड़ा नाला

तक नाला नहीं रहने के कारण आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

मैं उक्त स्थान पर नाला निर्माण कराने की माँग सरकार से करता हूँ ।

टर्न-8/आजाद/20.02.2024

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत रक्सौल प्रखण्ड में प्रस्तावित प्लस 2 अनुसूचित जाति, जनजाति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की स्थापना नहीं होने से स्थानीय छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । मैं उक्त आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास को अतिशीघ्र स्थापित करवाने की मांग करता हूँ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी नगर परिषद् क्षेत्र में अवस्थित सैकड़ों वर्ष पुराना दुलरूआ धाम तालाब जर्जर स्थिति में है ।

अतः मैं उक्त तालाब का चहारदिवारी, सीढ़ी, पार्क एवं सौंदर्यीकरण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला के झाझा प्रखंड अंतर्गत कॉजवे पुल जो कि भारी वाहनों के आवागमन के कारण काफी कमजोर हो चुका है, उसकी महत्ता को देखते हुए कॉजवे पुल का चौड़ीकरण अथवा नवनिर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरूआ प्रखंड पकरी पंचायत के ग्राम-तारापुर में लगभग 5 एकड़ में विस्तृत दुबकुल पोखर जीर्णशीर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है, शीघ्र जीर्णोद्धार का कार्य कराने की मांग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड अर्थात बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों को आऊटसोर्सिंग एजेंसियों के बजाय विभिन्न विभागों में संविदा पर पदस्थापित करने की मांग करता हूँ । बेल्ट्रॉन के पत्रांक-7541, दिनांक 1.11.2018 के अनुसार इससे राज्य सरकार को 50 करोड़ रू0 की वार्षिक बचत होगी ।

श्री कृष्णनन्दन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी तुरकौलिया गोविंदगंज एस0एच0-54 पथ में बलुआ धनौती नदी पुल से बालगंगा मुशहर टोली तक सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण निर्माण हेतु अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंध) से पत्रांक-8/22 के द्वारा स्वीकृति की मांग के अुनसार स्वीकृत नहीं है, जिसे स्वीकृत कर निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि झोपड़ी से संसद तक गरीबों के लिए मशाल जलाने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं वंचितों के नेता, राष्ट्रीय राजनीति के सितारे पद्म विभूषण, पूर्व केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान को मरणोपरांत भारतरत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करें ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अन्तर्गत सिंधिया प्रखण्ड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है । सिंधिया प्रखण्ड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के लिए एक नया भवन बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, लौरिया एक ऐतिहासिक स्थल के साथ-साथ औद्योगिक नगरी भी है । यहां की यातायात व्यवस्था को सुगत बनाने के लिए बाईपास रिंग मार्ग की अति आवश्यकता है । सड़क उपलब्ध है । मैं सदन के माध्यम से पक्कीकरण करवाने की मांग करता हूँ ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों की भांति सम्पूर्ण बिहार के छात्र-छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करने की एवं दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों को केवल 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, ''अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया उम्र-55 वर्ष, ग्राम-तकिया याकूब, जिला-गोपालगंज की हत्या दिनांक 12.02.2024 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गयी ।

अतः मैं सदन के माध्यम से हत्याकाण्ड में संलिप्त सभी अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सुदूर जिलों के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की वजह से देहात के गांवों में उन्हें कोई अपना मकान किराया पर भी देना नहीं चाहता है ।

अत: मैं मांग करता हूं कि महिला एवं विकलांग शिक्षकों को गृह जिला में सुविधानुसार स्थानांतरित किया जाए ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के खरहट पंचायत के गिदवास बाजार में पूर्व से निर्मित बड़े पानी टंकी से जलापूर्ति विगत 5 वर्षों से नहीं हो रही है । जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है ।

अत: जलापूर्ति प्रारंभ करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखण्ड के खैरा, चकला मौलानगर, पूर्वी मुरादपुर, मुरादपुर पंचायतों के गांव में नाला नहीं रहने के कारण जलजमाव की स्थिति बनी रहती है । उक्त पंचायत के गांवों में नाला सह सड़क का निर्माण कराने हेतु सूचना देता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड में अनियमितता तथा गुणवत्ताविहीन कार्य हो रहा है । इसकी जांच निगरानी से कराने की मांग करता हूँ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के अंतर्गत बखरी बाजार में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

अत: अतिशीघ्र नाला निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज कुर्सेला एस0एच0 60 रामपुर से पिठौरा, बेलसंडी होते हुए सुपौल सीमा तक जाने वाली सड़क जिसकी लंबाई लगभग 26 कि0मी0 है, को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत कर पुनर्निर्माण करवाने की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : बेतिया में राजनीतिक संरक्षण में पहले संवेदक कृष्णा पटेल पर और फिर 18 फरवरी को नागेन्द्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला हुआ । ठेकेदारी पट्टा पर कब्जा के लिए वहां अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है । इसे जांच कराकर दोषी पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के लालगंज निवासी व्यवसायी मुकेश कुमार साहू को दिनांक 27.01.2024 को अपराधियों ने दिन-दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी, जिसका कांड संख्या- 21/24 है ।

अतः अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा तथा सुरक्षा की मांग करता हूँ ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के बरियापुर प्रखण्ड कार्यालय के लिए अधिकृत जमीन का मुआवजा किसानों को 2013 की दर से दे रही है । मैं सदन के माध्यम से सरकार से वर्तमान दर से मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : कुंदन जी, आपकी क्या सूचना है, बोलिए ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बीते देर कल शाम में कुछ अपराधियों ने काफी गोली-बारी की, जिसमें मेरे घर के सामने भी गोली-बारी करते हुए गये हैं । बीते कुछ दिनों में काफी अपराधिक घटनायें बढ़ी हैं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसका उच्चस्तरीय जॉच कराकर के अपराधियों को अविलम्ब पकड़ने का काम एवं उसको सजा देने का काम किया जाय ।

अध्यक्ष : सरकार देखवायेगी ।

माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनायें ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनायें ली जायेंगी ।

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री महबूब आलम, श्री अरूण सिंह एवं श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (समाज कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, ''सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बुनियादी मानवीय अधिकार है, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा में मान्यता दी गई है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है । उपरोक्त संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार सरकार द्वारा 60 वर्ष तथा 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को प्रतिमाह क्रमशः 400 एवं 500 रूप्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है । 80 के दशक में पेंशन की शुरूआत 50 रूप्ये से हुई थी । तब से अब तक मुद्रास्फीति की दर 50 गुणा बढ़ी है तथा खाद्यान्न एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत सौ गुणा बढ़ी है ।

अतएव लोकहित में मुद्रास्फीति एवं महंगाई के मद्देनजर वृद्धजनों को न्यूनतम 3000/- रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं । ''

टर्न-9/शंभु/20.02.24

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में कुल 1 करोड़ 1 लाख पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है जिसमें से 76 लाख 83 हजार वृद्ध पेंशनधारी, 13 लाख 35 हजार विधवा पेंशनधारी तथा 9 लाख 82 हजार दिव्यांग पेंशनधारी हैं । राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 4951 करोड़ रूपये का व्यय किया जाता है जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1436 करोड़ 77 लाख रूपये ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है । शेष लगभग 3515 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा है । वर्तमान में इसमें वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ये मंत्री महोदय आंकड़ा गिना रहे थे 1 करोड़ 76 लाख, 13 लाख 9 लाख- महोदय, आज की स्थिति में 400 रूपये सुबह शाम दो कप चाय नहीं मिलती है उसके लिए 600 रूपया चाहिए, 10 रूपये कप चाय मिलती है । महोदय, पेंशन की आवश्यकता श्रमिक वर्गों को ज्यादा होती है, गरीबों में जो श्रमिक वर्ग है । जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की और मेहतन से प्रदेश और देश का निर्माण किया और उन्हें पोषाहार कभी नहीं मिला जिसकी वजह से 60 वर्ष से उपर होने के हालात में उनकी कमर टूट जाती है । वे दस मकान में दौड़कर, पैदल चलकर भीख नहीं मांग सकते हैं । ऐसी हालत में ये 400 रूपया कुछ नहीं है इसलिए वे अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य हैं । इसलिए मैं मांग करता हूँ कि पैसे का इंतजाम करना होगा आपको, आपकी डबल इंजन की सरकार है । आपने किस बात के लिए समझौता किया है, कहां गया आपका विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज- इसलिए ये अभिशप्त जीने के लिए श्रमिक वर्ग का उपहास मत उड़ाइये । महोदय, आपको मासिक 3 हजार रूपया पेंशन देना होगा । इधर उधर की बात न करें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय महबूब साहब इधर उधर की बात बहुत करते रहते हैं । महोदय, श्रमिकों को अन्य सुविधा भी दी जाती है और जो वृद्धजन हैं उनको भी अन्य सुविधा सरकार के द्वारा समय-समय पर दिया जाता है । इसलिए सरकार के पास इसमें अभी बढ़ोतरी का कोई विचार नहीं है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसको ऐसे टाला नहीं जा सकता, इसके उपाय करने होंगे । दूसरे-दूसरे राज्यों में केरल जैसे राज्य में 21 सौ रूपया पेंशन होता है । मनी इन्फलेशन का क्या सरकार हिसाब देगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, अपनी सूचना को पढ़ें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

हो गया, सरकार ने जवाब दे दिया है ।

श्री विजय कुमार खेमका, श्री विनय बिहारी एवं श्री नीतीश मिश्रा, सा0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से समन्वय पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश में लगभग 9600 आपदा मित्र/सखी प्रशिक्षण प्राप्त कर निरंतर सेवा कार्य दे रहे हैं । सरकार द्वारा इनकी कार्य की पूर्ण उपयोगिता स्पष्ट न करने की स्थिति में हजारों युवक-युवती पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं । अतः आपदा मित्रों/सखियों की उपयोगिता स्पष्ट कर कार्य का निश्चित मानदेय तय करने के साथ इनकी स्थायी नियुक्ति के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, समय चाहिए, 23 तारीख को जवाब दिया जायेगा ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने विषय रखा है सरकार ने सुना है । अब निर्णय सरकार करेगी न, ऐसे थोड़े ही होगा । अब शून्यकाल की शेष सूचनाएं ली जायेगी ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों के सेंटर प्वाइंट पूर्णिया में एम्स की शाखा खुलने से आसपास के 15 जिले के लोग इलाज हेतु 400 कि0मी0 दूर पटना जाने की मजबूरी से निजात दिलाने के लिए पूर्णियां में एम्स खोलने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने अपनी बात रख दी न, हो गया बैठिए ।

श्री अमरजीत कुशवहा,स0वि0स0, मो0 कामरान,स0वि0स0, सत्यदेव जी कहां गये? बोलिये न, आपका शून्यकाल है ।

(श्री अमरजीत कुशवाहा, मो0 कामरान एवं श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0 द्वारा शून्यकाल की सूचना नहीं पढ़ी गयी ।)

श्री जिवेश कुमार : महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवारा प्रखंड के सनहपुर ग्राम निवासी श्री मनोज भगत के 11 वर्षीय पुत्र रंधीर कुमार जो 26 जून, 2023 की शाम से अभी तक लापता है । श्री मनोज भगत जी के द्वारा सिंहवारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी । जिसका प्राथमिकी संख्या-126/23 है । सिंहवारा थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर रंधीर कुमार को सकुशल बरामदगी सरकार कराये । अध्यक्ष महोदय, गरीब का बच्चा है पूरे परिवार की रो-रोकर हालत बुरी हो गयी है । इसपर सरकार संज्ञान ले ।

अध्यक्ष : सब संज्ञान सरकार लेते रहती है ।

श्री सुदामा प्रसाद,स0वि0स0 ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र में खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में देश विदेश में मकाम बनाया है । मैं सदन के माध्यम से सरकार से खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों के हित में तत्काल प्रभाव से प्रत्येक पंचायत में स्टेडियम बनाने के लिए जगह चिन्हित कर उसका घेराबन्दी कराकर डे-नाइट मैच एवं प्रैक्टिस के लिए सोलर लाइट की व्यवस्था कराने के साथ-साथ उसी परिसर में जिम वाईफाई युक्त लाइब्रेरी एवं स्टडी हॉल बनाने की मांग करती हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से वॉकआउट कर गये)

अध्यक्ष : रश्मि जी, आपकी सूचना में 72 शब्द है और यह वास्तव में अमान्य हो गया है, लेकिन मैंने केवल आपको पढ़ने की सुविधा दी है । आगे से सभी माननीय सदस्य ध्यान रखें कि जो शून्यकाल की सूचना है वह 50 शब्द तक होना चाहिए । यह ध्यान रखिये, बैठिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के बिहपुर प्रखंड अन्तर्गत हरियो पंचायत के कहारपुर गांव अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र कोशी नदी के कटाव के कारण नदी में पांच वर्ष पूर्व विलीन हो गया है । अतः सरकार से कहारपुर गांव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत त्रिमुहान से एकचारी सनोखर होते हुए दिग्घी झारखण्ड सीमा तक पथ निर्माण विभाग के अधीन सड़क की स्थिति जर्जर है । अतः उक्त जर्जर सड़क के घनी आबादी वाले हिस्से में पी0सी0सी0 सहित सड़क निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : शून्यकाल समाप्त हुआ । अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/पुलकित/20.02.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)	-	08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी॰पी॰आई॰(एम॰)	-	02 मिनट
सी॰पी॰आई॰	-	02 मिनट
ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰	-	01 मिनट
कुल	-	180 मिनट

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 4398,51,79,000/- (चार हजार तीन सौ अठानवे करोड़ इक्यावन लाख उनासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

महोदय, यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं । जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार का प्रस्ताव प्रथम है ।

अत: माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री राजेश कुमार : मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांग 10/- रुपये से घटाई जाए ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना पक्ष रखें । आपका समय 14 मिनट है ।

श्री राजेश कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव रखता हूँ ।

महोदय, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 4398,51,79,000/- (चार हजार तीन सौ अठानवे करोड़ इक्यावन लाख उनासी हजार) रुपये का प्रावधान किया है, जिससे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की विभिन्न योजनाओं को पूरा किया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इस विभाग के लिए 4398,75,00,000/- (चार हजार तीन सौ अठानवे करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था । महोदय, पिछले बजट भाषण में माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था, उल्लेख किया था कि 64.22 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर जिला अंतर्गत

कर्मनाशा नदी पर निष्कृत पम्प नहर योजना का कार्य कराया जायेगा और इसे अगस्त, 2023 तक पूर्ण करा लिया जाएगा । इस बजट में भी इस योजना के लिए 64.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, यह कटौती प्रस्ताव मैं इसलिए लाया हूँ कि सरकार जो पिछले सदन में अपना वादा पूरा नहीं कर पाई है इसलिए आगे की राशि इसमें देने में, यह जनहित में उपयोग नहीं हुई । इसी तरह से हमारे क्षेत्र में उत्तर कोयल परियोजना एवं बटाने नहर परियोजना लंबित है । औरंगाबाद के बटाने नहर परियोजना का 1300 करोड़ रुपये का डी0पी0आर0 सरकार के पास आकर पड़ा हुआ है और मुझे समझ में नहीं आता कि वह 1300 करोड़ रुपये का जो डी0पी0आर0 तैयार है वह सरकार के स्तर पर ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ है । एक तरफ सरकार ताला-चाबी मांगती है कि हम किसान हित में काम करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भी है । एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़ है हमलोग तो विशुद्ध रूप से सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और सरकार बार-बार अपनी मांग कई योजनाओं के जरिए कर रही है । ठीक है, काम करने के लिए सरकार को पैसा देने की आवश्यकता है, उसका हमलोग विरोध नहीं करते लेकिन जो सदन में और जो सरकार की पॉलिसी है, उस सरकार की पॉलिसी में जब आप यह योजना ला रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि आखिर यह इस तरह की परियोजनाएं अब तक क्यों लंबित हैं ।

आगे के क्रम में माननीय मंत्री महोदय को बतलाने के लिए मैं आग्रह करता हूं कि इस वक्त जो पूरी योजनाएं लंबित हैं क्या यह सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में जिसकी यह मांग रखी गयी है उस वित्तीय वर्ष में क्या पूरा कराने का वचन देगी ?

महोदय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 2022 के प्रतिवेदन संख्या- 3 में उन्होंने उल्लेख किया है कि पूर्वी नहर गण्डक प्रणाली में

कार्यपालक अभियंता, वाल्मिकीनगर द्वारा संवेदक को 1.58 करोड़ रुपये का दोहरा भुगतान किया गया है लेकिन उसकी वसूली नहीं की गयी । विभाग के अनुचित निर्णयों के कारण परियोजनाओं में चार वर्ष, नौ वर्ष का विलम्ब हुआ है । क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि आखिर किन-किन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा यह 1.58 करोड़ रुपये के अधिक पेमेंट की हम भुगतान किये ।

दूसरी तरफ मैं आगे भी बताना चाहता हूं कि विभाग ने रात्रि प्रहरी तथा अमीनों के पदों को समाप्त कर देने के कारण भी परियोजनाओं में बहुत-सी खामियां आ रही है, जिससे परियोजनाओं को पूरा करने में, तटबंधों की देखरेख करने में कठिनाई होती है ।

महोदय, तटबंधों की सुरक्षा में करोड़ों रुपये का व्यय होने के बाद भी तटबंध टूट जाते हैं और बाढ़ आ जाती है । महोदय, 13 जून को सिवान में एवं 28 जून में सीतामढ़ी में तटबंध टूट गये थे । अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध समाजसेवी मेधा पाटकर ने 12.02.2024 को कोसी तटबंध पीड़ितों के धरना में शामिल होकर राज्य सरकार से यह प्रश्न पूछा था कि सरकार ने कोसी की समस्या की जांच के लिए जो 15 कमिटियां बनाई थी उनकी सिफारिशों पर अबतक कौन सी कार्रवाई की गयी है । मंत्री महोदय इस सदन को बताने की कृपया करेंगे कि उन कमिटियों की जो सिफारिश थीं वे अबतक क्यों नहीं लागू हुईं ?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पिछले वक्तव्य में यह भी बतायें कि कोसी नदी में तीन लाख से ज्यादा घर बह गए तो मात्र 56 हजार को 6 हजार रुपये के रूप में मुआवजा दिया गया, बाकी का क्या हुआ ? वह भी माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि उस पर भी बताएं । क्योंकि जिनके घर बहते हैं और जो परिस्थितियां रहती है 6 हजार रुपये में हम समझते हैं कि उनकी कोई आवश्यकता पूरी नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, 13.07.2023 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने विधान परिषद में वक्तव्य दिया था कि नेपाल से आने वाली नदियों में बाढ़ से भारी नुकसान के स्थायी हल पर केन्द्र चुप है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए वे केन्द्र सरकार को कब तक राजी कर

लेंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो यहां अभी काम कर रही है इसलिए इनके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई इनके लिए स्थायी समाधान होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संजीदगी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सिंचाई परियोजनाओं, हम प्रकृति पर आश्रित होते हैं और प्रकृति पर निर्भर होकर जब किसान अपनी आँख टकटकी लगाकर खेती करता है, औसतन बारिश जब कम होती है तो हमारी नहर प्रणालियों में भी पानी कम आता है । यह हमारी व्यावहारिक कठिनाई है, सरकार को भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा लेकिन इन कठिनाइयों के स्थायी समाधान के लिए हमारी जो जल प्रणाली की कैनाले हैं उनकी उड़ाही के लिए जो आप योजना बनाए हैं, वह काफी कम है । आपका मेन कैनाल जो डेहरी बांध इन्द्रपुरी से चला है उस नहर के उड़ाही की आवश्यकता है । दूसरी तरफ हम अनुदान में कटौती प्रस्ताव इसलिए दे रहे हैं कि जहां हमको महसूस हो रहा है, कि जहां विपक्ष को सकारात्मक सहयोग जनहित में देना है, हम सकारात्मक सहयोग देने के लिए तैयार है लेकिन जब हम यह राशि आवंटित कर रहे हैं तो इसकी उपयोगिता भी सही होनी चाहिए ।

(क्रमशः)

टर्न-11/अभिनीत/20.02.2024

..क्रमशः..

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है । इसकी अधिकांश नदियों और जलाशयों में गर्मी में पानी सूख जाता है और जानवरों के पेयजल की भारी संकट देखी जाती है, तो सरकार को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जानवरों को उस स्थिति में उनके लिए भी यह व्यापक व्यवस्था की जाय । चूंकि बजट में जो प्रावधान है, हम सबके लिए प्रावधान कर रहे हैं लेकिन पशुधन जो किसान के लिए काम आते हैं, पशुधन गाय, बकरी इन लोगों के लिए जब चरवाहे जाते हैं और दूर-दूर तक उनको पानी का अभाव होता है, इसलिए वहां उनके लिए भी यह प्रावधान करने की जरूरत है । महोदय, विभाग के अधिकारी पर्याप्त रूप से

योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं जिसके कारण योजनाओं में गड़बड़ियां और वित्तीय अनियमितता होती है, इन सबकी जांच करानी चाहिए । अंत में मैं शिक्षा विभाग का जो बजट है, यह इसी गिलोटिन में शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपने प्रस्ताव को आगे रखते हुए..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है । बस दो मिनट ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पूरा संरक्षण है ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के पिछले 17 महीनों की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने 3 लाख नौकरियां दी हैं । इस गठबंधन की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी बात की गयी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से यह आग्रह करूंगा कि महागठबंधन की जो नीतियां हैं वह निष्पक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित, उसको सुधार करने के लिए, निष्पक्ष रूप से उन नीतियों में कटौती न करे, उसको पूर्णतः उसी तरह से लागू करे । इन्हीं औचित्य को लेकर मैंने अपना कटौती प्रस्ताव लाया था, इसका औचित्य यही था । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, अपना पक्ष रखें । आपके पास 15 मिनट समय है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन विभाग द्वारा, माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी द्वारा लाये गये मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, आपकी अध्यक्षता में पहली बार मुझे अवसर मिला है बोलने का, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा..

अध्यक्ष : आप तो कई बार मेरी अध्यक्षता में बोल चुके हैं । शायद विधान सभा की अध्यक्षता की बात आप कर रहे हैं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, पार्टी की अध्यक्षता में तो बहुत बोला, अध्यक्ष भी आपके साथ-साथ रहा जिले का लेकिन पहली बार विधान सभा में यह अवसर प्राप्त हुआ है इसलिए मैं अपने को भी सौभाग्यशाली मानता हूं । महोदय, वर्ष 2004-05 के अगर बजट को हम देखें तो राज्य सरकार का कुल बजट 23 हजार 885 करोड़ का

था और उसमें अगर हम जल संसाधन के बजट को देखें, महोदय, यह राजद सरकार का अंतिम बजट था, 261.66 करोड़ रुपये का था और आज जब इस सदन में माननीय जल संसाधन मंत्री अपना बजट पेश कर रहे हैं तो सभी सदस्यों को गर्व होना चाहिए कि आज हम 4 हजार 398 करोड़ 51 लाख 79 हजार रुपये के खर्च की बात कर रहे हैं और उसके लिए राशि मांगी जा रही है । यह जल संसाधन विभाग बिहार के अंदर दिखता नहीं था कि यह भी कोई विभाग है, यह गौण विभाग था लेकिन 2005 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार बनी और यह सरकार जब काम करना शुरू की तब अचानक उछाल आया और यह अचानक उछाल क्यों प्रारंभ हुआ महोदय, तो उसके पहले काम के बदले जिस प्रकार के काम हो रहे थे, जिस प्रकार से घोटाले हो रहे थे उसके कारण राज्य की जनता को जो उसको मिलना चाहिए हक वह नहीं मिल पा रहा था । राज्य में विकास काफी दूर की बात हो गयी थी । महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलते रहिए । ये लोग आपका समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, आज जो जल संसाधन है वह मानवता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा हवा के बाद मनुष्य के लिए जो आवश्यक है वह जल संसाधन है । महोदय, आज जिस प्रकार से जल संसाधन के क्षेत्र में गिरावट आ रही है भूगर्भ जल के क्षेत्र में और जिस तरह से जल की प्रचुरता के बाद जल की कमी हो रही है, यह हम सबके लिए, सदन के लिए चिंता का विषय है । इस पर हम सबको गौर करना चाहिए और हम सबके लिए यह चिंता का विषय है कि आज लगातार प्रतिवर्ष भूगर्भ जल की गिरावट तीन मीटर प्रतिवर्ष की दर से हो रहा है, जो बिल्कुल खतरनाक है और इसके लिए सब कोई चिंतित है । भारत सरकार इस पर, लगातार भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय इस पर काम कर रहा है । मानवता के सामने मौजूद सबसे चिंताजनक चुनौतियों में से एक है पानी का संकट । संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे निपटने के लिए

अपने सतत विकास एजेंडा 2030 के तहत एक लक्ष्य निर्धारित किया है और वह यह है कि इस अवधि के दौरान सबके लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी । मूलभूत उद्देश्य 2030 तक सबको सुरक्षित और स्वच्छ पानी सुलभ कराया जाय । इस लक्ष्य के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की जल विकास रिपोर्ट, 2019 इस बात का संकेत देती है कि दुनिया में लगभग 4 अरब लोग जो कि विश्व की आबादी का दो तिहाई हिस्सा है हर साल कम से कम एक महीने पानी की जबर्दस्त किल्लत से जूझ रहे होते हैं । भारत भी उन देशों में एक है जहां पर जल संकट बहुत जटिल अवस्था में है, जिसका समाधान करने के लिए अनिवार्य कदम उठाये जाने की आवश्यकता है और भारत सरकार ने इसके लिए लगातार कदम उठाये हैं । महोदय, उसके तहत बिहार में भी जल संसाधन पर लगातार काम होना शुरू हुआ है । महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश के अनुसार हर व्यक्ति को पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने और शारीरिक स्वच्छता के लिए प्रतिदिन कम से कम 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है । जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों को देखते हुए जल संकट एक बड़ा खतरा बन गया है । भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से जलीय चक्र प्रभावित हो सकता है । परिणाम स्वरूप वाष्प पंप, हिम गलन और पानी की उपलब्धता में स्थायी और स्थानीय परिवर्तन और तेज हो सकता है । महोदय, इसलिए यह हम सबके लिए, भविष्य के लिए चिंता का विषय है । इसमें यह कहना माननीय सदस्यों का कि और राशि कम कर दी जाय, हम क्यों राशि दें तो कैसे मनुष्य जिंदा रहेगा ? आज जल संसाधन को इसकी भी चिंता करनी है । हमारा सबसे ज्यादा पानी सिंचाई में जाता है, 30 प्रतिशत जल सिंचाई में चला जाता है । जैसे मनुष्य के शरीर में दो तिहाई जल है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी दो तिहाई जल है लेकिन सभी जल पेयजल नहीं है, सभी जल सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं आता है । तीन प्रकार के जल में हिमजल, पृष्ठ जल और भूगर्भ जल, इन तीनों पर जब हम विचार करते हैं तो सबसे ज्यादा उसमें समुद्री जल है, हिम जल है और भूगर्भ जल सबसे ज्यादा कम है । उसमें भी अगर शुद्ध पेयजल की बात करें जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है तो वह और अधिक कम है ।

इसलिए महोदय, नदी जोड़ो परियोजना की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मैं उसको बताना चाहता हूं । महोदय, 1958 में नदियों को जोड़ने पर पहली बार विचार मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य इंजीनियर आर्थर कॉर्टन ने रखा और 1960 में तत्कालीन सरकार ने गंगा और काबेरी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया था । महोदय, 2002 में तत्कालीन सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्य दल का गठन किया और साथ ही इस योजना पर देश भर में सार्थक विमर्श प्रारंभ हुआ । 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया । महोदय, 24 जुलाई..

..क्रमशः..

टर्न–12/हेमन्त/20.02.2024

श्री अरूण शंकर प्रसाद(क्रमशः): 2014 को केंद्रीय केबिनेट की बैठक में नदियों को जोड़ने को लेकर विशेष समिति के गठन की मंजूरी दी गयी और 2021 में विश्व जल दिवस के मौके पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के केन और बेतवा को जोड़ने को लेकर करार पत्र पर हस्ताक्षर किये । महोदय, इसके साथ ही देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना को औपचारिक स्वीकृति मिली । बिहार सरकार ने भी इस क्षेत्र में लगातार कई परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया है जिस पर काम चल रहा है और लगातार बिहार सरकार नदी जोड़ो परियोजना के ऊपर काम कर रही है । महोदय, अगर हम भारत के जल स्रोतों पर विचार करें, तो भारत में 24 लाख जलस्रोत हैं जिसमें शहर में केवल तीन फीसदी है । केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत के पहले वाटर बॉडी सेंसस द्वारा देश में करीब 24 लाख से अधिक जलस्रोत चिन्हित किये हैं । महोदय, इसमें चिंताजनक तथ्य यह है कि जलस्रोतों का करीब छठवां हिस्सा यानी लगभग 16 फीसदी जलस्रोत उपयोग करने के लायक नहीं हैं । या तो वह पूरी तरह से जीर्णशीर्ण हो चुके हैं या सूख गये हैं । महोदय, अनेक स्रोत अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं । दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश, जहां

पानी की उपलब्धता हमेशा से एक गंभीर मसला रहा है, पिछले 75 साल में पहली बार इस तरह की गणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं और अंततः अब जाकर यह संपन्न हुआ है । महोदय, जिस काम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आज तक जल स्रोतों की गणना नहीं हो पायी थी, लेकिन मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आज जलस्रोतों की गणना कराकर कितना उपयोग में है, कितना अनुपयोगी है, कितना अतिक्रमित है यह सारे विषयों की चिंता करने का काम किया गया है । महोदय, अगर 24 लाख जलस्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें, तो उसमें से 20,30,040 उपयोग में हैं, अर्थात 84 प्रतिशत जलस्रोत हमारे उपयोग में हैं । जो गांवों में 23,55,055 हैं यानी 97 प्रतिशत हैं और केवल 3 प्रतिशत शहरों में हैं । इसमें मानव निर्मित 18,90,463 और प्राकृतिक निर्मित 5,34,077 हैं । लेकिन जल संसाधन के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह है बिहार के अंदर बाढ़ की विभीषिका, जो आपदा बनकर आती है और यह प्राकृतिक आपदा में आता है, यह कोई मानव निर्मित आपदा नहीं है । महोदय, इस प्राकृतिक आपदा में बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है, जहां उत्तर बिहार में 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ की तबाही के आवर्ती खतरे में है, अर्थात यह नहीं है कि एक वर्ष खतरा आया और टल गया हमेशा के लिए, यह लगातार खतरा बना रहता है । प्रतिवर्ष जब सावन भादो का महीना आता है, तो हमारे लिए बाढ़ चिंता का विषय हो जाता है और राज्य का सारा कामकाज छोड़कर हमारे मंत्री सहित अधिकारियों को बाढ़ की तबाही के लिए लगना पड़ता है और यह बाढ़ की विभीषिका लगातार बढ़ती जा रही है । आजादी के पहले जितना बाढ़ क्षेत्र बिहार के अंदर था आज उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है । महोदय, उसका कारण है अंधाधुंध सड़कों का बनना, जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, बसावट जिस प्रकार से हो रही है, आबादी का बढ़ना और यह बसावट किसी प्लान के तहत नहीं होती है, जो पानी का रास्ता है, महोदय, आप देखेंगे कि अक्सर हम लोग गांव के अंदर रहते हैं और बरसात के समय, बाढ़ के समय सबसे बड़ी जो परेशानी होती है कि सस्ती दर पर, जहां पानी का बहाव था उस जमीन को खरीदकर वहीं घर बना रहे हैं ।

महोदय, यह अत्यधिक चिंता का विषय है और आने वाला समय केवल जलजमाव का समय होगा । महोदय, कितना हम लिफ्ट के माध्यम से, कितना हम मोटर पंप लगाकर पानी को खींचकर बाहर निकालते रहेंगे । इस पर एक समेकित चिंतन होना चाहिए सदन के अंदर ताकि इन समस्याओं से निजात पा सकें । महोदय, यह केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है और इसलिए समाज को मिलकर इसके प्रति जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी तभी जाकर वह हो सकेगा ।

महोदय, उत्तर बिहार में 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ की तबाही के खतरे में है । भारत में 16.5 प्रतिशत और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1 प्रतिशत होता है । बिहार के भोगौलिक क्षेत्रफल का लगभग 73.6 प्रतिशत यानी 68,800 वर्ग किलोमीटर, 26,600 वर्ग मील, 94,160 वर्ग किलोमीटर बाढ़ प्रभावित है । यह इतना बड़ा इलाका जब बाढ़ की तबाही मचाता है और खासकर जब हम बिहार के उत्तर बिहार की बात करें...

अध्यक्ष : कन्क्लूड कीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : तो कमला, कोसी, गंडक और आज से नहीं, यह नदी जोड़ो परियोजना जब लटकी रह गयी और नेपाल के अंदर हाई डैम निर्माण की जरूरत महसूस की गयी और उस समय से 2004 में जब देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो केंद्रीय स्तर की वार्ता हुई थी, सचिव स्तर की वार्ता हुई और उस समय यह प्रयास प्रारंभ हुआ कि सीसा पानी में, बड़हा क्षेत्र में और नुनथर में हाई डैम्प का निर्माण हो, जहां सात-सात नेपाल की बरसाती नदियां आकर मिलती हैं और वहां से तेज धारा बनकर आती है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : लेकिन बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किया है, मैं केवल उसको बता देना चाहता हूं । कमला बैराज पर 405 करोड़ की लागत से एक बैराज का निर्माण कराया है । जब भारत और नेपाल की वार्ता सफल नहीं हो सकी, तो कमला बैराज पर उसका निर्माण कराकर आज लाखों लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का ही काम नहीं किया है, बल्कि सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध करायी है

। महोदय, यह इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है और माननीय संजय झा जी को भी मैं इस सदन के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : और माननीय विजय बाबू भी हमेशा जल संसाधन के मंत्री रहे हैं । इन दोनों लोगों के प्रयास से वह सफल हो सका है और आज मिथिलांचल के लोग बाढ़ की त्रासदी से निजात पा चुके हैं कुछ हद तक, मैं यह नहीं कहता कि पूरी तरह से उन्हें निजात मिल चुका है ।

अध्यक्ष : अब मत कहिये, अब बंद कीजिए आप ।

माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी, अपना पक्ष रखें । 28 मिनट समय है आपका ।

श्री चन्द्र शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी पद पर आसीन होने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई । मैं उम्मीद करता हूं कि इस गरिमामयी पद की शोभा आपके नेतृत्व में बेहतर और विलक्षण रूप से काम करेगी । मैं इस अवसर पर सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी, बेरोजगारों और युवाओं के लिए हर समय चिंतित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित मधेपुरा के महान मतदाताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे बड़ी शख्सियत के खिलाफ बड़े मतों के अंतर से जिताकर इस सदन में लगातार तीसरी बार भेजा है ।

महोदय, स्वयंसिद्ध है, सर्वविदित है कि सिंचाई अधिसंरचना में वृद्धि करके ही हम कृषि क्षेत्र में फैलाव कर सकते हैं या बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं।

...क्रमशः..

टर्न-13/धिरेन्द्र/20.02.2024

(क्रमशः)

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अंग्रेजी वर्जन का जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र में राशि में भारी कटौती की गयी है और उसमें भी जो बाढ़ की त्रासदी झेलने के कारण होते हैं महोदय, वह

स्पष्ट है कि मेंटेनेंस, रिपेयरिंग में भयंकर लूट होती रही है । अरूण शंकर जी को सुन रहा था, 17-18 वर्ष से लगातार डबल इंजन की सरकार है और बारिश के समय में कोई-न-कोई तटबंध टूटता ही टूटता है । अगर 17-18 साल में डबल इंजन की सरकार भी तटबंधों को दुरुस्त नहीं कर सकती है तो कब करेगी ? यह सरकार से भी जानना चाहूँगा । महोदय, कुछ एक त्रासदी बड़ी विडम्बना है, 700 करोड़ रुपये लगाये गये, मगर रुपयों का क्या हुआ, यह भी चिंता का विषय है, जाँच का विषय है कि नहरों का अंत गंगा तक सुविधाजनक पहुँच पाया या नहीं, अगर पहुँच पाया तो कितना क्यूसेक पानी वहाँ से गंगा में प्रवाहित हो पाती है, जिससे कि बाढ़ की त्रासदी कम हो सके । मैंने जो बात कही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में, पृष्ठ-126 के टेबुल नं-3.49, इसमें स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र में 2114.87 करोड़ का इनवेस्टमेंट होता था जो वर्ष 2022-23 में घटकर 1525.59 करोड़ रुपया हो गया । महोदय, जब अनुदान माँग पर चर्चा हो रही हो तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर पैसा किस बात के लिए माँग रहे हैं, जब इतनी कटौती ही आप कर रहे हैं तो यह हमारे राज्य बिहार के कृषकों के लिए चिंता का विषय है । महोदय, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर क्षेत्रफल के अनुसार भी जो सात निश्चय-2 की परिकल्पना है कृषि क्षेत्र में हर खेत तक पानी पहुँचाने का, उसमें सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा योगदान होना है । महोदय, ऐसे में राशि में कमी हुई तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रफल में कमी होगी तो जो सिंचित क्षेत्र होना चाहिए, उसमें भी भारी कमी दर्ज की गयी है । महोदय, वर्ष 2020-21 में जहाँ 77.6 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई होती थी, वहाँ लगभग 26 प्रतिशत हो गयी है । महोदय, मैं इस बात से चिंतित हूँ कि आहर, पईन, नहर के क्षेत्र में भी भारी कटौती हुई है । वर्ष 2020-21 में 77.6 प्रतिशत क्षेत्र का सिंचाई तलाब, आहर से होता था जो वर्ष 2022-23 में घटकर 26.9 प्रतिशत हो गया है । महोदय, जब लगातार एक महत्वपूर्ण विभाग जो कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर सकती है, ऐसे मामले में सार्वजनिक निवेश में कटौती और ऊपर से हर समय यह दिखता है, लोगों के बीच चर्चाएँ होती हैं,

अखबारों में छपता है, नहर, पुल-पुलिया कभी धंस गया, कभी टूट गया तो भयंकर रूप से भ्रष्टाचार का शिकार हुई है । महोदय, मैं चूंकि माननीय मंत्री जी जल संसाधन विभाग के साथ-साथ लंबे समय तक शिक्षा विभाग को भी देखते रहे हैं और पुनः अभी देख रहे हैं । हमारी सरकार चार दिन पहले महागठबंधन की सरकार गयी है और एन॰डी॰ए॰ की सरकार बनी है.....

(व्यवधान)

10 दिन हुआ है ? जो भी, 12 या 13 तारीख को गयी तो महोदय, मेरा कहना है कि यह सर्वविदित है । महोदय, वर्ष की अगर गणना करूं तो हमारे महागठबंधन का कॉमन एजेंडा था, हम सरकार बनायेंगे तो 10 लाख लोगों को एक कलम से नौकरी देंगे, सरकार तो....

(व्यवधान)

महोदय, सरकार तो बनी नहीं, मगर सरकार में हमलोग शामिल हुए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखिये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, समय बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

आ रहा हूँ, वहाँ भी आ रहा हूँ ।

अध्यक्ष : वे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि ज्यादा कर रहे हैं । बोलिये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, तो महागठबंधन का एजेंडा था एक कलम से दस लाख लोगों को नौकरी देने का । सरकार तो नहीं बनी मात्र 12 हजार 270 वोट से, वह भी बेईमानी के बाद सरकार में हमलोग नहीं आ सकें, मगर दस लाख नौकरी देने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी को तैयार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन 15 अगस्त, 2022 का आया और तब लगभग-लगभग 4.5 लाख लोगों की बहाली हुई और उसमें अकेले 02 लाख 17 हजार शिक्षा विभाग में बहालियाँ हुई हैं । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं, एन॰डी॰ए॰ के लोग कहते हैं कि साहब हम बहाली करने में सक्षम हो पायें, ईर्ष्या-जलन से जूझ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आप कैसे कर दिये माननीय मुख्यमंत्री जी थे । माननीय मुख्यमंत्री जी

तो हैं ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे नेतृत्व को इस बात के लिए तैयार 17-18 साल में आप नहीं कर पाए, मगर महागठबंधन कर पाया, इस बात को आपको समझना चाहिए । महोदय, मैं बारीकी से चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उद्‌बोधन हुआ, वर्तमान माननीय जल संसाधन मंत्री-सह-शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो उद्‌बोधन हुआ, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, महोदय । इसलिए शिक्षा विभाग की उपलब्धि और अन्य उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अपनी बात भी करने का अवसर है, मैं उस दिन भी जवाब दे सकता था, उठा भी लेकिन समय नहीं मिल पाया, तब आप आसन पर नहीं थे महोदय और आज हैं तो हमको लगता है कि साथी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको तो हम कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं । महोदय, मैं शिक्षक हूँ....

अध्यक्ष : चन्द्रशेखर जी, कितना बढ़िया आप सिंचाई विभाग पर बोल रहे थे, कहाँ भटक गये आप, दूसरों को भी बोलने का मौका दे रहे हैं । कितना अच्छा सिंचाई पर बोल रहे थे ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षा की जरूरत को अंतरात्मा से स्वीकार करता हूँ और मैं, सिर्फ मैं नहीं, मेरे अपने परिवार में लगभग एक दर्जन से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं । इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलता रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूँ और पाँव भी छूता हूँ और यह मेरा निजी मामला है, बड़े भाई हैं लेकिन जहाँ राजनीति में सुचिता का सवाल आयेगा, जहाँ सिद्धांतविहीन राजनीति का सवाल आयेगा तो प्रश्न खड़ा होगा। महोदय, मैं यह कहता हूँ कि मैं मंत्री बनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह कर कि जबरदस्ती ले लिया तो जबरदस्ती ले कर चन्द्रशेखर ने जो काम किया महागठबंधन के नेतृत्व में, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ और मैं पुनः अपने नेता सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी का वह समय याद करता हूँ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट । बोलिये, क्या व्यवस्था है ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था मेरी यह है कि ये शिक्षक बहाली पर बोल रहे हैं । मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि शिक्षक बहाली की फाईल पर दस्तखत किये थे और डिबेट हो रहा है जल संसाधन विभाग पर तो जल संसाधन विभाग पर न बोलेंगे, ये शिक्षा पर बोल रहे हैं । शिक्षक के फाईल पर दस्तखत नहीं किये थे, छोड़ दिये थे....

अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये । चन्द्रशेखर जी, आप बोलिये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, साथी को ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या मत कीजिये । महोदय, जब यह अवसर मिला तो मुझे इस बात की अनुभूति है कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बेहतर काम किये जा सकते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-14/संगीता/20.02.2024

श्री चंद्र शेखर (क्रमशः) : महोदय, इसको टारगेट करके मुझे यह मालूम है कि भारत का गौरव अगर दुनिया में है तो उसका केंद्रबिन्दु भी बिहार है । जिस बिहार को और मगध को ज्ञान की भूमि कही जाती है, दुनिया के सबसे समुन्नत विश्वविद्यालय बिहार के विक्रमशिला, नालंदा हुआ करते थे और अब जो पाकिस्तान में चला गया वह तक्षशिला हुआ करता था । महोदय, ज्ञान के क्षेत्र में हम अपनी विरासत को प्राप्त करें इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मुझे शिक्षा मंत्री बनने का अवसर मिला, मेरे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमको बुलाकर कहा कि चाहे जो भी हो जाए हमें 10 लाख नौकरी की दिशा में कदम रखना है और आप इसके लिए बेहतर काम करने का प्रयास कीजिए । महोदय, मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में जब हमें चिन्ता हुई मैं एक महीना तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं गया । एक महीना तक...

(व्यवधान)

महोदय, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारा समय बढ़ाना पड़ेगा । ये ठीक बात नहीं है । भाई आप 4 बार, 5 बार, 6 बार जीते हैं क्यों आप परेशान हैं भाई...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिए, आप इधर देखकर बोलिए, उधर कहां देखने लगते हैं आप ?

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, एक महीना तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कर्टसी करने भी नहीं गया । एक महीना तक विभिन्न शिक्षक संगठनों से, विभिन्न हितधारकों से, विभिन्न सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और शिक्षकों से और सेवानिवृत्त और सेवारत बड़े पदाधिकारियों से भी इंटरेक्शन किया । महोदय, शिक्षक संगठनों से, आधा दर्जन शिक्षक संगठनों से इंटरेक्शन किया और एक महीना के बाद जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी कहां थे इतना दिन, हम कहे कि सर कौन सा शक्ल लेकर आते । महोदय, 17 साल में तो शिक्षा गांव में खत्म हो गया और इसके जड़ में कौन है यह साथियों को पता है । हृदयविदारक है महोदय, अच्छा है आप इस आसन पर बैठे हैं, गांव में घर आपका नहीं है । महोदय, अगर गांव में घर होता तो 17 साल में जिन्होंने शिक्षा को रौंदा है और यह भी याद नहीं है कि जब माननीय लालू प्रसाद जी के 90 के दशक में शिक्षक बहाल हुए थे बी0पी0एस0सी0 से 25 हजार, उस समय तक देश में 25 हजार एक साथ किसी राज्य ने शिक्षक बहाली नहीं किया था । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं गया और विजय बाबू भी वहीं पर थे, मैंने कहा कि साहब बी0पी0एस0सी0 को दे दीजिए परीक्षा आयोजित करने के लिए, निश्चित रूप से शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन और गुणवत्ता लाने के लिए बी0पी0एस0सी0 को देना अनिवार्य है । महोदय, उसके बाद मैंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा दान योजना लाया जाय । महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहता हूं कि मैं जब गया मुख्यमंत्री शिक्षा दान योजना का प्रस्ताव लेकर के तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सुझाव के आदेश दिए और विजय बाबू के साथ बैठकर वह फाईनल हुआ और सहमति हो गई । महोदय, दिनांक-23.09.2022 को...

अध्यक्ष : चन्द्रशेखर जी, गोपनीयता का शपथ लिए थे न उस समय, क्यों बाहर कर रहे हैं...

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं...

अध्यक्ष : बोलिए, आगे बोलिए ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, हमारे मंत्री जी भी बोल रहे थे । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं गया और वह आप सभी को मालूम है कि अधिकारी छात्रों के लिए आदर्श होते हैं । मेरे मन में एक बात थी कि अगर अधिकारी सप्ताह में अपनी इच्छा से एक दिन भी प्रखंड से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक वर्ग कक्षा का संचालन कर देंगे तो यह बिहार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष हासिल करेगा और जब हम सेवारत 2-3 आई0ए0एस0 लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारी वाईफ्स एसोसिएशन को भी डाल दीजिए । विजय बाबू के साथ सहमति हो गई, प्रोसीडिंग हो गया, सहमति हो गई उच्च स्तर पर, मगर वह मैं समझता हूं ईर्ष्यावश शायद लागू नहीं हुआ । यह एक क्रांतिकारी कदम होगा । महोदय, इसके साथ ही मैं सब लाया हूं दस्तावेज, किस-किस डेट में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया सुझाव लेकर के, एक दर्जन से ज्यादा है । महोदय, मैं सितंबर से लेकर जनवरी, 2023 तक कम से कम 5-6 बार बी0पी0एस0सी0 को दीजिए, बी0पी0एस0सी0 को दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमत हो जाते थे, अधिकारियों को निदेशित करते थे मगर पता नहीं नेपथ्य से कौन सा आदेश होता था कि फिर वह खटाई में पड़ जाता था । मगर मैं साधुवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने फरवरी, 2023 में सहमति जाहिर की जो बी0पी0एस0सी0 को परीक्षा देना है । सच कहिए महोदय, मुझे लगा कि शायद प्रभु परमात्मा ईश्वर ने अगर मुझे शिक्षा मंत्री का पद दिया है तो आज सबसे बेहतर दिन है कि बी0पी0एस0सी0 को लालू प्रसाद यादव जी के जमाने जैसा फिर से परीक्षा आयोजित करने का काम दिया गया है । महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं महोदय, फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई । मार्च, 2023 में कैबिनेट के लिए संचिका गई, 10 अप्रील को कैबिनेट की मंजूरी मिली, 24 अप्रील को प्रशासी प्रवर समिति ने वेतन निर्धारण किया और पद सृजन किया । महोदय, उसके बाद अप्रील, 2023 में

बी0पी0एस0सी0 को अधियाचना गया । अप्रील, 2023 में बी0पी0एस0सी0 को अधियाचना गया अब आप समझिए कि बी0पी0एस0सी0 की अधियाचना अप्रील, 2023 में गया, इसमें तो हम अनुपस्थित नहीं थे माननीय मंत्री महोदय जरा स्पष्ट करिएगा । उसके बाद 16 मई, 2023 को हमें हमारे एक नोटिंग में, महोदय, एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं, हमारे नोटिंग में हर समय यह होता था कि राज्यकर्मी का दर्जा जो हमारा एजेंडा था शिक्षकों के लिए, 2015 में सरकार महागठबंधन की बनी थी, 9 हजार से 18 हजार वेतन हमने किया था, आपने क्या किया जरा जवाब दीजिएगा, उसके बाद जब राज्यकर्मी का दर्जा हमारा इशू था, हमारे एजेंडा का विषय था महागठबंधन का तो राज्यकर्मी बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया । 16 मई, 2023 को राज्यकर्मी बनाने के लिए और विकल्प लेकर पदस्थापन करने के लिए प्रस्ताव दिया । महोदय, फिर अति आवश्यक सुझाव इस खंड में दिए गए बी0पी0एस0सी0 के लिए । जैसे-नेगेटिव मार्किंग हटाना, अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करना, केवल एक पाली की 150 अंकों की परीक्षा लेना...

(व्यवधान)

परीक्षा से ई-विकल्प हटाने, चांस की वार्ता समाप्त करने, वगैरह-वगैरह । जब मैं यह प्रस्ताव लेकर गया विजय बाबू भी हर जगह रहते थे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा...

अध्यक्ष : आज भी विजय बाबू आपके सामने बैठे हुए हैं ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि चंद्रशेखर जी...

(व्यवधान)

सुन लीजिए, सुन लीजिए आपके बारे में फायदा होगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा चन्द्र शेखर जी, आप तो लगता है बी0जे0पी0 वालों से सलाह ले लेते हैं । हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप लगता है बी0जे0पी0 वालों से सलाह ले लिए लेकिन मेरे हर मांग को, एकाध को छोड़कर के मेरे प्रस्ताव लिखित जो हैं मेरे पास दस्तावेज है डेट सहित, मेरे हर मांग को, सुधार के हर मांग को माना गया

मगर 5 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, महोदय, इस तरह से मैं यह डेटवाईज लाया हूं । 30 मई, 2023 को बी0पी0एस0सी0 ने विज्ञापन जारी किया । सुन लीजिए, आपलोगों को शायद सुविधा होगी । महोदय, 30 मई, 2023 को विज्ञापन जारी हुआ और नए ए0सी0एस0 का पदस्थापन 7 जून को हुआ । प्रथम विज्ञापन से लेकर नए ए0सी0एस0 के आने में लगभग एक महीना 7 दिन का अंतर है और एक महीना 7 दिन का अंतर जब प्रथम विज्ञापन में है तो बी0पी0एस0सी0 में ऐसे महान ए0सी0एस0 का क्या-क्या योगदान है यह हमको बताया जाय । महोदय, यह पूरी तरह से महागठबंधन सरकार ने और अपने इशू को रखा और हर समय यह कोशिश किया कि हम बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में कर सकें । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं हमारे नए जो ए0सी0एस0 साहब आए, आते-आते बी0पी0एस0सी0 के अध्यक्ष से उलझ गए, यह सार्वजनिक है सब जानते हैं, फिर उलझ गए, पता नहीं उलझने में वे माहिर हैं और क्या करते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-15/सुरज/20.02.2024

श्री चन्द्र शेखर (क्रमशः) : महोदय, डोमिसाइल मुद्दा एक बहुत बड़ा इशू था । डोमिसाइल नीति महागठबंधन के एजेंडे का विषय था । डोमिसाइल नीति लागू करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई । महोदय, हमको आश्चर्य है यह कहते हुये कि हम नियमावली लेकर जाते थे, विजय बाबू हर समय रहते थे । नियमावली है उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में पता नहीं अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू है । मगर अधिकारी पढ़ाते थे नहीं सब निरस्त हो गया । मेरी चुनौती है कि अगर निरस्त हुआ है उत्तराखंड का, अगर निरस्त हुआ है छत्तीसगढ़ का या देश के अन्य राज्यों का तो मैं सरकार से जवाब चाहूंगा कि कब निरस्त हुआ और अभी कौन-सा डोमिसाइल नीति चालू है...

अध्यक्ष : लेकिन आज तो वह जवाब देंगे सिंचाई विभाग पर । केवल जल संसाधन विभाग पर बोलना है...

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, चूंकि हमको आरोपित किया गया है जवाब देने दीजिये इसलिये डोमिसाइल नीति को आराम से लागू किये माननीय मुख्यमंत्री जी । मगर 25 जून को उसको निरस्त कर दिये । अब जब निरस्त कर दिये, चूंकि हम सरकार के मंत्री थे तो न चाहते हुये भी हमें स्वीकार करना पड़ा...

अध्यक्ष : अब केवल 5 मिनट बचा है आपका चन्द्रशेखर जी ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, वे लोग डिस्टर्ब किये हैं । 5 अगस्त को सर्वदलीय की बैठक हुई, जिसमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया और अलग से परीक्षा लेने पर सहमति हुई । निगेटिव मार्किंग हटाने के लिये जब मैंने कोशिश किया, 02.06.2023 को लिखकर दिया लेकिन उस समय मेरी बात नहीं मानी गयी । मेरे सलाह के दो महीने बाद बी0पी0एस0सी0 परीक्षा से निगेटिव मार्किंग हटायी गयी । मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव आया मेरे पास नियोजित शिक्षकों को लेटरल इंट्री शिक्षक बनाने का । लेटरल इंट्री के मानक नियम हैं भारत सरकार में उससे इतर शिक्षकों को अपमानित करने का, ऐसा प्रयोग करना ठीक नहीं था । मैंने मंतव्य संचिका पर दिया और लेटरल इंट्री शिक्षक का हम विरोध किये । महोदय, तब उसका नाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली हुआ । 27 अक्टूबर, 2023 को राज्यकर्मी बनने पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कठिन प्रावधानों के विरूद्ध मेरा मंतव्य था । कुछ तो माने गये अगर सारे प्रस्ताव माने जाते तो अभी शिक्षक आंदोलन को मजबूर नहीं होते । महोदय, मैं आपलोगों से कहना चाहता हूं कि 18 दिसंबर, 2023 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के निरूपण की संचिका मेरे पास आयी । ए0सी0एस0 से नहीं मुख्य सचिव के माध्यम से आयी । अब समझ लीजिये कि क्या स्थिति है, राजपाठ कैसे चलता है । ए0सी0एस0 के माध्यम से नहीं सी0एस0 के माध्यम से मेरे पास संचिका आयी और जो मैंने मंतव्य दिया कठिन प्रावधानों को हटाने का, जो अनावश्यक था, अतार्किक था, अदूरदर्शी था, गैर वैधानिक था । मैंने उस पर मंतव्य देकर अध्यापक नियमावली, 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो प्रस्ताव दिया

अधिसंख्य प्रस्तावों को माना गया, कुछ आवश्यक प्रस्तावों को नहीं माना गया, जिसके कारण शिक्षक अभी परेशानी झेल रहे हैं । पदस्थापन की क्रूर नीति कौन नहीं जानते हैं । हम कहते हैं कि हम शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं तो क्या पदस्थापन दंड के रूप में देंगे । सासाराम की लड़की किशनगंज में, किशनगंज की बच्चियां सासाराम में, मधेपुरा की बच्चियां बेतिया में, बेतिया की बच्चियां मधेपुरा में । माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति के बावजूद भी विजय बाबू के नेतृत्व में बैठक हुई और निदेश विजय बाबू ने दिये । मैंने उसी समय विजय बाबू को कहा कि सर, यह हठी हैं आपकी बात भी नहीं मानेंगे और आज तक नहीं माना है ।

अध्यक्ष : अब कंक्लूजन की ओर बढ़िये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, इम्पोर्टेंट है...

अध्यक्ष : कंक्लूजन की ओर बढ़िये, समय समाप्त हो रहा है ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, डिस्टर्ब किया गया है दो-तीन मिनट ज्यादा दे दिया जाय । मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पदस्थापन की क्रूर नीति के कारण हजारों शिक्षक-शिक्षिकायें योगदान नहीं किये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक श्वेतपत्र जारी करें जिलावाइज कि कितने लोगों के पदस्थापन के लिये चिट्ठी गयी, कितने बच्चे-बच्चियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया और ज्वाइनिंग करके कितने बच्चों ने छोड़ दिया । महोदय, मैं इसका जवाब चाहूंगा । इंटर काउंसिल को पहले से ही बहुत ज्यादा लोड है । इंटर काउंसिल सब ढंग के बड़े-बड़े एग्जाम आयोजित करती है । शिक्षकों का नियोजन, शिक्षकों की परीक्षा अलग से जब लेने का प्रावधान हुआ तो हमने सलाह दिया था कि एस0सी0ई0आर0टी0 से कराइये क्योंकि एस0सी0ई0आर0टी0 को दक्षता परीक्षा लेने का व्यापक अनुभव है । जब एक शिक्षक दक्षता परीक्षा पास कर गया तो पुनः उसकी परीक्षा की क्या जरूरत है । फिर भी चूंकि ऑफलाइन परीक्षा एस0सी0ई0आर0टी0 लेती है उस समय मेरी बात नहीं मानी गयी । मगर बाद में माननीय मंत्री जी का और ए0सी0एस0 साहब का फरमान आया कि हम दो बार ऑफलाइन एग्जाम भी लेंगे । मेरा इसमें चिंता का

विषय है पिछले दफा अखबारों में पढ़ा राजद के मंत्री बेईमान हैं मगर दूसरे कोई नहीं हैं । यह एक तरफ से डर लगता है कि यह निश्चित रूप से वाइजनेस है सरकार का । आपको अगर...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, तीन मिनट...

अध्यक्ष : आपका टाइम हो रहा है ।

श्री चन्द्र शेखर : आपको अगर जांच करानी है तो 2015 से लेकर आज तक शिक्षा विभाग का गांव से लेकर शहर तक जांच कराइये और इस अवसर पर मैं तो यह कहता हूं कि जांच करानी है तो सदन की सर्वदलीय कमेटी से कराइये । अगर जांच करानी है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत जजों से कराइये । बाकी सरकारी एजेंसियों का क्या हाल है...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री चन्द्र शेखर : अंत में महोदय आउटसोर्सिंग बहाली में एक लाख से ज्यादा...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये आप ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, 2 मिनट कंक्लूड कर देता हूं । आउटसोर्सिंग बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया । मेरे पास पत्र है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, 2 मिनट । केबिनेट का निर्णय है और राज्यादेश है फिर भी आउटसोर्सिंग बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया...

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया है । हम जल संसाधन मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुये हैं । हम...

अध्यक्ष : ललित जी 10 मिनट का समय है आपके पास, बोलिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : हम सुल्तानगंज की जनता के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस लायक हमको समझा कि हमको विधान सभा चुन करके भेजी है । हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री और

माननीय मुख्य सचेतक श्रवण बाबू के भी शुक्रगुजार हैं कि हमको मौका मिला है और हम पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, सात निश्चय-2 अभियान में ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' पहुंचाने के लिये हमारे जल संसाधन मंत्री माननीय विजय बाबू अभी तक चयनित 1198 योजनाओं में से 621 योजनाओं को पूरा करवा लिये हैं, जिससे कि 2 लाख 10 हजार 524 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था दुरूस्त हुई है । गया, बोधगया, राजगीर एवं नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना को पूरा कर लिया गया है, जिससे वहां की जनता को पेयजल प्राप्त हो रहा है इसके लिये भी हम माननीय मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं । अध्यक्ष महोदय, 4515. 70 करोड़ रुपये के तहत हथीदह के निकट इन्टेकवेल-सह-पंप हाउस का निर्माण किया गया है । राजगीर के निकट गंगा जी राजगृह जलाशय, गंगा जी गया जलाशय का निर्माण हुआ है । नवादा शहर में भी गंगा जल से पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ हो गयी है । यह साधारण बात नहीं है कि जहां पानी की बहुत दिक्कत है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है और हमारे मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर लोगों के लिये पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, 114.97 करोड़ की लागत से सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट का निर्माण हुआ ।

(क्रमशः)

टर्न-16/राहुल/20.02.2024

श्री ललित नारायण मंडल (क्रमशः) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एक सुखद घटना है और इसके लिए हम लोग सरकार को बधाई देते हैं । पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अंतर्गत नहरों की गाद सफाई एवं उनके बांधों तथा संरचनाओं के पुनः निर्माण के लिए 810 करोड़ रुपये स्वीकृत होने से मधुबनी जिले के 19 प्रखंडों एवं दरभंगा जिले के 5 प्रखंडों के किसानों को बहुत लाभ मिला है । सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है । उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 386.86 करोड़ में गंगा को फल्गू नदी में पूरे वर्ष गंगा जी डैम में

लगाकर हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने बहुत ही धार्मिक काम किया है । उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि भागीरथ ने बहुत अथक परिश्रम करके गंगा को स्वर्ग से उतारकर गंगोत्री से लाकर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए काम किया था । यह हमारे मुख्यमंत्री जी इस मायने में दूसरे भागीरथ साबित हुए जिन्होंने गंगा को फल्गू नदी में उतारकर और वहां हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने का काम किया है । नदियों को जोड़ने एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 130.88 करोड़ की लागत से बागमती-बूढ़ी गंडक 120.96 करोड़ की लागत से बागमती-बूढ़ी गंडक की शांतिधार योजना 69.89 की लागत से गंडक-अकाली नाला-गंडक-माही-गंगा नदी जोड़ योजना कार्य प्रगति पर है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बगल के मुंगेर जिले के हवेली-खड़गपुर प्रखंड में 125.92 करोड़ की लागत से सिंधवारिणी जलाशय योजना, 145.43 करोड़ की लागत से डकरानाला पंप नहर योजना के बचे कार्य को कराने के लिए जो प्रस्ताव गया है इसके लिए हम ही नहीं मुंगेरवासी भी और भागलपुरवासी भी इसके लिए सरकार के और मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं । इसी तहर अन्य कई सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है अगर उन सबको हम रखना चाहें तो उतना समय हमको प्राप्त नहीं होगा । चूंकि कम समय में हमको सब बात रखनी है इसलिए बहुत चुन-चुन कर के चुनिंदा बातों को हमने आपके सामने रखा । उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपने क्षेत्र की कुछ योजनाओं की बात मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । सर्वप्रथम सुलतानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा किनारे पर गंगा रीवर फ्रंट के तहत सीढ़ी घाट, सौंदर्यीकरण एवं नमामि गंगा घाट से गंगा के किनारे-किनारे रेलवे ओवर ब्रिज सुल्तानगंज तक कावड़ियों के लिए पी0सी0सी0 सड़क निर्माण की मांग करता हूं । इस मांग का मौखिक समर्थन हमारे तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय बाबू थे उन्होंने भी किया था और मौखिक समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमको प्राप्त हुआ है । इसलिए हम अपने वर्तमान जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारी इस मांग पर थोड़ा-सा ध्यान दें और आप जानते हैं कि सुल्तानगंज बहुत ही धार्मिक स्थल है । सुल्तानगंज से कावड़िया जल उठाकर के

देवघर तक प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में जाते हैं । इसलिए गंगा रीवर फ्रंट सुल्तानगंज का निर्माण होना चाहिए । यहां से इंजीनियर सब जाकर के उसका सर्वेक्षण भी हो चुका है । इसलिए थोड़ी-सी कृपा कीजियेगा तो सुल्तानगंज जो धार्मिक स्थल है वहां से यात्रियों को देवघर जाने में बहुत सुविधा होगी । दूसरी बात है कि...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, दूसरी बात है कि सुल्तानगंज से गंगा जल को लिफ्ट कर बांका जिले के बहुआ डैम में जल जमा कर उचित समय पर सिंचाई करायी जाय तो इससे सुल्तानगंज, तारापुर, अमरपुर एवं बेलहर विधान सभाओं के कृषकों को अपार समर्थन मिलेगा और उनके पेट को अन्न मिलेगा । तीसरी बात अंत में अपनी बात कहना चाहता हूं कि अंत में मैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के अपने गांव मंझली हमारी बस्ती का नाम है जो गंगा की बाढ़ में डूब जाता है । हम चाहते हैं कि मझली बस्ती को बचाने के लिए एक रिंग बांध जिसको बबूरिया बांध कहते हैं, का निर्माण कराने की मांग करता हूं...

उपाध्यक्ष : ठीक है समाप्त कीजिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामवृक्ष सदा । आपका समय 16 मिनट है ।

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपके और आपके सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं आभार प्रकट करता हूं गरीबों का मसीहा, देश के सबल प्रहरी आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का और मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार के सबल प्रहरी, गरीबों के मान और सम्मान आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी को जिन्होंने एक गरीब, मुसहर, मजदूर के बेटा को आज इस विधान सभा में भेजने का काम किया है । मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे सचेतक आदरणीय शाहीन साहब का जिन्होंने आज मुझे बोलने के लिए समय दिया । मैं आभार प्रकट करता हूं अलौली विधान सभा की महान जनता मालिक को जिनके आशीर्वाद, प्यार और

सहयोग से आज इस विधान सभा में मुझे बोलने का मौका मिला है । मैं आभार प्रकट करता हूं पूरे सदन का जिनके सामने आपने मुझे बोलने का मौका दिया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं :

''तरक्की की फसल हम भी काट लेते,
थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते ।
मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था,
इनके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था ।।
पल भर के लिए मैं बेजमीर हो जाता,
माननीय मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कब अमीर हो जाती ।।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मांग के संबंध में मैं बताना चाहता हूं जल संसाधन विभाग की मांग है, शिक्षा विभाग की मांग है, ग्रामीण कार्य विभाग की मांग है, परिवहन विभाग की मांग है, योजना एवं विकास विभाग की मांग है, संसदीय कार्य विभाग की मांग है, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी विभाग की मांग है, सूचना एवं जन संपर्क विभाग की मांग है, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग की मांग है तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मांग है । ये तमाम 10 विभाग की मांग पर आज सदन में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं । सबसे पहले जो जल संसाधन विभाग की मांग है । जल संसाधन विभाग में मैं कहना चाहता हूं आप जानते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की त्रासदी से बिहार के लोगों की हर साल कमर तोड़ दी जाती है और उस बाढ़ को रोकने के लिए जो उपाय होने चाहिए उसके लिए सरकार के स्तर पर उपाय नहीं हैं । बहुत दिन से आज 17-18 साल से आज आपकी सरकार है, एन0डी0ए0 की सरकार है और शुरू से ही आपकी सरकार कह रही है कि इस महीने में हम बाढ़ से निजात दिला देंगे, अगले साल दिला देंगे, उस साल दिला देंगे लेकिन अभी तक बाढ़ से कोई निजात नहीं मिली है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपके जल संसाधन विभाग में चाहे आपकी नहर की बात हो, चाहे बागमती नदी की बात हो, चाहे कमला, कोशी, करेल नदी की बात हो आप जाकर स्थिति

देखिये । हम लोगों के यहां ही नहीं बल्कि बिहार के जितने जिले में आपकी बागमती नदी टच करती है ।

क्रमशः

टर्न–17/मुकुल/20.02.2024

क्रमशः

श्री रामवृक्ष सदा : जिस बागमती को लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसके ऊपर भरकर लोगों का घर बन रहा है और बागमती नदी एक समय जो सिंचाई के काम आता था, उस बागमती नदी से सिंचाई होता था लेकिन उसमें आपकी सरकार और आपने कोई नहर बनाने की व्यवस्था नहीं की कि किसान उस बागमती नदी से सिंचाई करे । उसके ऊपर आपने उस ढंग का कोई काम नहीं किया है । बागमती नदी की आज स्थिति यह है कि आप चले जाइये, हम दूसरी जगह की बात नहीं करना चाहेंगे, हम अपनी अलौली विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहेंगे । आप अलौली विधान सभा में बहादुरपुर से लेकर बागमती नदी संतोष में आकर कोसी नदी में मिलती है, इसके बीच में लगभग 10–12 पंचायत हैं, चाहे वह बहादुरपुर हो, चाहे गौराचक हो, चाहे सिमराहा हो, चाहे हरिपुर पंचायत हो, चाहे सहसी पंचायत हो, चाहे भिखारीघाट पंचायत हो, चाहे हथवन पंचायत हो, चाहे अलौली पंचायत हो, चाहे अम्बां इचरूआ पंचायत हो या चाहे चातर पंचायत हो । इन तमाम पंचायतों से होकर यह नदी गुजरती है और इस नदी की यह स्थिति है कि पूरी की पूरी नदी का अतिक्रमण हो चुका है और यह नदी हमलोगों के किसानों की सिंचाई का एक मात्र महत्वपूर्ण स्रोत है और उसमें आपका कहीं पर भी नहर नहीं है । अगर आप उस नदी से नहर निकालकर पटवन की व्यवस्था करते हैं तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा । हमलोगों का कोसी क्षेत्र का इलाका है, हमलोगों के क्षेत्र में कुछ दिनों के बाद बाढ़ का पानी घूसेगा, बाढ़ अफरा–तफरी मचायेगी । यह फ्लड–कंट्रोल का जो काम होता है वह तो देखने लायक होता है । यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, जब पानी आना शुरू होता है तब फ्लड–कंट्रोल का काम शुरू होता है । इधर कोसी में पानी गिरता है और उधर बोरा में बालू भरा

जाता है और सभी बालू को कोसी में बहा दिया जाता है और ठेकेदार पैसा उठा लेता है । इसलिए अगर फ्लड-कंट्रोल का काम होना चाहिए तो बाढ़ के आने से पहले होना चाहिए । फ्लड-कंट्रोल का काम जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल तक में पूरा हो जाना चाहिए । जून-जुलाई में बाढ़ आता है और आप जून-जुलाई में फ्लड-कंट्रोल का काम करते हैं जो कहीं सक्सेस नहीं है । यह लूट का अड्डा बना हुआ है, इसमें ठेकेदार और बिचौलियों का फायदा होता है, इसमें किसी का फायदा नहीं होता है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिस बागमती नदी की हमने चर्चा की है, यह बिहार के कई जिलों से होकर गुजरती है और आप इस नदी से सिंचाई के लिए नहर निकाल सकते हैं यह हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे । हम दूसरा आग्रह करना चाहेंगे कि आपने बागमती नदी में आज से तीन साल, चार साल पहले जो कोसी बांध का ऊंचीकरण करवाया था, उसमें कहीं पर बांध का ऊंचीकरण हुआ है और कहीं पर उसी ढंग से है । जो ठेकेदार हैं वे सही से काम नहीं किये हैं, छोड़-छोड़कर काम किये हैं । उसके बाद जहां पर गांव है, वहां पर आपका बांध ऊंचीकरण हुआ है, आपके बांध में जब वर्षा होती है तो बांध की मिट्टी गांव के रोड को पूरा अस्त-व्यस्त कर देती है । तीन महीना तक हमलोगों के इलाके में चाहे सनोखरा गांव हो, चाहे मेघौना गांव हो, चाहे गौरा गांव हो, चाहे हथवन गांव हो, चाहे रामपुर गांव हो, चाहे अलौली गांव हो, चाहे अम्बां इचरूआ गांव हो या चाहे चातर गांव हो इन तमाम जगहों से होकर जो बांध गया है वहां पर मिट्टी पड़ी हुई है वह मिट्टी वर्षा के पानी से गलकर लोगों के घरों में घूस जाती है, इसके कारण रोड भी अस्त-व्यस्त हो जाता है, वह रोड चलने लायक नहीं रहता है । तीन महीनों तक हमलोगों के क्षेत्र का आदमी जिनका घर बांध के बगल में है वह नर्क की जिंदगी जीता है । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार से मांग करना चाहेंगे कि आप बांध पर ईंट सोलिंग कराने का, जहां-जहां गांव है वहां-वहां पर बांध पर ईंट सोलिंग करवा दें । अगर बांध पर ईंट सोलिंग हो जाता है तो गांव में जो बांध की मिट्टी धस जाती है

उस समस्या से वहां के ग्रामीणों को निजात मिल जायेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे आपका बांध भी पक्का होगा और इससे ग्रामीण भी खुश हो जायेंगे । महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा विभाग की भी मांग है । शिक्षा विभाग की मांग में मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो और जब उन्होंने संविधान लिखा था, जब उन्होंने शिक्षा की बात की थी कि शिक्षित बनो तो लोग जब शिक्षित बनने के लिए तैयार हुए थे तो उस समय इतनी छुआछूत की भावना थी कि लोग चाहकर भी शिक्षित नहीं होते थे । बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी का संविधान पन्नों में ही सिमटकर रह गया । जब 1990 का दशक आया, जब 1990 का दौर आया, जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का आगाज हुआ तो उन्होंने कहा था कि ए गाय चराने वाले, ए भैंस चराने वाले, ए बकरी चराने वाले, ए सुअर चराने वाले, ए घोंघा चुनने वाले, ए चूहा पकड़ने वाले पढ़ना-लिखना सीखो और बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 के दौर में मुख्यमंत्री बने थे तो वे कभी मुसहर की बस्ती में चले जाते थे, कभी डोम की बस्ती में चले जाते थे, कभी मेस्तर की बस्ती में चले जाते थे और कभी पासवान की बस्ती में चले जाते थे और मुसहर के बच्चों के अपने हाथों से बाल झाड़ते थे, किताब-कॉपी देते थे, स्लेट-पेंसिल देते थे और उनको स्कूल भेजते थे और जब हमलोगों की मां-बहन कहती थी कि लालू बाबू हमलोगों को रहने के लिए घर नहीं है तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते थे अगर जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो या नहीं तो मरना सीखो और जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी को हमलोगों की मां-बहन कहती थी कि हमलोगों को रहने के लिए घर नहीं है, हमलोगों के लिए रोड नहीं है तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारा बेटा शिक्षित हो जायेगा, उस दिन तुम्हारा शिक्षित बेटा विकास की लकीर को तुम्हारे गांव तक खींच देगा । यह था वह 1990 का दौर और 1990 की शिक्षा । शिक्षा के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन उस समय भी हुआ था । आज जितने स्कूल हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर कोई भी माननीय सदस्य ईमानदारी से बता दें कि आज बिहार में जितने भी

स्कूल चल रहे हैं, बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर 25 हजार ठोस शिक्षकों की बहाली नहीं करते तो आज बिहार में जो भी शिक्षा है वह भी गर्त में चली जाती । आप सभी लोगों ने मिलकर शिक्षा का क्या हाल कर दिया है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । आपलोग नहीं चाहें कि गरीब का बच्चा पढ़े, आपलोग नहीं चाहें कि शोषित का बच्चा पढ़े, आपलोग नहीं चाहे कि दलित का बच्चा पढ़े और आपलोगों ने नम्बर के आधार पर शिक्षकों की बहाली करने का काम किया है । जो लोग गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उनके पास उतने नम्बर नहीं थे, जिसके कारण आपलोगों ने उनको वंचित करने का काम किया । यह बाबू लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि गरीब का बच्चा पढ़ने लगा, मुसहर का बच्चा पढ़ने लगा । जब डोम का बच्चा पढ़ने लगा, जब मेस्तर का बच्चा पढ़ने लगा और भंगी का बच्चा पढ़ने लगा तो आपलोगों ने आरक्षण खत्म करने के लिए निजीकरण कर दिया कि किसी को नौकरी नहीं देनी है, चाहे वह पिछड़ा का बेटा हो, अत्यंत पिछड़ा का बेटा हो, दलित का बेटा हो या महादलित का बेटा हो । आपलोग कभी भी निचले वर्ग के लोगों को, नीचे पायदान पर जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दीजिएगा, यही आपलोगों की नीयत है । आज देखिए, जहां हमलोग नौकरी की बात करते हैं वहां निजीकरण हो गया, कहां आरक्षण गया, कहां बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी का संविधान गया । आज शिक्षक की बात है, हमको यह पता नहीं चलता है कि आज इस बिहार में क्या हो गया है, सरकार ऊपर है या प्रधान सचिव ऊपर है यह पता ही नहीं चल रहा है । यह भी पता नहीं चल रहा है कि सरकार पदाधिकारी को चला रहा है या पदाधिकारी सरकार को चला रहा है यह बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस संबंध में आपके माध्यम से ठोस पहल होनी चाहिए, आप बिहार के जाने-माने मंत्री हैं और आपके अंदर शिक्षा विभाग भी है, इसलिए इस संबंध में ठोस पहल होनी चाहिए । यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में किसी भी पदाधिकारी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जायेगी, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमलोग

चुकाने के लिए तैयार हैं । इसलिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर भी निर्णय लीजिए, आप अपने हाथों में काम लीजिए, अपने हाथों से काम कीजिए, आप सब कुछ पदाधिकारी के भरोसे छोड़ देते हैं, आपके पदाधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं, आपके पदाधिकारी आपको सही बात नहीं बताते हैं, आपके पदाधिकारी आपको गुमराह करते हैं इसलिए ऐसे लोगों से आपको होशियार रहने की जरूरत है, सरकार को ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है।

क्रमशः

टर्न–18/यानपति/20.02.2024

श्री रामवृक्ष सदा (क्रमशः) : और आप जनता के हित में निर्णय लीजिए, जनता के हक में काम कीजिए और जनता के हक में काम कीजिएगा तो जनता खुद आपकी जय–जयकार करेगी, आप चले जाइये अभी बहुत से साथी बोल रहे थे, नौकरी की बात बोल रहे थे.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : हमारे शिक्षा मंत्री जी की बात बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं अभी हमारे आदरणीय मांझी जी भी बैठे हुए हैं, वह हमारे गार्जियन हैं, बहुत दिन से सदन में हैं आज से नहीं हैं हमलोग बच्चे थे, तबसे हैं । क्या बताएंगे कि इस बिहार में यदि सबसे ज्यादा शिक्षा की स्थिति गिरी हुई है तो वह किस जाति की गिरी हुई है, वह मुसहर जाति की गिरी हुई है । आपने क्या कोई पहल की, आपने क्या सरकार से कोई ठोस उपाय किया, आपने क्या कुछ किया । आज हमलोगों के समाज में, आज हमलोग कुछ भी बोलते हैं, हमलोगों की बात दब जाती है, आज हमलोगों के समाज में पत्रकार नहीं है, आज हमलोगों के समाज में मीडिया नहीं है, शिक्षा के माध्यम से सरकार से और आपके सदन से मांग करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि आप जो है हमलोगों के लिए पिछड़ा, अत्यंता पिछड़ा दलित के लिए पत्रकार का कॉलेज खुलवाइये, जहां दलित का बेटा भी पत्रकारिता कर के हमारी बातों को बुलंद करेगा, यह मैं सदन से मांग करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, समाप्त कीजिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : कुछ क्षेत्र की मांग है महोदय, मैं आपका सम्मान करते हुए हमारे क्षेत्र में अलौली विधान सभा के अंतर्गत खगड़िया प्रखंड के जलकौरा में गंडक नदी पर पुल बन रहा था, वह पुल ठेकेदार छोड़कर भाग गया है इसपर महोदय सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । उस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो, दूसरा महोदय अलौली विधान सभा के अंतर्गत अलौली प्रखंड में गढ़घाट में कोसी नदी में, करेह नदी में बहुत दिनों से जनता की मांग है कि यहां पुल बने इसलिए आपके आसन, सदन और सरकार से.....

उपाध्यक्ष : ठीक है, समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र जी ।

श्री रामवृक्ष सदा : मैं मांग करना चाहता हूं कि गढ़घाट में पुल बने इन्हीं बातों के साथ एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं महोदय.....

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री रामवृक्ष सदा : ''मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था,
मेरी किस्ती थी डूबी वहां, जहां पानी कम था''
इंकलाब जिंदाबाद ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : सबसे पहले मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, मैं अपने डिप्टी सी0एम0 श्री सम्राट चौधरी जी को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं महोदय जो आज हमको इस जगह पर बोलने का अवसर मिला है महोदय । हम अपने सचेतक महोदय जनक सिंह को भी आभार व्यक्त करते हैं महोदय उन्होंने भी हमें बोलने का मौका दिया हृदय से आभार व्यक्त करता हूं महोदय । महोदय, सबसे पहले मैं अपने जल संसाधन मंत्री अभिभावक स्वरूप आदरणीय विजय चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अपना बिहार बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित है महोदय और शुरू से ही यह होते आया है महोदय । यह प्रकृति की देन है लेकिन जिस तरह अपने बजट में इन्होंने प्रावधान किया है, यह बिहार की जनता के लिए गौरव है महोदय । 24-25 का बजट जो आदरणीय हमारे

यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया है । महोदय, हम अपनी तरफ से बिहपुर विधान सभा की तरफ से भी आभार व्यक्त करते हैं, अपने विधान सभा के लाखों जनता का आभार व्यक्त करते हैं महोदय कि जिन्होंने हमें दूसरी बार विधायक बनाने का काम किया है उस बिहपुर विधान सभा की जनता को भी मैं हृदय से नमन करता हूं । महोदय, अभी राजद के लोग XXX कर, चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे, इतना गंदा बोल रहे थे महोदय, इन लोगों को आदत हो गई है किस तरह ये चिल्लाते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी, एन0डी0ए0 का संस्कार है कि हमलोग संसदीय भाषा की तरह बोलते हैं । महोदय, बोलने लगेंगे तो वह छोड़कर चले जाएंगे । महोदय, सबसे पहले तो इश्तेहार चिपकवा दीजिए, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जनता ने उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहां पर भेजा था लेकिन आज लगातार दो दिन से जनता की अनदेखी करके यह लोग सदन से बाहर हो रहे हैं महोदय, यही यह बिहार की जनता के लिए चिंता करते हैं । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यह फिर से चिल्लाएंगे, इनको चिल्लाने की आदत है, मुझे कम समय दिया गया है मैं अपने आदरणीय विजय चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत कम समय बोलूंगा मैं कि यह पूरे बिहार में जो कटाव निरोधी कार्य हैं, वह पूरे चाहे वह गंडक नदी से हो, कोसी नदी से हो, कमला बलान नदी से हो.....

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपलोग बैठ जाइये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : सबों ने, सब जगह बाढ़ नियंत्रण के लिए इन्होंने काम किया है । उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, ये लोग तो चिल्लाएंगे ही महोदय, इनका काम ही है महोदय पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का शेष कार्य सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए कार्य प्रगति में है.....

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : असंसदीय भाषा प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगा । यदि आपको असंसदीय लग रहा है तो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगा । आप विषय पर बोलिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, ये दुहाई दे रहे थे, महोदय, मुंगेर जिला के.....

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : सभी लोग अपने आसन पर जायं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : हवेली खड़गपुर प्रखंड में 125 करोड़ रुपये की लागत राशि से.....

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : जो भी असंसदीय शब्द है सब निकाल दिया जायेगा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : हम अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं महोदय.....

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : भूदेव जी को बोलने दीजिए । जो भी असंसदीय भाषा है उसे प्रोसीडिंग से हटा दिया जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गए)

श्री भूदेव चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके समक्ष एक दलित सम्मानित विधायक ने अपनी बात बड़े ही तरीके से, बड़े ही सलीके से रख रहे थे.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : सुन लीजिए, बोल दिए न असंसदीय भाषा को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाएगा । माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री भूदेव चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके समक्ष एक दलित माननीय विधायक ने अपनी बात बड़ी ही स्पष्टता से और बड़ी ही शालीनता से, सरलता से रख रहे थे लेकिन आपने देखा, वह भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने इशारा करके कहा कि दलित की भाषा XXX है, XXX है, इस तरह से दलितों का अपमान हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, उनको माफी मांगनी

चाहिए । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से दलितों की उपेक्षा हो रही है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, आपसे अनुरोध है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः वेल में आ गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : असंसदीय भाषा निकाल दिया जाएगा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : मैं बोलना चाहता हूं महोदय.....

उपाध्यक्ष : आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री कुमार शैलेन्द्र : मुझे बोलने दिया जाय महोदय.....

उपाध्यक्ष : जो भी असंसदीय भाषा है वह प्रोसीडिंग से निकल गया ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र जी, जो भी बोलना हो जल संसाधन पर बोलिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, यह विपक्ष के लोग इसी तरह बोलते रहते हैं । आदरणीय इनके तेजस्वी यादव अपने बजटीय भाषण में इन्होंने खुद कहा था बैठो न, सुन तो लो, क्या यहां दलित के लोग नहीं रहते । हमारे विधायक दलित नहीं हैं क्या जो इस तरह माननीय सदस्य को कहते हैं । यह अपनी भाषा को सही मानते हैं महोदय । मैं आपके माध्यम से.....

(व्यवधान जारी)

टर्न-19/अंजली/20.02.2024

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, साफ-साफ शब्दों में आसन के द्वारा कहा गया कि जो भी अंससदीय भाषा बोली गई है वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगा, उसके बावजूद भी आप लोग झूठमूठ का डिस्टर्ब कर रहे हैं । प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, निकाल दिया जाएगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुडंघाट जलाशय योजना का निर्माण 185 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है । महोदय, इस योजना के निर्माण से जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में कुल 2035 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगी । माननीय महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत दियारा पंप हाउस का निर्माण एवं इसके वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य....

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : बैठिये आप लोग । अपने-अपने जगह पर जाइए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : 56.63 करोड़ रुपये के हरहर पंप हाउस का निर्माण कार्य एवं लिंक नहर का निर्माण 57.71 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : ठीक है बैठिये । आप सब पहले बैठिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : बक्सर जिलान्तर्गत कर्मनाशा नदी पर निकृष पंप नहर योजना का निर्माण कार्य 64.22 करोड़ रुपये की लागत से...

उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य अब समाप्त कीजिए । आपका समय खत्म हो चुका है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मुझे बोलने दिया जाय । मेरा समय तो यही लोग ले लिये ।

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग स्थान पर बैठिएगा तभी न कुछ होगा । बैठिये न स्थान पर । सब लोग स्थान पर बैठिये न । सत्यदेव जी आप बोलिए । सत्यदेव जी को बोलने दीजिए । सत्यदेव जी बोलेंगे ।

(व्यवधान जारी)

शांति-शांति । बोलिए सत्यदेव जी । माननीय सदस्यगण, आपलोग अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए । शैलेन्द्र बाबू, बैठ जाइए । माननीय सदस्य संजय जी बैठ जाइए । माननीय सदस्य बैठिये । बोलिए सत्यदेव जी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ गए)

श्री सत्यदेव राम : महोदय,...

उपाध्यक्ष : सत्यदेव जी बोल रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आज भाजपा के माननीय सदस्य ने...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, समय दिये हैं, बोल रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आज भाजपा के माननीय सदस्य ने जिस तरह से सदन के अंदर एक माननीय दलित सदस्य को ये XXX कहे हैं यह अपमान है और उनको माफी मांगनी होगी महोदय ।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : इधर से भी बोलने देंगे, उनको बोलने दीजिए न ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, ये पूरे बिहार के दलितों का अपमान है । जब हमलोगों का सम्मान नहीं होगा तो दलित का सम्मान कैसे होगा महोदय ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : इधर से भी बोलिएगा । माननीय सदस्य, इधर से भी मौका मिलेगा । बोलने दीजिए उनको ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, ये लोग गांव से लेकर के सदन तक अपमान करते हैं । हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस सदन के अंदर जो माननीय सदस्य ने इस तरह के शब्द का व्यवहार किया है उनको माफी मांगनी होगी, तभी सदन चलेगा । इसलिए आप आदेश कीजिए । हमारा इतना ही है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य सर्वजीत जी बोलिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय,..

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : इसके बाद आप बोलिएगा । हां-हां बोलिए । इसके बाद आप बोलिएगा न । बैठिये न । उधर से बोलिएगा । बैठ जाइए न । इसके बाद आपलोग बोलिएगा । अपनी बात रखिएगा सरावगी जी इनके बाद ।

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन जो है...

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : बोलने दीजिए, माननीय सदस्य बोल रहे हैं । आप बोलिए । समीर साहब, चुप रहिए न बोल रहे हैं न ।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गए)

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है । लोकतंत्र में सभी जाति, धर्मों को जनता जीता कर इस सदन में भेजती है ।

(व्यवधान)

सुन लीजिए न । आपलोगों की आदत है कि जब भी सदन के अंदर, सदन के बाहर कोई अगर दलित का बेटा कुछ बोलना चाहता है तो आप लोग आज से 50 साल पहले वाला व्यवहार करना शुरू कर देते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति मुसहर का बेटा है और अगर इस व्यक्ति का, अगर उस माननीय सदस्य की आप जीवनी और इतिहास निकालिएगा तो आधी जिदंगी...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठिये । आपकी तरफ से भी बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे । माननीय सदस्य कृपया आप समाप्त कीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : बैठिये न । आपसे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : आपसे ज्यादा विद्वान हैं हम, समझ गए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब बैठ जाइए ।

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुसहर का बेटा अगर सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ है, महोदय, उसके बाद असंसदीय भाषा का प्रयोग कि XXX करता है अगर आपको लगता है उपाध्यक्ष महोदय...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, असंसदीय भाषा हम पहले ही कह दिये हैं कि जो भी है वह प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, अगर आपको लगता है, आप जिस आसन पर बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि सदन में कोई दलित के बेटे को अधिकार नहीं है तो मैं सदन का बहिष्कार करता हूं । हमलोग सदन से चले जाते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से वॉकआउट कर गए)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी ।

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता जाने की जो खिसियाहट होती है वह इन लोगों में परिलक्षित और दिखाई पड़ती है । महोदय, माननीय कुमार शैलेन्द्र जी जो बोल रहे थे कोई ऐसा शब्द नहीं बोले, इन लोगों ने उसमें जाति का रंग देकर और मैं चुनौती देता हूं सत्यदेव जी ने जो शब्द बोला, वह आप वीडियो मंगा कर देख लीजिए, अगर वह शब्द कुमार शैलेन्द्र जी ने बोला होगा, कितना मिसलीड कर रहे हैं, सत्यदेव जी द्वारा जातीय रंग दिया जा रहा है । सत्ता जाने की जो खिसियाहट होती है वह साफ दिखाई पड़ रही है । उपाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा जाति सूचक शब्द माननीय विधायक ने नहीं बोला और सत्यदेव जी ने जातीय सूचक शब्द बोला है । आप वीडियो मंगा के देखिए । सत्ता जाने की जो खिसियाहट होती है वही विलाप ये लोग कर रहे हैं, जनता देख रही है जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उसका

हिसाब जो है इस सदन में होगा और एक मिनट, मैं चुनौती देता हूँ सत्यदेव जी ने जो बोला है, आप इसको नोट करिए और वीडियो देखिए । माननीय विधायक कुमार शैलेन्द्र जी का भी वीडियो देखिए और सत्यदेव जी ने जो बोला है उसका भी वीडियो देखिए । जिन्होंने गलत बयानी की है उनको माफी मांगनी चाहिए और सत्यदेव जी से माफी मंगवानी चाहिए सदन में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाहता हूं आपको ।

XXX - आसन के अदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

टर्न-20/आजाद/20.02.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में कुछ देर से जो अप्रिय बातें हो रही हैं, वे सदन में शोभनीय नहीं हैं क्योंकि बात बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंच गई है कि एक माननीय सदस्य ने आसन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई दलित का बेटा सदन में बोले तो हमलोग जाते हैं । महोदय, यह बिल्कुल गलत परम्परा है और लोग अपने किसी निजी राजनैतिक स्वार्थवश लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ें, यह अच्छी बात नहीं है। आपने तो बहुत ही सही कदम उठाया कि अगर माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र जी कुछ बोल रहे थे, उसमें कुछ आपत्तिजनक असंसदीय शब्द या अमर्यादित बात थी तो आपने आसन से नियमन दे दिया कि उसको निकाल दिया जायेगा और संसदीय प्रणाली में यही होता है । खासतौर से इस तरह की प्रतिक्रियावादी मतलब भावनाओं को व्यक्त करना यह सदन को अपमानित करने जैसा है । किसी जात का वर्ग या खास जाति का नाम लेकर और दलित का नाम लेकर महोदय, आसन सदन, पूरा बिहार और पूरा देश अवगत है कि इसी सदन में पिछले सात दशक अधिक से,

मतलब 70 वर्षों से अधिक दलित का बेटा जिस कॉम्यूनिटी का नाम लिया उन्होंने, उसका बेटा सदन का सदस्य होकर पिछले 70-75 वर्षों से इस सदन में आते रहे हैं और अपनी आवाज बा-अदब बुलन्द माने कि किसी के आवाज से कम नहीं, उतनी बुलन्द आवाज में जनता के हक की बात करते रहे हैं । फिर इस तरीके से आसन को कटघरे में लाकर के पूरे संसदीय जो प्रणाली या हमारी जो विरासत है, उसको कलंकित करना कि 50 साल पहले वाला व्यवहार किया जा रहा है । आप 50 साल की बात कर रहे हैं, यहां तो 75 साल पहले से इस सदन में दलित या किसी कॉम्यूनिटी के लोग यहां आते रहे हैं और अपनी आवाज पूरी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पूरी निर्भीकता से इस सदन में उठाते रहे हैं, यह पूरे बिहार ने देखा है । महोदय, किसको कह दिया कि आप दलित की आवाज को बंद करना चाहते हैं । क्या आसन पर बैठा आदमी किस वर्ग से आता है, क्या वे वाकिफ नहीं थे और ये तो एन0डी0ए0 गवर्नमेंट का कमाल है कि आज आप उस आसन पर बैठे हुए हैं । यह हमलोगों के मतलब मानसिकता है कि हम चाहे दलित हों या महादलित हों, हमेशा समाज का उसको सबसे सम्मानित अंग मानते हैं और मानते रहेंगे । इनके किसी ख्याल से हमलोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता, बजट पर ही बोलियेगा ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग के समर्थन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बिहार की जनता के साथ-साथ न्याय के साथ विकास का वादा किया था, आज सभी विभागों के द्वारा विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया है । महोदय, मैं आपके माध्यम से जिनका आज विषय है जल संसाधन विभाग, आदरणीय जल संसाधन मंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय का भी हृदय

से आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य सचेतक महोदय, अभी जो तत्काल में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री महोदय हैं, आज विषय भी है, मैं श्री श्रवण कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, इसी सदन से मैं मधेपुरा बिहारीगंज विधान सभा जहां से मुझे वहां की महान जनता जनार्दन ने लगातार दूसरी बार भेजने का काम किया है अपने आशीर्वाद से, मैं बिहारीगंज विधान सभा की तमाम महान जनता का भी इस सदन से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ।

महोदय, आज जल संसाधन विभाग का बजट जो 4398 करोड़ 51 लाख 79 हजार रू0 का जो मांग आया है, मैं उस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूँ । महोदय, जल संसाधन विभाग एक ऐसा विभाग है, जोकि किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है । अभी हमारे बहुत साथी बोल रहे थे नहर प्रणाली के बारे में, अभी वे सब चले गये । वर्ष 2008 में जो बाढ़ की प्रलयकारी विभीषिका आयी थी, जो कि हमलोगों की तरफ ज्यादा थी, कोसी में और मात्र सब नहर, जितनी भी नहर प्रणाली थी, सब अस्त-व्यस्त, क्षतिग्रस्त हो गयी थी । मात्र 2-4 साल के अन्दर सभी नहर प्रणाली का काम जल संसाधन विभाग से जोड़ा गया और नहर प्रणाली को चालू किया गया, जिससे किसान भाइयों की खेती, जल संसाधन विभाग की नहर प्रणाली के द्वारा ही हमलोगों के तरफ ज्यादा होती है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है । इसकी सुविधा बढ़ाने हेतु बड़ी योजनाओं के साथ-साथ छोटी योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन कराया जा रहा है । महोदय, आज सात निश्चय-2 पहले सात निश्चय था, सात निश्चय-2 जब बीच में सरकार बनी, उसमें जो निर्णय लिया गया, उस अभियान के अन्तर्गत सरकार द्वारा हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का निश्चय किया गया है । इसके तहत जल संसाधन विभाग के नेतृत्व में लगभग सभी ग्राम टोलों में संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर योजनाओं का चयन किया गया है । इसमें किसानों के द्वारा उनका भी मंतव्य लिया गया है । ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग के द्वारा

भी क्रियान्वित हो रहा है । दोनों विभागों का सहयोग प्राप्त हुआ है । योजनाओं के चयन में किसानों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। मैं अभी तुरंत उसपर भी बोला हूँ । इस अग्रणी पहल का उद्देश्य सभी गांवों में और असिंचित खेतों को पानी की उपलब्धता कराना ही जल संसाधन विभाग का मुख्य काम है । महोदय, दक्षिण बिहार के गया, बोधगया, राजगीर एवं नवादा शहरों की बढ़ती जनसंख्या पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अतिमहत्व स्थान होने एवं भूगर्भ जल के गिरते स्तर के कारण इन शहरों में पर्याप्त जल की आवश्यकता थी, इस कमी को दूर करने हेतु मानसून अवधि के अधिशेष जल को गंगा नदी से उद्भव कर पाईप लाईन के माध्यम से इन शहरों को जलापूर्ति की महत्वकांक्षी योजना गंगा जल आपूर्ति योजना को पूर्ण कर दिया गया है । यह बहुत ही बड़ा काम हुआ है जो कि कभी सोचा नहीं गया था । राज्य की इस तरह की पहली योजना है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी के चिंतन का ही यह फल है । महोदय, गया, बोधगया, राजगीर, नवादा के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनलोगों को गंगा जल प्राप्त होगा । आज उनका सपना पूरा किया गया, आज हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी के पहल से, उनके चिंतन से आज गंगा जल का दर्शन वहां के लोग कर रहे हैं और गंगा जल ग्रहण कर रहे हैं । महोदय, जल-जीवन-हरियाली के तहत भी इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में ही हो रहा है । महोदय, एक बहुत बड़ी बात है कि हाथीदह के निकट इन्टेकवेल सह पम्प हाउस, राजगीर के निकट गंगा जी राजगीर जलाशय का निर्माण, राजगीर डिटेंसन टैंक सह पम्प हाउस, राजगीर शहर में पेय जलापूर्ति हेतु जलशोधन संयंत्र का निर्माण, गया जिला के तेतर पंचायत में गंगाजी जलाशय का निर्माण किया गया है ।

..... क्रमशः ....

टर्न-21/शंभु/20.02.24

श्री निरंजन मेहता : क्रमशः नवम्बर 2022 से गया, बोध गया एवं राजगीर शहरों को गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है । दिसम्बर, 2023 से ही नवादा शहर में भी गंगा जल

की आपूर्ति की जा रही है । महोदय, एक नयी बात और है तत्काल हुआ है जो कि बेगुसराय स्थित राजेन्द्र सेतु एवं निर्माणाधीन छः लेन सेतु के बीच गंगा नदी के बायें तट पर उपलब्ध भूभाग का ऊंचीकरण करते हुए इसके नदी भाग में लगभग 550 मीटर की लंबाई में सिमरिया घाट धाम निर्माण एवं इसके सौंदर्यीकरण कार्य तीव्र गति से हो रहा है । गंगा आरती हेतु विनिर्दिष्ट स्थल स्नान घाट एवं चेंजिंग रूम घाट के समानांतर स्नान हेतु सुरक्षा व्यवस्था एवं लैंड स्केपिंग शौचालय परिसर, धर्मशाला परिसर एवं प्रशासनिक भवन का भी कार्य तीव्र गति से हो रहा है । इन कार्यों के संपन्न होने से सिमरिया घाट एक प्रमुख धार्मिक स्थल पर्यटन के रूप में उभरेगा । महोदय, पश्चिमी कोशी एवं साथ ही वहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे । पश्चिमी कोशी नहर परियोजना में भी वहां के कृषक के लिए काम किये जा रहे हैं । महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू के ही कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि फल्गू नदी पर गया जी डैम विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आधुनिकतम तकनीक से रबर डैम योजना- गया जी डैम का कार्यान्वयन किया गया है । इससे विष्णुपद मंदिर के सामने 500 मीटर की लंबाई में वर्षभर कम से कम दो फीट गहरा पानी उपलब्ध रहेगा और उसका लाभ आज वहां मिल रहा है । इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप पूरे वर्ष जल की उपलब्धता से श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न माध्यमों से अपनी प्रसन्नता जाहिर की है । पितृपक्ष महासंगम 2023 के दौरान लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किया गया है । फल्गू नदी के उपर निर्मित सीता पुल के श्रद्धालुओं को सीता कुण्ड की तरफ जाने में काफी आसानी हो गयी है । गया जी डैम, रबर डैम को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों पर्यटक वहां पर आते रहते हैं । महोदय, वर्ष 2023-24 खरीफ अवधि में जल संसाधन विभाग द्वारा अनेक नहरों के अंतिम छोड़ तक पानी उपलब्ध कराया गया तथा विगत वर्षों की तुलना में नहरों में अधिक जलश्राव प्रवाहित किया गया जिससे खरीफ अवधि में सुखाड़ की विषम परिस्थिति में कृषकों को सिंचाई की सुविधा दी गयी । महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू की असीम कृपा से हमलोगों

के यहां सुपौल जिला अन्तर्गत वीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भौतिकीय प्रतिमान केन्द्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना अंतिम चरण में है । यह केन्द्र सी0डब्लू0पी0आर0एस0 पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अति आधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा । महोदय, जल संसाधन विभाग बिहार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई संरचना को मजबूत करता है क्योंकि राज्य को कम और अनियमित वर्षा का सामना करना पड़ता है । इसके साथ-साथ सूखा और बाढ़ भी परेशान करता है । फसलों की उपज बढ़ाना, किसानों की आजीविका में सुधार लाना और सूखा तथा बाढ़ के मामले में अनुकूलता बढ़ाना जल संसाधन विभाग का पुनीत कर्त्तव्य है । जल संसाधन विभाग कृषि विभाग के लिए भविष्य में पानी की सुस्थिरता सुनिश्चित करने की कुंजी है । महोदय, आज के इस व्यय विवरणी में 9 विभाग गिलोटिन में है । जिसमें सभी विभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में कार्य हो रहा है । महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग तथा शिक्षा विभाग पर कुछ शब्द रखना चाहूंगा । महोदय, आज ग्रामीण कार्य विभाग इतना काम ग्रामीण कार्य विभाग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में हुआ है । एम0एल0ए0 का सबसे पहला काम है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ को लागू करना जिस पंचायत में, जिस गांव में, जिस टोला में कनेक्टीविटी नहीं है । एम0एल0ए0 चाहता है तो रोड होता है एम0एल0ए0 नहीं चाहेगा तो रोड नहीं होगा । आज उस कार्य को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में लगभग पूरा कर लिया गया है । मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ अब हमको लगता है बहुत जगह मिलता नहीं है, अब चौड़ीकरण की तरफ बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा । आज 3054 एम0आर0 में उसको 2018 की अनुरक्षण नीति में बदलाव करके पहले गांव का रोड कमजोर होता था उसकी मजबूतीकरण के लिए 2018 में अनुरक्षण नीति को सुदृढ़ बनाकर उस रोड के मजबूतीकरण के लिए भी नियम लाया गया है जिसपर कि आज गांव की रोड भी सुंदर सड़कें मजबूत सड़कें बन रही है । महोदय, आज गांव में चौड़ीकरण भी हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि किसी भी जिले से पटना में 6 घंटे में लोग आवे और वह सबका

सपना पूरा हो गया है और अब 5 घंटे की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट है वह भी पूरा हो जायेगा । अब कहीं-कहीं तो पूरा हो गया है, 7 घंटा में हम ही आते थे अभी साढ़े 4 घंटा में, 5 घंटा में पटना आ रहे हैं । शिक्षा पर हम बोलेंगे कि पहले क्या स्थिति थी । अभी हमारे विपक्ष के लोग बहुत भाषण देकर चले गये हैं, लेकिन मैं उनकी ओर नहीं जाऊंगा- भवन नहीं था, छात्र छात्रा की उपस्थिति नहीं थी । आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा क्या-क्या हुआ राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर कमजोर वर्ग के बच्चे बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है तथा इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। डी0बी0टी0 के माध्यम से शिक्षा से संबंधित योजनाओं की राशि का बच्चों को हस्तांतरण कराना, बालिका पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य छात्रवृति, प्रीमैट्रिक, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति आदि योजनाओं की राशि वितरित की जा रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले बच्चे बच्चियों की उपस्थिति स्कूलों में नगण्य थी और आज क्या उपस्थिति हो रही है कि जगह नहीं मिल रहा है, भवनहीन था । साइकिल देने पर आज हमारी गांव की बेटी स्कूल जाती है और जिसको कभी सोचा नहीं था वह भी स्कूल में हरेक पंचायत में हाइस्कूल का प्लस टू का निर्माण कराया गया और गांव के लोग पंचायत के लोग उसी में पढ़ते हैं और हरेक काम समयानुसार हो रहा है । मैं अंत में आज के व्यय विवरणी में मांग संख्या-49, 21, 37, 35, 31, 43, 24, 25, 18 में जो बजट की मांग की गयी है । मैं उस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूँ तथा सरकार के भी पूरे बजट का समर्थन करता हूँ । कुछ क्षेत्रीय बातें है मैं माननीय मंत्री महोदय से बाद में मिलकर करा लूंगा । बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय एन0डी0ए0 सरकार ।

टर्न–22/पुलकित/20.02.2024

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी ।

श्रीमती ज्योति देवी : धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंधित विषयों पर आपकी अनुमति से मैं सरकार के बजट के पक्ष में, उपरोक्त विषयों पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं अपने दल के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी साहब एवं दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 संतोष कुमार सुमन जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया । साथ ही, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ और सदैव उनके आयुष्मान रहने की कामना करती हूँ । एन0डी0ए0 गठबंधन वाली सरकार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करेगी, यह मैं कामना करती हूँ । महोदय, जल संसाधन विभाग के तहत गया जिला में बड़े पैमाने पर गंगा जल लाया गया, यह काफी सराहनीय कार्य है और देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे विश्व के लोग इसकी सराहना कर रहे हैं । आज मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से यह कहना चाहती हूं कि जल संसाधन विभाग के तहत सरकार की अन्य हरेक विभागों में अनगिनत उपलब्धियां है, उसे मैं लिखकर लाई हूँ, इसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए । लेकिन कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं, अगर थोड़ा बहुत एक–डेढ़ मिनट बढ़ जाए तो मैं आपसे समय मांगने का आग्रह करती हूँ क्योंकि यह विषय बहुत ही जरूरी है ।

महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखण्ड बाराचट्टी में बाराचट्टी में बरण्डी बियर परियोजना को धरती पर उतारने की मांग की जाती रही है । इस दिशा में विभाग ने उसके निर्माण हेतु सभी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर लिया है, अब सिर्फ विभाग को इसकी स्वीकृति देनी रह गयी है । मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस परियोजना पर धरती पर उतार दिया जाए ताकि इस क्षेत्र के हजारों

किसानों को लाभ मिल सके । इमामगंज में डारो बांध की भी मांग की गयी है । इसकी भी वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं, मैं इसे भी बनाने की मांग करती हूँ ।

महोदय, जल संसाधन विभाग का जो वर्ष 2024-25 के लिए बजट बना है और इसके तहत जो-जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अत्यंत सराहनीय है । इस बजट में जल-जीवन-हरियाली अभियान को निरंतर जारी रखने एवं नदियों को जोड़ने की योजना एवं मृत नदियों को पुनजीर्वित करने की बात कही गयी है, वह और भी सराहनीय है ।

महोदय, शिक्षा विभाग के तहत कहना है कि आधारभूत संरचना के तहत क्षेत्र में जो छात्रों एवं शिक्षकों की सुविधा के लिए भवन बनाये जा रहे हैं, सरकार का यह अच्छा कदम है । महोदय, मैं इसमें सिर्फ जोड़ना यही चाहती हूँ कि भवन निर्माण विभाग कार्य संवेदक पर छोड़ देते हैं । इसकी तकनीकी कार्य की निगरानी बहुत ही कम देखी जाती है, इसके निर्माण में गुणवत्ता का अभाव होता है । विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है किंतु अभी भी विषयवार एवं आवश्यक विषय से संबंधित शिक्षकों का अभाव है जैसे- प्रखण्ड बाराचट्टी अंतर्गत सुलेबट्टा उच्च विद्यालय में कुल नामांकित 1715 बच्चे हैं, कुल शिक्षकों की संख्या- 23 हैं, किंतु केमेस्ट्री, जिओग्राफी, हिन्दी, मैथमेटिक्स एवं गृह विज्ञान विषयों के प्लस-टू में शिक्षक बहाल नहीं हुए हैं । 2013 से 2017 तक जितने भी छात्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राज्य से बाहर शिक्षा अध्ययन जाकर शिक्षा ग्रहण किए हैं, उन सभी छात्रों एवं कॉलेजों को अभी तक देय राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है जबकि भुगतान हेतु सारी प्रक्रिया पूरी कर कॉलेजों एवं छात्रों ने विभाग को समर्पित कर दिया है । छात्रों एवं कॉलेजों का उत्साह बढ़ाने हेतु भुगतान में शीघ्रता लाने की कृपा की जाए ।

महोदय, सरकार का यह भी संकल्प है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च विद्यालय की स्थापना जो लगभग पूर्ण कर ली गयी है, अति सराहनीय कार्य है । किंतु मेरे विधान सभा क्षेत्र बाराचट्टी का प्रखण्ड- मोहनपुर एवं बाराचट्टी की भौगोलिक बनावट अलग है । अधिकांश हिस्सा जंगली-पहाड़ी एवं दुर्गम रास्तों से

भरा है । जैसे- प्रखण्ड- मोहनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत- केवला, अमकोला तथा लखैयपुर में एक-एक उच्च विद्यालय स्थापित है, किंतु इन तीनों के बीच के भाग में कोई उच्च विद्यालय नहीं है, जिससे लगभग 20-30 गांव से अधिक है । यहां के बच्चे-बच्चियों को इस स्थल से उच्च शिक्षा पाने के लिए किसी भी दिशा में 5 से 6 किलोमीटर जाना होता है और पूरा रास्ता जंगली और सुनसान रहता है । इस क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं । सरकार से आग्रह है कि ग्राम पंचायत- लखैयपुर के ग्राम- मंझौली में एक उच्च विद्यालय की स्थापना कर दी जाए ।

महोदय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में सरकार से अनुरोध है कि इस विभाग में बहाली में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की कृपा की जाए ।

महोदय, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनम्रतापूर्वक कहना है कि बड़े पैमाने पर बिहार में अतिथि शिक्षकों ने वर्षों तक अपनी सेवा देकर अभियंत्रण महाविद्यालयों की साख बचाई है, किंतु नियमित शिक्षकों की बहाली हो जाने के उपरांत लगभग सभी अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है, इन्हें भी समायोजित करने की कृपा की जाए ।

महोदय, गृह विभाग से जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं, पुलिस भवन बन रहे हैं, थाना भवन उनकी किसी प्रकार से कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बिल्डिंग बन रही है उसका शिलान्यास थाना प्रभारी करते हैं, इस पर भी सोचने, विचार करने की बात है । राज्य में अंगरक्षक बड़े पैमाने पर हम सभी की सेवा करते हैं, उनको वर्ष 2019 से कोई टी0ए0 वगैरह नहीं मिल रहा है उसके लिए लोग बहुत परेशानी में है, इसको भी देने की कृपा की जाए ।

महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग - मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि राज्य में बड़े पैमाने पर पुल सड़कों का निर्माण कराया है । जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास संभव हुआ है, जैसे पठन-पाठन और लोगों को रोजमर्रा की, मार्केटिंग की सुविधा मिली है, यह सराहनीय कार्य है । इससे जुड़े हुए हमारे यहां सामने बैठे हैं

प्रधान सचिव महोदय, इनसे भी मैं काफी प्रभावित हूँ । जो भी काम लाते हैं सरल तरीके से हम सब की बात सुनते हैं और काम करते हैं, इन्हें भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ । महोदय, इसमें मेरा कहना यही है कि मेरा जंगली-पहाड़ क्षेत्र होने के कारण बड़े पैमाने पर रोड की स्वीकृति तो मिली है, परंतु जगंल विभाग एक किलोमीटर, दो किलोमीटर पड़ जाने से जंगली क्षेत्र में पूर्ण रोड एन0ओ0सी0 के अभाव में नहीं बनायी जा रही है । इसकी भी एन0ओ0सी0 लेने का कोई सरल तरीका अपनाया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन यह कहना चाहती हूँ कि अभी जो भी हमारे विरोधी भाई कह रहे थे कि सरकार ने कुछ नहीं किया । हमने नौकरी बांटी, मैं यह कहना चाहती हूँ अपने भाइयों से अगर कहीं से भी वे सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि किसी कार्य के लिए, कोई भी कार्य होता है या कोई भी नौकरियां मिलती हैं उसका पूर्ण श्रेय राज्य सरकार को जाता है और राज्य के मुखिया को जाता है इसलिए ये कभी भी ऐसा नहीं करे कि यह हमने किया है, हमने किया है । सरकार बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है और जनता भी इसको समझ रही है । मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि अगर ये उपलब्धि बता देना चाहते हैं तो उस समय की उपलब्धि बता दें जब उस समय लोग कहते थे कि रोड है कि गड्ढा है, गड्ढा है कि रोड है । इस स्थिति को वे समझें और लोगों को बरगलाने का काम न करें, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ । मैंने ज्यादा समय लिया इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद और अध्यक्ष महोदय, अभी आसन पर नहीं है लेकिन उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ । मैं नई टीम से उम्मीद करती हूँ कि यह एन0डी0ए0 गठबंधन की टीम बिहार को कि और तरक्की करके ऊपर ले जाएं । इसी आशा के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरी : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा लाये गये जल संसाधन विभाग के संबंध में 4398,51,79,000/- (चार हजार तीन सौ अठानवे करोड़ इक्यावन लाख उनासी हजार) रुपये की मांग

के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । इसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी एवं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी फारबिसगंज विधान सभा की जनता का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने दूसरी बार इस सदन में भेजने का काम किया । मैं जनक जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन जल के वे स्त्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं । अधिकांशतः लोगों को ताजा जल की आवश्यकता होती है । जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है । उपाध्यक्ष महोदय, पृथ्वी पर 97 प्रतिशत पानी खारा पाया जाता है और केवल 3 प्रतिशत ताजा पानी है । इसका दो-तिहाई से थोड़ा अधिक हिस्सा ग्लेशियरों और घनी बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, पृथ्वी पर उपस्थित जल अत्यंत कम और सीमित मात्रा में है । जल के प्राकृतिक स्त्रोतों जैसे की नदी, तालाब, हिमनाद, वर्षा और भूमिजल आता है जिसका बेहतरीन रख-रखाव एवं संरक्षण अति आवश्यक है । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले कई सालों से बिहार सरकार जल का संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सतत प्रयास कर रही है ।

(क्रमशः)

टर्न-23/अभिनीत/20.02.2024

..क्रमशः..

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, एक बेहतर जल प्रबंधन को लेकर एन0डी0ए0 सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी एवं माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी के द्वारा कई योजनाओं पर ठोस कदम उठाये जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जल और हरियाली पृथ्वी के गहने हैं । एक सुन्दर वसुन्धरा के लिए पहाड़ों, कंद्राओं सहित वन के आच्छादित धरती एवं

पर्याप्त जल की नितांत आवश्यकता है । मानव सहित पृथ्वी पर अन्य जीवों का भी जल के बिना जीवन संभव नहीं है । यूं कहें कि जल एवं जीवन की संरचना में जल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है । इस दिशा में जल संसाधन विभाग प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधन, जल संपदा के अभीष्टतम सदुपयोग के लिए संकल्पित और सतत प्रयासरत है । उपाध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा जल संसाधन, जल प्रबंधन की नई एवं आधुनिकतम तकनीकों का सफलतापूर्वक सदुपयोग करते हुए राज्यहित में कई अच्छे कार्य किये जा रहे हैं और किये जाते रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमलोग उत्तरी बिहार से आते हैं । प्रत्येक साल उत्तरी बिहार में बाढ़ की विभीषिका से हमलोग जूझते रहते हैं । उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है जिसका मुख्य केंद्र बिन्दु नेपाल होता है । नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं, यदि इन नदियों का बिहार सरकार उच्च स्तरीय सर्वे कराकर उक्त नदियों पर डैम या अन्य उपायों से नियंत्रित करे तो बाढ़ की विभीषिका से हम बच सकते हैं एवं पूरे उत्तर बिहार में सड़कों, नहरों, पुलों के साथ जान-माल की हानि से भी हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में एन0डी0ए0 सरकार के द्वारा नहरों के विकास में काफी काम हुआ है परंतु संवेदकों की लापरवाही के कारण अभी भी पूरे बिहार सहित हमारे अररिया जिला के ए0बी0सी0 कैनाल नहर के गाद की जो सफाई करनी थी अभी भी नहीं की गयी है, जिससे माइनरों एवं चैनलों का अवैध अतिक्रमण भी जलप्रवाह में बाधा बनी हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग में कुछ पुराने नियमों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है । हमलोगों को, पहले जो देखा जाता था कि जितने भी नहर और चैनल बनाये गये थे उनमें दो किलोमीटर के रेडियस में पुल का निर्माण कराया गया था । छोटे-छोटे पुल हुआ करते थे और उन पुलों से किसान लोग अपने खेत, खलिहानों से अपना उपज लाया-जाया करते थे लेकिन आज वस्तुस्थिति बिल्कुल बदल गयी है । अब नहरों के किनारे बसावटों की जो संख्या है, एक बहुत बड़ी बसावट हर जगह, हर एक-एक किलोमीटर पर नहर के

अगल-बगल में, इर्द-गिर्द लोगों का बसावट हो गया है, खासकर गांवों में, तो अब जो नियम था कि दो किलोमीटर के अंतराल में ही छोटे-छोटे पुल दिए जायं समपार पुल, तो वैसी जगहों पर अब चौड़े पुल की जरूरत है । चूंकि गाड़ियों का परिचालन भी हो रहा है, मोटरसाइकिलें भी जा रही हैं, उसी में बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर भी जा रही हैं और किसान अपने माल को भी ला रहे हैं । छात्र-छात्राएं पढ़ने भी जा रहे हैं, तो जगह-जगह पर, ऐसे सभी जगहों को चिन्हित करके जहां बसावट हो वहां पर पुल का निर्माण कराने की हमलोग सरकार से आशा रखते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके संदर्भ में हमारे ही विधान सभा में तीन-चार जगह ऐसे हैं जहां पुल बनाना नहर पर अति आवश्यक है, जिसमें मंझुआ पंचायत के गोपालपुर ए0बी0सी0 नहर पर, कोठीहाट चौक से लाल बहादुर चौक जाने वाले मार्ग में ए0बी0सी0 नहर पर, ढ़ोलबज्जा से मुसहरी वार्ड सं0-3 खेरका जाने वाले मार्ग में ए0बी0सी0 नहर पर, ऐसी बड़ी संख्या में लोग उन नहरों के बगल में बसावट अपना बनाये हुए हैं और काफी समय से लोग पुल की मांग कर रहे हैं । मैं पिछले आठ साल से लगातार विधान सभा में इस मामले को लाया हूं लेकिन अब तक उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि इन तीनो-चारों जगहों पर जल संसाधन विभाग तरीके से जांच करावाकर उसमें पुल निर्माण का कार्य कराये ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहां उत्तर बिहार में महानंदा फेज-3 का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण की प्रक्रिया में जो काम होना था वह अभी तक लंबित है । जो चैनल बनना था उसका सर्वे हो चुका है, बहुत जगह जो वहां गये थे, अमीन लोग गये थे उसका नापी भी किये हुए हैं, कहां त्रुटि हो रही है कि अबतक महानंदा फेज-3 का काम अधर में पड़ा हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो बनना है, महानंदा बेसिन का जो निर्माण होना है उसमें परमान नदी को ही मापदंड रखा गया है । परमान नदी के दोनों तरफ के जो घाट हैं वे काफी नजदीक पड़ते हैं और उसके बगल में काफी बसावट हैं । ऐसे बहुत सारे बसावट हैं...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अगर उसका सही तरीके से सर्वे नहीं कराया गया तो वे सारे गांव, गांव के गांव उस महानंदा बेसिन परियोजना के अंतर्गत आ जायेंगे और गांव, शहर और जो छोटे-छोटे जो कसबे हैं वे सभी उस महानंदा फेज-3 के सर्वे के अनुसार उसमें समाहित हो जायेंगे । इसलिए कुछ गांव हैं उसके संबंध में..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य विद्या सागर केशरी जी, अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : हमलोग जानकारी देना चाहेंगे..

अध्यक्ष : केशरी जी, अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : जी महोदय । बस तुरंत कंक्लूड कर देते हैं । महोदय, इसमें हमारे यहां परमान नदी जो टेढ़ी-मेढ़ी होकर चलती है उसको सीधी कराने की जरूरत है और उसमें अमहारा बाजार, खैरका बजार, घोड़ाघाट बजार, रमैय बाजार, खबासपुर बाजार, गुरमी बाजार गांव बच सकता है यदि हम उस सर्पिली नदी को सीधा कराकर महानंदा बेसिन फेज-3 का काम करायें ।

अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि इसमें ग्रामीण कार्य विभाग के भी बहुत सारे काम को करना है, तो ग्रामीण कार्य विभाग को लेकर भी मैं अपने क्षेत्र की समस्या को रखना चाहूंगा, चूंकि समय कम है । हमारे यहां मंझुआ पंचायत के खमकोल घाट पर और रमैय पंचायत के डहरा घाट पर काफी समय से हमलोग पुल के निर्माण के लिए, परमान नदी पर पुल के निर्माण की बात को रखते आये हैं लेकिन आजतक उस स्थान पर पुल का निर्माण नहीं हो सका, इसलिए हम श्रीमान से चाहेंगे कि उसका भी ख्याल रखते हुए उन सभी स्थानों पर पुल का निर्माण करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे गार्जियन हैं इसलिए हम दो मिनट का समय और लेंगे..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसलिए हम कह रहे हैं कि समाप्त कीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, समय कम रहने के कारण जल्दी बोलना पड़ता है । महोदय, हमारे यहां कुछ लोहे के पुल हैं जो बिल्कुल ध्वस्त होने की स्थिति में हैं । वैसे

पुल कॉलेज चौक से हरिपुर, एन0एच0-57 से पोठिया, जोगबनी से पुरानी जोगबनी, सभी स्थानों पर लोहे के पुल के बदले उच्च स्तरीय पुल बनाने का काम श्रीमान हम सदन के माध्यम से विभाग को कहना चाहेंगे । इसी प्रकार से..

अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद ।

माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह । माननीय सदस्य, अपना पक्ष रखें ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, बस एक शिक्षा विभाग से संदर्भित है कि हमारे यहां जो विद्यालय हैं, जो कुछ विद्यालय हैं उसमें..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी को लिखकर दे दीजिएगा । अब समय नहीं है, सरकार को भी जवाब देना है ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, एक मिनट सिर्फ समय दे दिया जाय । जो उच्च विद्यालय और उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं, पूरे बिहार का मामला है, उन सभी विद्यालयों में पठन-पाठन अच्छे तरीके से हो, तो उसमें चाहरदीवारी का काम करवा दिया जाय और एक बड़ा सा गेट लगवा दिया जाय । चूंकि विद्यालय परिसर में किसी प्रकार से अनधिकृत रूप से कोई प्रवेश न करे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह जी ।

टर्न-24/हेमन्त/20.02.2024

श्री राज कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फिर से एक बार सदन की ओर से बोलने का मौका मिला है, मेरी बारी तो नहीं थी, अचानक ही, मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं अपनी सरकार का पक्ष रख सकूं । आज मैं भी इस कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपना पक्ष रख रहा हूं और जो मांग आयी है उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं । सिंचाई विभाग का जो 4,398 करोड़ का बजट आया है, वह बिल्कुल स्वागत योग्य है और कुछ चीजें जो इसमें हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । जल-जीवन-हरियाली की बात इसमें की गयी है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही, जो मानसून के समय में अधिशेष जल होता है, गंगा के बहाव में

और जिसके कारण बाढ़ जैसी समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए इतनी बड़ी सोच रखना कि उस जल को अन्य उपयोग में ले जाकर उसको रबर डैम के माध्यम से फल्गू नदी तक पहुंचाना और पेयजल की आपूर्ति गया, बोधगया, नवादा, राजगीर जैसे जिलों में करवाना । यह बहुत ही अग्रणी सोच का प्रतीक है और ऐसी सोच का प्रतीक है कि आज बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है । माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे अभिभावक स्वरूप भी हैं और मटिहानी से काफी संबंध भी रखते हैं । मैंने कल भी कहा था कि 2021 में जब बाढ़ आयी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मटिहानी में दौरा हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहां के लोगों से वादा किया था और उसी दिन यह तय हुआ था विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा कि एक रिंग बांध का निर्माण किया जायेगा ताकि बाढ़ की विभीषिका जो गंगा के किनारे बसे लगभग दो लाख से अधिक की आबादी के लोगों को झेलनी पड़ती है, उससे स्थायी निजात मिल जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, बार-बार मैंने कई माध्यमों से किया है कि थर्मल से लेकर और मटिहानी ढाला तक रिंग बांध के निर्माण के कार्य को अब निश्चित रूप से अमलीजामा पहनाने का काम करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया, उस वादे को भी पूरा किया जा सके और हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के आगे अपनी सरकार की उपलब्धि को बता सकें ।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अक्सर मुझे बोलने के लिए कहा जाता है, मेरी तैयारी कम होती है और अचानक ही बोलने के लिए कहा जाता है ।

अध्यक्ष : कम ही बोलना है ।

श्री राज कुमार सिंह : इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा एक शेर के माध्यम से, चूंकि आप भी शेर का काफी शौक रखते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि-

''ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाय मुझे,
कोई मुश्किल घड़ी हो, तो चुना जाय मुझे,

सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी,

मेरी आवाज से आगे भी सुना जाय मुझे ।''

अध्यक्ष : वह समझ गये कि क्या कहना चाहते हैं आप । धन्यवाद । अब समाप्त करिये ।

श्री राज कुमार सिंह : और अंत में, चूंकि हम सब लोग यहां पर अटल जी को मानने वाले लोग हैं और हमारे नेता भी अटल जी का काफी सम्मान करते हैं और हम सब लोगों को बिहार के विकास में साथ-साथ चलना पड़ेगा, कदम मिलाकर चलना पड़ेगा । तो अटल जी की एक कविता से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि-

''सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ,

प्रगति चिरन्तर कैसा इति अथ,

सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,

असफल, सफल समान मनोरथ,

जीवन को शत-शत समान आहुति में,

जलना होगा, गलना होगा,

कदम मिलाकर चलना होगा ।''

बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार रौशन जी । आपके पास केवल चार मिनट समय है ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस सदन के माध्यम से मैं आपको बधाई देता हूं । क्योंकि आपके मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करने का पहले भी मौका मिला है और पुनः मैं बधाई देता हूं । बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता और सचेतक को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने पातेपुर विधान सभा की उन तमाम जनता को जिनके आशीर्वाद से एक दलित का बेटा सदन में आकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग के बजट पर सरकार के पक्ष में मुझे बात रखने के लिए कहा गया है । जल संसाधन के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे बिहार के अंदर काम हो रहा है । यह बजट केवल बजट ही नहीं है, यह बजट 4398,51,79000 रुपये का शुभ-शुभ बजट है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि कितना सुंदर बजट आप लाये हैं । इस बजट के माध्यम से पूरे बिहार के अंदर जब बाढ़ की विभीषिका आती है, तो उस समय एहसास होता है कि इस बजट की कितनी आवश्यकता है । लेकिन हमें लग रहा है, जो विपक्ष के साथी हैं, जिस प्रकार से उनका उजड़ा हुआ चमन है और पूरा का पूरा फील्ड खाली करके, जनता के हित की रक्षा उनके ध्यान में नहीं रही और सदन से भाग खड़ा हुए हैं ऐसी दुर्भाग्य की भावना लेकर, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट है, उस बजट में आम जनता की जो रक्षा होगी बाढ़ के समय, इसके लिए बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । वहीं शिक्षा विभाग पर भी आज बजट है । अभी हमारे साथी चले गये । बोल रहे थे, 90 के दशक को याद करा रहे थे । 90 के दशक में उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया था । 90 के दशक में जिस प्रकार से पूरे बिहार के अंदर एक चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार के दलितों का अपमान किया जा रहा था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनको दलित के बेटा के, अति पिछड़ा और गरीब के बेटा की पढ़ाई से मतलब नहीं था, उन्हें केवल चरवाहा विद्यालय खोलने से मतलब था । वह समझते थे कि बिहार के अंदर जो गरीब है, जो दलित है, जो महादलित है, जो अतिपिछड़ा समाज से आते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है । उन्हें लग रहा था कि केवल चरवाहा विद्यालय खोलकर, इसको केवल दस्तखत करवाना सिखा दो और इसी पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे । ऐसे लोग जो अपने बाल-बच्चे को नहीं पढ़ा पाये । बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वह तो स्वयं आठवीं पास हैं । उनके पिता ने चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार के दलितों का अपमान करने का काम किया और आज सदन के अंदर विपक्ष के लोग उसी के लिए पीठ थपथपा रहे थे । दलितों को जो सम्मान, आज बिहार सरकार ने, बिहार

के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज मिला है और एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में जब-जब सरकार रही हमेशा शिक्षा पर, तब शिक्षा की क्या स्थिति थी, 90 का दशक याद करा रहे थे । चरवाहा विद्यालय तो उन्होंने खोल दिया था, कहीं पर भवन दिखाई नहीं दे रहा था ।

अध्यक्ष : अब कन्क्लूड कीजिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, आप भी विधायक हैं, हम सभी माननीय विधायक हैं । अपने विधान सभा क्षेत्र जाते थे, वहीं चरवाहा विद्यालय पेड़ के नीचे दिखायी देता था । कहीं भवन नहीं था, कहीं शौचालय नहीं था, लेकिन आज मैं माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे बिहार के अन्दर सभी विधान सभा में स्कूलों में एक-एक भवन दिखायी दे रहा है और भवन निर्माण हो गया है, शिक्षकों की बहाली हो गयी है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है । भवन बन गया था, वहां विद्यालय अवस्थित नहीं हो रहा था, लेकिन बिहार सरकार के सही निर्णय के कारण आज विद्यालय में टीचर भी हैं, भवन भी है और विद्यार्थी की उपस्थिति भी आज प्रचुर मात्रा में रहती है । यही एनडीए की सरकार में पढ़ाई की गुणवत्ता का स्तर है ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । समाप्त कीजिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमें लग रहा है कि हम अंतिम वक्ता हैं । इसलिए थोड़ा-सा समय, आज खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग का भी बजट है ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर भी है ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : गरीबों की चिंता उन्हें नहीं है, दलितों की चिंता उन्हें नहीं है । आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों के घर में राशन पहुंचाया जा रहा है, मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है । उनका दर्द उन्हें नहीं है । उनको लग रहा है कि बिहार के गरीबों को अनाज पहुंचना, दलितों को, अतिपिछड़ों को, चाहे किसी भी समाज के गरीब हों उनके घर में अनाज पहुंच रहा है, तो विपक्ष के लोगों को नहीं सुहा रहा

है, आज सदन छोड़कर भागने को उतारू हैं । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीबों के यहां अनाज पहुंचाकर सबसे बड़ा काम किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । लखेन्द्र जी, अब समाप्त कीजिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से जिस प्रकार पूरे बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया है । आज कहीं दूर से भी हम पांच घंटे के अंदर पातेपुर से और पूरे बिहार में कहीं से भी पटना पहुंच जाते हैं । यही हमारी एनडीए सरकार की उपलब्धि है । इसलिए ग्रामीण विकास मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : दलितों को सम्मान जिस प्रकार बिहार के अंदर एनडीए की सरकार में मिल रहा है । यदि दलितों को सम्मान नहीं मिलता, तो आज गरीबों के घरों का निर्माण नहीं होता, घरों में शौचालय नहीं बनता, उसको मुफ्त में अनाज नहीं मिलता । माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का काम है सदन छोड़कर भाग जाना और जो बिहार का 90 का दशक याद दिला रहे थे, जो व्यक्ति पशुओं का चारा तक खा गया

(क्रमशः)

टर्न–25/धिरेन्द्र/20.02.2024

(क्रमशः)

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, जिस व्यक्ति ने हजारों–करोड़ों का घोटाला किया, वैसे व्यक्तियों को दलितों की चिंता हो रही है आज । वैसे लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को दलितों की चिंता हो रही है । सदन में उनके नेता बोल रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी को भगवान की उपाधि दे रहे थे । शर्म करना चाहिए, जिस लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों का अनाज खाया, जिसने पशु तक का अनाज खा गया, गरीबों के हक को मार कर खा गया, उसको गरीबों की चिंता क्या हो सकती है । इसलिए केवल....

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान जी । आपका केवल दो मिनट है ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, इस बजट का मैं समर्थन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कृपा के लिए बहुत शुक्रिया । मैं सरकार के मुतालबा के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ । इस वक्त चूंकि इरीगेशन का भी मैटर है और एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी हैं, इसलिए मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, आपके माध्यम से कि महानंदा नदी में सबसे अधिक कटाव है, उसके किनारे बसे हुए घरों की रक्षा के लिए बांध सुरक्षात्मक कार्य कराये जायें । 2460 प्लस 1 कोटि के मदरसों में से 877 की जाँच हो चुकी है, उसकी तनख्वाह जारी की जाय । मदरसा शिक्षकों का पेंशन जारी किया जाय । टायर-1 की तरह टायर-3 को जो डी॰एल॰एड॰ ट्रेनिंग बच्चें हैं उनको इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी जाय । आई॰सी॰टी॰ लैब इंस्ट्रक्टर को सेवा समाप्ति की चिट्ठी वापस करायी जाय । अमौर, कंजिया और विष्णुपुर हाई स्कूल में प्लस टू के मकान बनाये जाय । बिना सक्षमता परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाय । स्कूल की टाईमिंग सुबह 10 बजे से शाम 04 बजे तक करायी जाय । विकलांग एवं महिलाओं को निकटतम बहाली के लिए उपाय निकाला जाय । आर॰डब्ल्यू॰डी॰ के तहत खाड़ी, रसेली, बम्बाधार और रियादअली धार और परापूर्णियाँ में पिछले 10 साल से जो लंबित योजनाएँ हैं उनको पूर्ण करायी जाय । महोदय, कनकई नदी के सिमलबाड़ी भाट ताहीरहट बलिया में प्रस्तावित पुलों का, नंदनिया में प्रस्तावित पुलों का निर्माण कराया जाय । अमौर में बकड़ाधार पर पुल छः महीने पहले सैंक्शन हो गया है, टेंडर भी हो गया है, उसका काम शुरू करवाया दिया जाय । बायसी के अंतर्गत मथुरापुर खपड़ा में और गोटपुर खुटिया में वहाँ पर पुल की नितांत आवश्यकता है....

अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद । अब समाप्त कीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक मामला । कोच का परसराय रोड पिछले 7-8 साल से बन रहा है, उसका काम अधूरा है, यह कराया जाय और इस सदन में मैं एक बात कह कर जाउंगा कि दलित, अगड़े-पिछड़े सब भारत के संतान हैं, किसी के खिलाफ

अभद्र व्यवहार नहीं किया जाय । अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो गई है तो इसका समाधान कराया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज ही सदन में द्वितीय पाली के प्रारंभ में ही हमने आपकी इजाजत से इस सदन में जल संसाधन विभाग की माँग के रूप में 4,398 करोड़ रुपये से अधिक रुपये की माँग सदन में रखी थी और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आसन का, जिसने इस पर लगातार पिछले तीन घंटे से सदन में विमर्श कराया है । सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ लगभग एक दर्जन सदस्यों को, लगभग 12 सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे थे और मुझे खुशी है यह बात बताते हुए कि उसमें से अधिकांश माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य बातों के अलावा कुछ अपने-अपने इलाके की, जल संसाधन विभाग से संबंधित कुछ समस्याओं की तरफ इशारा किया है, कुछ माँग की है । सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो बातें उठायी हैं उसका विभाग ने और सरकार ने संज्ञान लिया है और आने वाले समय में हम जरूर उसकी पूरी छानबीन कराकर और उसमें जो भी संभव होगा उसके निदान का प्रयास हम जरूर करेंगे, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं । महोदय, अन्य लोगों ने, अन्य माननीय सदस्यों ने तो जो बातें कही, आप भी शुरू में यहाँ थे, फिर अभी आये हैं, जहाँ भी होंगे, सदन में जो विमर्श चल रहा था, आप निश्चित रूप से उससे वाकिफ होंगे । एक बात की तो प्रसन्नता विभाग को और सरकार को अवश्य है कि किसी भी माननीय सदस्य ने जो सत्ता पक्ष के हैं उन्होंने तो सरकारी नीतियों की जो इस विभाग के द्वारा अपनायी जा रही है उसकी सराहना इन्होंने तो की ही, हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने । विपक्ष के भी किसी माननीय सदस्य ने जल संसाधन विभाग की नीतियों या जो हम काम कर रहे हैं उसकी कहीं से कोई आलोचना नहीं की, यह हमारे विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है और महोदय, अब मैं कहना तो

नहीं चाहता था, जिक्र तो नहीं करना चाहता था लेकिन इसी क्रम में एक हमारे साथी डॉ॰ चन्द्र शेखर जी इस चर्चा में भाग ले रहे थे, अब पता नहीं जल संसाधन विभाग को सिर्फ उन्होंने अपनी बात रखने का एक जरिया बनाया लेकिन जो बातें उन्होंने की, आसन की तरफ से भी आप उनको इशारा कर रहे थे कि वे सारी वेदना या टीस या पीड़ा, वह हमको लगा कि उनकी सारी वेदना शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई थी, जितनी भी बातें वे कह रहे थे, अब मैं उचित नहीं मानता हूँ कि इस समय उनकी बातों का जिक्र करूं और इस क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री जी का भी नाम लेकर और मेरा भी नाम लेकर कुछ जो व्यक्तिगत वार्तालाप होती है जो विश्वास और भरोसे के आधार पर होती है, उसको भी उन्होंने उद्धृत किया जो मेरी समझ से बिल्कुल मुनासिब नहीं था । इसलिए मैं उन पर और टिप्पणी कर उनकी बातों को वजूद में लाना नहीं चाहता हूँ । उसको दरकिनार करते हुए लेकिन कुछ प्रक्रियात्मक बातें या तथ्यात्मक बातें जो उन्होंने विभाग के संबंध में और नियुक्तियों के संबंध में खासतौर से की है, उसके बारे में मैं समय बचा कर भी कुछ टिप्पणी जरूर अंत में करूंगा । पहले मैं अपने विभाग की बात कर लूँ ।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा हम सारे सदस्यों के आभारी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है । विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं अरूण शंकर जी को और विद्या सागर केशरी जी को, जिन्होंने कुछ आँकड़े, कुछ तथ्य जमा कर इस विमर्श में भाग लिये हैं और कुछ ऐसी जानकारियाँ दी हैं जो इस विभाग के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और हर नागरिक को उस बात को जाननी चाहिए और समझना चाहिए । हमारे साथी जो कह रहे थे, यह बात सही है कि इस धरती का यानी इस पृथ्वी का, हमारे सदस्य ने दो-तिहाई कहा था लेकिन दो-तिहाई से भी अधिक है, लगभग तीन-चौथाई हिस्सा 71 प्रतिशत है । धरती का 71 प्रतिशत भाग जो है वह जलमग्न है लेकिन वहीं पर यह भी बात है कि अब दुनिया के सामने कोई एक संकट जो सबसे गंभीरता से उभर कर पूरी दुनिया को प्रभावित करने जा रही है, वह जल संकट है । यह धरती की त्रासदी है कि जितना जल उपलब्ध है उसमें 97 प्रतिशत जल खारा है । तीन-चौथाई भाग

जल-ही-जल है लेकिन वह जल का 97 प्रतिशत, जितना जल पृथ्वी पर उपलब्ध है उसमें 97 प्रतिशत खारा है मतलब मानव उपयोग के लायक नहीं है । सिर्फ दो प्रतिशत जल ही उपयोग के लायक है और उसमें भी एक प्रतिशत जल ही ऐसा है जो मानव के उपयोग के लायक है । इसलिए अब यह स्थिति है और हमलोगों के लिए बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है अगर हम देखें तो हमलोग ऐतिहासिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार उतना भाग्यशाली प्रदेश नहीं है संसाधन के मामले में । हम ज्ञान, अध्यात्म की धरती भले ही रहे हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वह हमें अति अल्प मात्रा में उपलब्ध है । महोदय, हमारे पास न खान है, न खदान है, न समुद्री किनारा है, न सोना निकल रहा है, न हीरा निकल रहा है, न कोई दूसरी चीज, ऐसा माईन-मिनरल कुछ है नहीं, न समुद्री किनारा है ।

(क्रमशः)

टर्न-26/संगीता/20.02.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : बहुत सारे प्रदेश के लोग आज आगे बढ़ गए हैं, वे ईश्वरीय कृपा से बढ़े हैं । महोदय, जिनको हजारों किलोमीटर समुद्री किनारा है उनको अरबों की अकूत सामुद्रिक संपत्ति संसाधन उपलब्ध है लेकिन महोदय, जो हमारे पास एक प्राकृतिक संसाधन जो अब हम प्रचुरता से भी नहीं कह सकते हैं, कुछ दिन पहले 10-20 साल पहले तक हमलोग कह सकते थे कि हमारे यहां जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन सबसे बड़ी चिन्ता की बात जो है वह यह है कि हमारे यहां जल की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है, यह सबके चिन्ता की बात है और देखते-देखते महोदय, कि हमलोग जो कभी जलाधिक्य मतलब जो वॉटर सरप्लस एरिया कहते हैं, जल के मामले में हमलोगों के यहां पर्याप्त जल होता था और मानव जीवन के लिए जल की उपलब्धता का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैमाना स्वीकृत है, उसके हिसाब से ही प्रति व्यक्ति अगर 1700 घनमीटर जल उपलब्ध है जो सभी अवस्था में, सबलोग जानते हैं कि जल तीनों अवस्था में रहता है, पानी भी रहता है, बर्फ भी रहता है, जलवाष्प भी रहता है, बादल भी रहता है, सबमें जल

रहता है लेकिन पूरे इस जलचक्र में संपूर्ण मात्रा हमेशा निश्चित रहती है, स्थिर रहती है तीनों को मिला लीजिए तो अभी जो कुछ दिन पहले तक आजादी या उससे भी पहले हमारे यहां पर्याप्त जल था, मतलब 4000 घनमीटर से ज्यादा प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता थी जबकि आज विश्व में 1700 घनमीटर ही प्रति व्यक्ति अगर जल उपलब्ध है तो उसको संतोषजनक माना जाता है । अगर 1700 घनमीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता है, जिसको पर कैपिटा वॉटर अवेलेबिलिटी कहते हैं, तो वही संतोषजनक होता है । लेकिन हमलोग कहां 4000 पर थे और चिन्ता की यह बात है कि अभी जो अद्यतन 2021-22 के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से हमलोग लगभग 1460-1468 घनमीटर पर पहुंच गए हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है महोदय, उसके हिसाब से अगर 1700 से नीचे जाता है प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, तो वह एक तरह से पानी के लिए दबाव में आने की स्थिति है । मतलब एक तरह से जो हमलोग जल के मामले में मतलब बेफिक्र रहने वाली स्थिति में थे, इतनी जल की उपलब्धता थी, आज हमारे यहां जल की उपलब्धता जल के उपयोग के कारण उसकी मात्रा सीमित होती जा रही है और प्रति व्यक्ति जो हिस्सा पड़ता है उसके हिसाब से अब हम दबाव महसूस करने लगे हैं और अगर यही क्रम जारी रहा तो समझिए अगले 10 वर्ष में अनुमान है कि हमलोग लगभग साढ़े 1300 घनमीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता से भी नीचे आ जायेंगे और मानक यह कहता है कि अगर 1000 घनमीटर जल उपलब्धता से हमलोग नीचे आ गए तो वह जलाभाव की स्थिति होती है, मतलब हर व्यक्ति जल की कमी महसूस करने लगेगा, लोगों को घर में जल मिलने में, जलापूर्ति में दिक्कत होगी और यही कारण है कि आज एक-एक बूंद जल के उपयोग को देखने की जरूरत है, उसके सदुपयोग की जरूरत है और जल उपयोग में जो दक्षता लाने की बात होती है कि वॉटर यूज एफिसिएंसी या जल उपयोग दक्षता जिसको कहते हैं कि जो काम हमलोग आदतन भी एक बाल्टी पानी से नहा सकते हैं तो 4 बाल्टी से नहाते हैं, एक बाल्टी में पानी से कपड़ा धो सकते हैं तो चार बार उसको निकालते हैं तो ये सबकुछ आदत हमलोगों को बदलनी चाहिए । मान लीजिए हमारी पीढ़ी तो

निकल जाएगी लेकिन आने वाली जो हमारी संतति है, हमारी संतान है, भावी पीढ़ी है उसको हम कैसी पृथ्वी सौंपना चाहते हैं यह तो आज के इस युग में आज की जो पीढ़ी है उसको सोचने की जरूरत है और इसके बारे में तो गांधीजी ने ही हमलोगों को विचार दिया था, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, न्यासधारिता का सिद्धांत कि जो प्राकृतिक संसाधन आपको उपलब्ध है, इस पीढ़ी को उपलब्ध है, उसका हम उपयोग तो करें लेकिन उपयोग करें इस तरीके से जो जिस रूप में जिस मात्रा में हमें प्राकृतिक संसाधन मिला है, हमारी पीढ़ी को मिला है, हमलोग उसी मात्रा में, उसी रूप में हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम सौंप दें । यह हमारी पीढ़ी का दायित्व है और इसीलिए जल के उपयोग में दक्षता लाने की बात है । महोदय, हम सबलोग भाग्यशाली हैं इस मायने में कि हमें हमारे मुख्यमंत्री जैसा सजग नेतृत्व मिला है और अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि संयोग से उस समय आपके आसन पर मैं हुआ करता था और उसी समय एक प्रस्ताव आया था और सदन के सभी दलों के सदस्य, हमलोग सेंट्रल हॉल में बैठे थे, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो दिक्कत लोग महसूस कर रहे थे, उसपर पूरे दिन की चर्चा हुई थी, आप भी उसमें शामिल थे, आपको भी स्मरण होगा और उसके बाद हमलोगों ने जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको लॉन्च किया था और अगर उसके अलग-अलग अवयवों को देखेंगे तो 11 अवयव में 9 अवयव सिर्फ जल से जुड़े हुए हैं तो जल उपलब्धता के बारे में या जो उपलब्ध जल है उसके संचयन के बारे में इससे बड़ी जागरूकता नहीं हो सकती है और उस जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम को लगातार सभी जगह, सभी सूबे में, सभी मुल्क में सराहा जा रहा है और आज यह देश और दुनिया की आवश्यकता है कि हम अपने यहां जल का संचयन करें, संरक्षण करें और जल को जब तक हम संसाधन नहीं समझेंगे, रिसोर्स नहीं समझेंगे, पूंजी नहीं समझेंगे, पानी है तो बहा देना है, सो नहीं है जल को अपनी संपत्ति समझना चाहिए । उसको यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए और ठीक कह रहे थे हमारे एक माननीय सदस्य, खासतौर से सिंचाई विभाग का जुड़ाव जल संचयन या जल उपलब्धता के बारे में संवेदनशीलता के

संबंध में जो है वह सबसे अधिक है क्योंकि जितना जल हमलोग उपयोग करते हैं, उसका 80 प्रतिशत सिंचाई के काम में जाता है बाकी 20 प्रतिशत में सब काम होता है और सिंचाई के काम में भी जल की बर्बादी 25-30 परसेंट तक होती है । जरूरत से ज्यादा जल मतलब खर्च हो जाता है, जितने जल की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो भी खेती करने वाले लोग हैं, जैसे खरीफ के फसल में ही धान की खेती में जब पानी देखिएगा कि लोग पूरा लगाकर छोड़ देते हैं, उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है । जो खरीफ फसल होता है उसकी खासियत होती है कि पानी लगने से भी वह खराब और बर्बाद नहीं होता है । अगर रबी में गेहूं के खेत में पानी लगा दीजिए तो वह गल जाएगा लेकिन खरीफ में धान में अगर पानी लगा दीजिए तो वह गलता नहीं है लेकिन पैदावार भी पानी लगाकर छोड़ दीजिए या सिर्फ उसके जमीन के भूमि को नमीयुक्त रखिए तो दोनों के पैदावार में भी फर्क आता है । पानी लगाने से, लेकिन चूंकि पानी लगा देने से भी फसल ठीक ही रहती है इसलिए लोग पानी लगाकर छोड़ते हैं अब समझिए उसमें से 30 परसेंट पानी बर्बाद चला जाता है । इसलिए महोदय, उन चीजों को भी हमें देखना होगा और हमें इस संबंध में बातें करनी होंगी । महोदय, अब मैं कुछ जो हमारी योजनाएं हैं उनका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं । (क्रमशः)

टर्न-27/सुरज/20.02.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : आप भी महोदय उसमें शामिल थे । हमलोगों के एन0डी0ए0 की सरकार में ही जो 2020 में बन रही थी, उसी वक्त हमलोगों ने सात निश्चय पार्ट-2 लागू किया था और जनता से जनादेश, मैनडेट हमलोगों ने सात निश्चय-2 के आधार पर ही लिया था । अभी कह रहे थे, ये लोग बराबर कहते हैं कि आप इधर से उधर चले गये, हम कहां चले गये । हम तो इन्हीं के साथ जनता से मैनडेट लिये थे, इन्हीं के साथ आ गये तो इसमें कौन-सी गलत बात है । यह तो जनता के मैनडेट के हिसाब से हमलोगों ने काम किया है और महोदय अगर आप उसमें देखियेगा तो उसका भी सबसे महत्वपूर्ण अवयव जो है सात निश्चय-2

का कि घर खेत को सिंचाई पहुंचाने का मतलब इस एन0डी0ए0 हुकूमत की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों के दु:ख दर्द को दूर करने की है । महोदय, हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के लिये सिंचाई का क्या महत्व है । यह कहने की बात नहीं है । कृषि की आत्मा ही सिंचाई से जुड़ी हुई है और हमलोग उसमें लगातार और महोदय विभाग के नाम पर भी जब गौर करियेगा तो इससे भी जल के बढ़ते महत्व का प्रदर्शन होता है । इस विभाग का पहले नाम था नदी घाटी योजना । पहले आपको याद होगा शुरू में इस विभाग को कहते थे नदी घाटी योजना विभाग, रिवर वैली प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट । बाद में इसका नाम पड़ा इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई डिपार्टमेंट और अब हो गया है जल संसाधन विभाग । ये नामाकरण में परिवर्तन भी अपने आप में कुछ कहता है और कहता यह है कि अब हमको जल के उपयोग के प्रति सजग होना होगा, संवेदनशील होना होगा, जल को एक संसाधन समझना होगा । महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं, कहने को तो बहुत है अब पांच ही मिनट है । चन्द्र शेखर जी शिक्षा विभाग में कह दिये हैं । हमारी अनेक योजनाएं हैं हर खेत को हम सिंचाई का पानी पहुंचा रहे हैं उसमें लगातार हमने काम किया है । अभी पिछले वर्ष मुझे बताते हुये खुशी हो रही है कि लगभग सवा दो लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों में हमलोगों ने अतिरिक्त सिंचाई सिंचन क्षमता सृजित की है और इतने खेत में सिंचाई दे रहे हैं इसलिये इसी तरह और भी महोदय आप भी कभी देखे होंगे गंगा जल । गंगा जल परियोजना की बात सबलोगों ने की है । भाई गंगा जल की क्या बात है, गंगा नदी की । कहा जाता है गंगा नदी शिवजी की जटा से निकली है और स्वर्ग से बहकर आती है । एक स्नान करिये और सारे पाप धूल जाते हैं । क्या-क्या नहीं कहा जाता है कष्टहरणी है, पापनाशनी है, मोक्षदायिनी है ऐसा पवित्र जल है गंगा नदी का और उस नदी के जल को अब समझिये कि हाथीदह से उठाकर और राजगीर, गया, बोधगया, नवादा इन सब इलाकों में पहुंचाने की योजना क्रियान्वित हुई है और मुझे बताते हुये हर्ष हो रहा है कि इन सब इलाकों में पानी पहुंचा दिया गया है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर जल उपलब्ध कराया जा रहा है । महोदय, आज से 10 साल पहले इन

सब चीजों की मांग तो छोड़ दीजिये, कल्पना भी नहीं की थी, जिसको जल संसाधन विभाग आज क्रियान्वित करके बिहार की जनता को समर्पित कर दिया है । अब मैं अगर शिक्षा विभाग की कुछ बात और भी महोदय । मैं लिखित भाषण रख दूंगा योजनाओं के संबंध में । सिमरिया घाट योजना है महोदय सिमरिया पूरे बिहार में समझिये बिहार का हरिद्वार है । वह धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, दिनकर से जुड़ा हुआ है । यह सबका केन्द्र है और उस घाट को विकसित करने की जो योजना चल रही है लगभग आधी पूरी हो गयी है । आप भी महोदय कभी राजेन्द्र सेतु से गुजरियेगा और शाम में देखियेगा तो आपका भी बरबस मन करेगा गाड़ी रोककर थोड़ी देर जाकर गंगा किनारे ठंडी हवा में थोड़ा आत्मा शुद्धिकरण कर लें । यह बरबस खींचता है, आकर्षित करता है । महोदय, वहां का दृश्य, वहां का मनोरम दृश्य उभरकर सामने आ रहा है । महोदय और भी योजनाएं हैं कई का हमारे साथियों ने भी जिक्र किया है वह सब योजनाओं के संबंध में जो मेरा प्रतिवेदन है इसको मेरे इस भाषण का अंग बनाने का आप निदेश देंगे । इसके साथ ही परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग से भी जुड़ी कुछ बातें हैं, जो कुछ प्रतिवेदन है संसदीय कार्य विभाग का भी प्रतिवेदन है इसको भी मैं रखूंगा इसका भी अंश बना दीजियेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य में था, ताज्जुब हो रहा था कि जब डॉ0 चन्द्र शेखर जी कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि यह बहाली हमने की । महोदय, यही मुख्यमंत्री जी ने भी बराबर बताया है, यही तो गठबंधन के टूटने का एक कारण बना कि जब सब काम मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, अनावश्यक श्रेय, क्रेडिट लेने की जो होड़ चली ये कौन नहीं जानता है कि नियुक्तियां किसके समय में हुई और हमलोग एन0डी0ए0 में थे, एन0डी0ए0 की जब हुकूमत बनी थी तो 4 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, यह कौन भूल जाता है । महोदय, इनसे पहले शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था उस समय लगभग 50 हजार नियुक्तियां हुई थी

और बी0पी0एस0सी0 से नियुक्ति की बात का जो ये श्रेय लेना चाहते हैं । महोदय, हम आज आसन के माध्यम से सदन को और बिहार की जनता को पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि बी0पी0एस0सी0 से परीक्षा लेने का निर्णय इनके शिक्षा मंत्री बनने से बहुत पहले लिया जा चुका था और मुख्यमंत्री के निदेश पर जब मैं शिक्षा मंत्री था उसी का निर्णय था और सबकुछ हो चुका था इसलिये इनको पता है कि जो सातवें चरण की नियुक्तियां थी, जिसमें 01 लाख से अधिक नियुक्ति होने वाली थी उसको हमने ही रोका था कि बी0पी0एस0सी0 से एग्जाम लेकर योग्य शिक्षक, प्रतिभावान शिक्षक की हम नियुक्ति करेंगे इसलिये हमने रोका था, इसलिये सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और हम ही लोगों ने रोककर बी0पी0एस0सी0 से बहाली की, नियुक्ति करायी थी और यह कह रहे थे, अपना तिथि गिना रहे थे । हमने तो उससे इंकार नहीं किया कि जब नियुक्ति हो रही थी तब ये शिक्षा मंत्री थे लेकिन शिक्षा मंत्री थे जरूर लेकिन नियुक्ति तब संभव हो पायी जब ये दफ्तर जाना भी छोड़ दिये तभी नियुक्ति हो पायी । जब तक जाते रहे तब तक नियुक्ति में अड़चनें आती रही इसलिये यह सब लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के रूप में अब हम तो कुछ कहना नहीं चाहते थे लेकिन खांमखां उन्होंने मुंह में ऊंगली डालकर बारबार मेरा नाम लेकर, मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और महोदय यह मैं आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को बिल्कुल स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि बी0पी0एस0सी0 से शिक्षकों के प्रतिभावान या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये योग्य शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के परामर्श पर उस समय शिक्षा विभाग ने लिया था, जब शिक्षा विभाग का प्रभारी मैं था । इनके समय में तो सिर्फ अधिसूचना जारी हुई थी इसलिये ये सारे तथ्य हैं । इन सब चीजों के आलोक में, महोदय अब ये लोग तो हैं नहीं लेकिन जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव दिया है हम उनसे आग्रह करते हैं कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और जो शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और संसदीय कार्य विभाग से भी जुड़े जो प्रतिवेदन हैं या जो मेरा वक्तव्य है उसको कार्यवाही का हिस्सा बनाने का आप नियमन दें ।

अध्यक्ष : दे दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसके साथ मैं अपील करता हूं, विपक्ष के सदस्य तो हैं नहीं कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लें । ये सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग बिहार में किसानों के हित में सिंचाई संसाधनों की बढ़ोतरी में हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं इसलिये हमारी मांग की स्वीकृति दें ।

(परिशिष्ट - 1,2,3,4 एवं 5 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 4398,51,79,000/- (चार हजार तीन सौ अंठानवे करोड़ इक्यावन लाख उनासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 फरवरी, 2024 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 40 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-21 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

बजट सत्र 2024-25 के दौरान सदन में

अभिभाषण

Talking Points

"हर खेत तक सिंचाई का पानी" एक महत्वाकांक्षी योजना

- 'हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के क्रियान्वयन द्वारा अब तक राज्य के 2 लाख 28 हजार 457 हे० क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने में सफल हुआ है।
- अब तक कुल चयनित 1198 में से 1180 योजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् कुल 653 योजनाएँ पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 45 अदद् योजनाऐं मनरेगा मद से पूर्ण की गयी है। कुल 533 योजनाओं का कार्य प्रगति में है।

गंगा जल आपूर्ति योजना के पहले चरण के तहत् पेयजल आपूर्ति आरंभ

- जल संसाधन विभाग के द्वारा **जल-जीवन-हरियाली अभियान** के तहत् शुरू की गई पेयजल की अति महत्वाकांक्षी योजना "**गंगा जल आपूर्ति योजना**" के पहले चरण में राजगीर, गया एवं बोधगया शहरों के बाद नवादा शहर को भी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 ली० शुद्ध गंगा जल उपलब्ध करा दिया गया है।
- "**गंगा जल आपूर्ति योजना**" के सफल कार्यान्वयन से राजगीर, गया एवं बोधगया शहरों में जल संकट दूर हीं नहीं किया गया है बल्कि 2051 तक की आकलित जनसंख्या के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित् की गई है। राज्य सरकार के द्वारा 4515.70 करोड़ रुपए की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया गया है।
- "**गंगा जल आपूर्ति योजना**" के दूसरे फेज के अंतर्गत बिहारशरीफ शहर को भी वर्ष 2036 की आकलित जनसंख्या के अनुसार गंगा जल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट निर्माण एवं इसका सौन्दर्यीकरण कार्य

- बेगूसराय स्थित सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट निर्माण एवं इसका सौन्दर्यीकरण कार्य को कुल 114.97 करोड़ की लागत से तीव्र गति से किया जा रहा है।
- योजना के तहत् 250 मीटर की लम्बाई में सीढ़ी घाट निर्माण कार्य, श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु बहुमंजिली धर्मशाला का निर्माण कार्य, संपूर्ण कल्पवास मेला क्षेत्र लगभग 1,09,000 वर्गमीटर के विकास के साथ-साथ सड़क, पाथवे निर्माण, पौधारोपण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

- अवशेष 300 मीटर की लम्बाई में सीढ़ी घाट निर्माण के साथ-साथ रीवर फ्रंट विकास के अन्य कार्यों सहित कई अन्य सुविधाओं का कार्य प्रगति में है।

नदी जोड़ योजना

- राज्य के अंदर की छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया गया है।

  बागमती - बूढ़ी गंडक (बेलवाधार) नदी जोड़ योजना का कार्य रूपये 130.88 करोड़ की राशि से पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में कराया जा रहा है। जिसको मई 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

  बागमती नदी - बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की शांतिधार योजना का कार्य रूपये 120.96 करोड़ की राशि से समस्तीपुर जिला में कराया जा रहा है। जिसको जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

  गंडक-अकाली नाला (छाड़ी) - गंडकी-माही-गंगा नदी जोड़ योजना का कार्य रूपये 69.89 करोड़ की राशि से गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में कराया जा रहा है। जिसको जनवरी 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- कार्यान्वित योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में छोटी-छोटी नदियों को जोड़ने के तहत् कई अन्य योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

- राज्यान्तर्गत नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा का विकास एवं भू-जल पुनर्भरण का लाभ मिलेगा।

भौतिकीय प्रतिमान केन्द्र

- सुपौल जिलान्तर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्श (उत्कृष्टता केन्द्र) के तहत् वीरपुर में भौतिकीय प्रतिमान केन्द्र की स्थापना का कार्य रु० 94.01 करोड़ की लागत से लगभग पूर्ण कर लिया गया है।
- इस केन्द्र की स्थापना एवं निर्माण होने से जल विज्ञान से संबंधित जटिल समस्याओं के अध्ययन, प्रयोगों एवं उसके निष्कर्ष से अभियंत्रण कार्यों में मदद मिलेगी।

- इस केन्द्र से बिहार के साथ-साथ अन्य सीमावर्ती राज्यों को जल विज्ञान के क्षेत्र में नदियों के लिए मॉडल टेस्ट की सुविधा मिल सकेगी। बिहार जैसे बाढ़ ग्रसित राज्य के लिए भविष्य में भौतिकीय प्रतिमान केन्द्र बाढ़ प्रबंधन में मील का पत्थर साबित होगा।

बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना
(Bihar Integrated Water Resources Management Project)

- प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए 'एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना तैयार किया गया है जिससे राज्य के सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे ।
- इस परियोजना की कुल राशि 4415 करोड़ रूपये है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है ।

परियोजना के अवयवों के अंतर्गत मुख्य प्रस्तावित कार्य

1. **संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माणः-**

   बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केन्द्र, गणितीय प्रतिमान केन्द्र, वाल्मी एवं अन्य विभागीय संस्थानों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

   गाद प्रबंधन हेतु ड्रेजिंग के लिए आधारभूत संरचना सुविधाओं का निर्माण

   डैम, बराज, वीयर, नहर प्रणालियों में स्काडा (SCADA) का अधिष्ठापन

2. **कुशल सिंचाई प्रबंधनः-**

   राज्य के बाँधो एवं बराजों का पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण

   सोन पश्चिमी मुख्य नहर का आधुनिकीकरण

   कमला सिंचाई और पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी सिंचाई का पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण

   गंगा जल का मोरवे, बासकुंड, आंजन एवं अन्य जलाशयों में स्थानांतरण

   जल-जमाव वाले चौर क्षेत्रों का सतत विकास (हसनपुर ब्लॉक (समस्तीपुर), मधेपूर ब्लॉक (मधुबनी), कहलगाँव ब्लॉक (भागलपुर) और अन्य जल-जमाव या चौर क्षेत्र जैसे गंडक, बागमती, कमला और अन्य नदी बेसिनों में)

   प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधनः-

   गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा के संवेदनशील रीचों में नवीनतम तकनीक से बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य

   फल्गु-जलवार, कमला के धारों एवं अन्य लिंक चैनल को बाढ़ शमन के लिए जोड़ने का कार्य इत्यादि ।

प्रस्तावित बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अवयव के अंतर्गत नए जल स्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल ले जाने हेतु प्रस्तावित योजना में गंगा जल का मोरवे, बासकुंड, आंजन व अन्य जलाशयों में स्थानान्तरण एवं अन्य नदी जोड़ योजनाएं सम्मिलित है।

सिंचाई क्षमता का सृजन एवं पुनर्स्थापन

राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से कुल सृजित हो सकने वाली सिंचाई क्षमता, 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध मार्च, 2024 तक कुल 37 लाख 72 हजार 219 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हो जायेगा। इसमें वर्ष 2023-24 के दौरान 34 हजार 679 हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता सम्मिलित है। सिंचाई क्षमता सृजन के साथ-साथ वर्ष 2023-24 में कुल 2 लाख 17 हजार 208 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का कार्य पूरा किया गया है।

वर्ष 2024-25 में सिंचाई क्षमता का सृजन एवं पुनर्स्थापन का कार्यक्रम

- वर्ष 2024-25 में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई की सभी योजनाओं पर कार्य करा कर हमलोगों ने 1 लाख 25 हजार 468 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य रखा है।
- वर्ष 2024-25 में 4 लाख 23 हजार 325 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम है।

सिंचाई उपलब्धि

- वर्ष 2023 खरीफ के दौरान 2200.45 हजार हेक्टेयर खरीफ सिंचाई के लक्ष्य के विरूद्ध वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से 1975.22 हजार हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराई गई है।
- वर्ष 2023-24 में रब्बी सिंचाई के लिए 723 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अनुरूप सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है।

महत्वपूर्ण वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्य की प्रगति

पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज- II)

- पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज- **II**) के अंतर्गत रुपये **421.92** लाख के लागत से तीन पैकेज में तिरहुत मुख्य नहर का वि०दू० **790.00** से **909.40** के बीच मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी भौतिक प्रगति लगभग 54% है।

- इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था। इस मुख्य नहर का निर्माण कार्य पटना उच्च न्यायालय में दायर वादों के कारण अवरुद्ध था। विभाग के पक्ष में फैसला आने के उपरांत संबंधित क्षेत्र में अवरुद्ध मुख्य नहर के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है।

- इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन से मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी, पारु, सरैया, साहेबगंज, मुशहरी, मुरौल एवं सकरा; वैशाली जिले के जन्दाहा, महुआ, राजापाकड़ चेहराकला, वैशाली, लालगंज, भगवानपुर, पटेढ़ी बेलसर, गारौल, पातेपुर एवं हाजीपुर और समस्तीपुर जिले के पुसा, मोरवा, ताजपुर, समस्तीपुर उजियारपुर, सरायरंजन, दलसिंहसराय एवं विभूतिपुर के कुल 1.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। वर्तमान में समस्तीपुर जिले में नहर से वृहत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

- माह जून 2024 तक मुख्य नहर के वि०दू० 855.00 समस्तीपुर जिला तक नहर तथा संरचनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष कार्य

- पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की स्वीकृति वर्ष 1962 में प्रदान की गई। कतिपय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान के पश्चात वर्ष 1971 में योजना का कार्य प्रारंभ हुआ। भू-अर्जन संबंधी मामलों के जटिलता के कारण योजना रूकी रही।

- इस योजना के अवशेष कार्यों को वर्ष 2020 में राज्य योजना के अधीन रू० 2372.52 करोड़ की पाँचवी पुनरिक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की नहरों की गाद सफाई एवं उनके बाँधों तथा संरचनाओं का पुनर्स्थापन एवं अवशेष कार्य 810.00 करोड़ रूपये की लागत राशि से कराया जा रहा है।

- खरीफ अवधि 2023 में प्रथम बार पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली के सभी शाखा नहरों तथा प्रमुख वितरणियों के अंतिम छोर तक जलश्राव पहुँचाया जा सका जिसके फलस्वरूप मानसून-2023 के पूर्वाद्ध में अल्पवृष्टि एवं सुखाड़ जैसी स्थिति के बावजूद भी किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी।

पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग (ई०आर०एम०) योजना

- सारण, सिवान एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत 1.58 लाख हे० सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 1.47 लाख हे० सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन हेतु पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन (ई०आर०एम०) योजना रू० 2061.8288 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। वर्तमान में योजना की प्रगति 46.94% है।
- योजना के कार्यान्वयन के उपरांत गोपालगंज जिला के 14 प्रखंड, सिवान जिला के 18 प्रखंड तथा सारण जिला के 17 प्रखंड लाभान्वित होंगे ।

सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पूर्वी लिंक नहर के 0.00 कि०मी० से 10.20 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

- पूर्वी लिंक नहर (कुल लम्बाई-10.20 कि०मी०) के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य राशि रू० 235.2497 करोड़ रूपये की लागत से प्रारंभ की गई है। इस योजना के पूर्वी लिंक नहर के 7.46 कि०मी० में बिटुमिनस सेवापथ के निर्माण का प्रावधान भी किया गया है।
- इस योजना के कार्यान्वयन हो जाने से 1539 हेक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ एवं 1,64,102 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे औरंगाबाद जिले के 7 प्रखण्ड, गया जिले के 2 प्रखण्ड, अरवल जिले के 2 प्रखण्ड तथा पटना जिले के 5 प्रखण्ड लाभान्वित होंगे। योजना को जनवरी, 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

सारण मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 17.00 तक का पुनर्स्थापन कार्य।

- सारण मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 17.00 तक का पुनर्स्थापन कार्य प्रक्रियाधीन है, जिससे गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिलान्तर्गत 75,194 हे0 सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

- योजना के कार्यान्वयन के उपरांत सारण मुख्य नहर के 17.00 कि0मी0 तक का भाग लाईन्ड हो सकेगा, जिससे नहर के शुरूआती भाग में गाद की समस्या से निजात मिलेगी एवं नहर में प्रवाहित होने वाले जलश्राव में वृद्धि होगी एवं नहरों के अंतिम छोर तक अच्छी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के कार्यान्वयन से गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिला के कृषक लाभान्वित होंगे।

- इस योजना की प्राक्कलित राशि 33349.00 लाख रूपये (तीन सौ तेत्तीस करोड़ उनचास लाख) मात्र है तथा इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

डकरानाला पम्प नहर योजना

- इस योजना का निर्माण वर्ष 1994 में ही किया गया था। परन्तु उदघाटन के बाद ही यह योजना ठप्प हो गया। वर्तमान फेज-I के कार्य हेतु रू० 145.43 करोड़ रुपये की राशि से शीर्ष कार्य (आर०सी०सी० पम्प हाउस), भेन्ट, मुख्य नहर, फरदा वितरणी एवं इससे निकलने वाली वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन, लाईनिंग कार्य, 03 अदद् भी०टी० पम्प का अधिष्ठापन कार्य एवं विद्युत आपूर्ति कार्य किया जाना है। योजना को दिनांक जूलाई, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- इस योजना से लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा एवं मुंगेर जिला के मुंगेर सदर, जमालपुर एवं धरहरा प्रखंड के कृषकों को 3284 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

सिंघवारणी जलाशय योजना

- मुंगेर जिलान्तर्गत सिंघवारणी जलाशय योजना का कार्य रूपये 125.82 करोड़ की राशि से किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत कंट्रोल्ड गेटेड आर०सी०सी० वीयर का निर्माण, 04 अंडर स्लूईस गेट तथा 09 स्पिलवे गेट का निर्माण तथा मुख्य नहर का 31.70 आर०डी० तक संरचना सहित निर्माण कार्य किया जाना है।

- योजना के जल ग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध अतिरिक्त जल को संग्रहित करना तथा मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर, टेटियाबम्बर एवं संग्रामपुर प्रखंड के कृषकों को 1660 एकड़ क्षेत्र में

अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना को अप्रैल, 2025 तक पूर्ण किया जाना है।

जमुई जिलान्तर्गत कुण्डघाट जलाशय योजना

- महोदय, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सुखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुण्डघाट जलाशय योजना का निर्माण रू० 185.21 करोड़ की राशि के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इससे जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में कुल 2035 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजनांतर्गत बहुआर नदी पर 300 मी० लम्बा मिट्टी के बाँध के साथ गेटेड स्पीलवे, आर०सी०सी० बॉक्स आउटलेट एवं जलाशय से निःसृत वितरण प्रणालियों का निर्माण प्रावधानित है। योजना की भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत है। इस योजना को वर्ष 2024 में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

उत्तर कोयल जलाशय योजना

- उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्य की कुल राशि 2430.76 करोड़ रूपये है। अवशेष कार्य के अधीन Common Component में व्यय का वहन शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। साथ ही Bihar Component के अंतर्गत व्यय का वहन 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। बिहार राज्य अंतर्गत अवशेष कार्य के कार्यान्वयन 1367.61 करोड़ रूपये की राशि से किया जाना है । योजना के अधीन 294.71 हे० का भू-अर्जन किया जाना है, जिसमें आवश्यकतानुसार 163.80 हे० भूमि के भू-अर्जन की कार्रवाई प्रगति में है।

- इस योजना के अन्तर्गत बिहार भू-भाग के उत्तर कोयल दायाँ मुख्य नहर में अंतिम छोर (गया) तक नहर की पूरी लंबाई में लाईनिंग कार्य किया जाना है। योजना के क्रियान्वयन से बिहार राज्य अन्तर्गत औरंगाबाद एवं गया जिले में 95,521 हे० में सिंचन क्षमता हासिल की जा सकेगी। जिसके फलस्वरूप औरंगाबाद जिले के 8 तथा गया जिले के 4 प्रखंड लाभान्वित होंगे।

कैमूर जिलान्तर्गत तियरा एवं ढड़हर पम्प हाउस का निर्माण कार्य

- कैमूर जिलान्तर्गत तियरा पम्प हाउस का निर्माण एवं इसके वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य रू० 56.53 करोड़ तथा ढड़हर पम्प हाउस का निर्माण कार्य एवं लिंक नहर का निर्माण रू० 57.71 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। इस कार्य के फलस्वरूप क्रमश: 2065 हे० एवं 2716 हे० ह्रासित सिंचाई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- तियरा पम्प हाउस के निर्माण की प्रगति 86 प्रतिशत एवं ढड़हर पम्प हाउस के निर्माण कार्य की प्रगति 90 प्रतिशत है। तियरा पम्प हाउस से वर्ष 2023 खरीफ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

बक्सर जिलान्तर्गत कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य

- बक्सर जिलान्तर्गत कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य रू० 64.22 करोड़ की लागत से प्रगति में है। इस कार्य को जून, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत है।

2023 की बाढ़ का कुशल प्रबंधन

- जल संसाधन विभाग राज्य में बाढ़ की विभिषिका को कम करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहा है। सदन अवगत है कि विभाग के द्वारा जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर वर्ष 2022 से बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु निर्धारित बाढ़ अवधि को विस्तारित करते हुये '15 जून से 15 अक्टूबर' के स्थान पर '1 जून से 31 अक्टूबर' कर दिया गया है ताकि बाढ़ की आपदा से कारगर ढंग से निपटा जा सके।
- वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 की बाढ़ अवधि में विभाग द्वारा निर्मित मुख्य तटबंध कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। यह विभाग की एक बड़ी उपलब्धि रही है ।

कमला बलान बायाँ एवं दायाँ तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य (फेज-1, 2 एवं 3) का कार्यान्वयन

- **कमला बलान फेज-1** के तहत् कमला बलान पर निर्मित पिपरा घाट पुल से ठेंगहा पुल तक कुल **80 कि०मी०** की लम्बाई में तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। **कमला बलान फेज-2** के तहत् कमला

बलान बायाँ तटबंध फटकी कुट्टी से पुनाच एवं कमला बलान दायाँ तटबंध के ठेंगहा से पलवा तक कुल **56.20 कि०मी०** की लम्बाई में तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण का कार्य प्रगति में है। **कमला बलान फेज-3** अंतर्गत कमला बलान बायां तथा दायां तटबंध के कुल **70.66 कि०मी०** की लम्बाई में 111.29 (फुहिया) तक तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य निविदा निष्पादन के बाद प्रारंभ किया जा रहा है।

फेज-3 के तहत् योजना के कार्यान्वयन के बाद कमला बलान बायां एंव दायां तटबंध के पुरी लम्बाई में तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य पूर्ण हो जायेगा एवं बाढ़ से सुरक्षा के साथ-साथ मधुबनी जिला के नेपाल से सटे हुए जयनगर शहर से दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों, समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड एवं सहरसा जिला के महिषी प्रखंड तक परिचालन सुगम हो जायेगा। इसके अतिरिक्त सहरसा जिला के महिषी प्रखंड में कमला बलान बॉया तटबंध से कोसी दायॉ तटबंध के मिलन बिन्दू एवं समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड में कमला बलान दायॉ तटबंध से बागमती बायॉ तटबंध के मिलन बिन्दू तक पक्की सड़क से सम्पर्कता स्थापित होने के फलस्वरूप आवागमन एवं तटबंधों का निरीक्षण सुगम हो जायेगा ।

बाढ़ 2024 के पूर्व की तैयारी

- बाढ़ 2023 के दौरान क्षतिग्रस्त स्थलों तथा नदियों के व्यवहार एवं आक्रामयता को देखते हुए संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वर्ष 2024 बाढ़ के पूर्व 330.71 करोड़ रूपये की लागत से 75 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- कोसी एवं गंडक नदी के नेपाल भू-भाग में कराए जा रहे 20 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पर रुपए 32.17 करोड़ का व्यय करने का कार्यक्रम है। इस राशि की शत्-प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त होती है।
- आपदा प्रबंधन विभाग अन्तर्गत आपदा प्रषमन कोष की निधि के तहत् रुपए 331.97 करोड़ की लागत से 129 अदद् अन्य बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

बाढ़ से संबंधित पूर्वानुमान का विस्तार

- बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र द्वारा कोसी, गंडक एवं महानंदा नदी बेसिन का विभिन्न स्थलों के लिए आगामी 72 घंटे एवं 120 घंटे के लिए बाढ़ पूर्वानुमान के रूप में जलस्तर/जलश्राव मानसून अवधि में प्रसारित किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त केन्द्र के द्वारा गंगा नदी के बक्सर से कहलगॉव के बीच 7 विभिन्न स्थलों सहित कुल 42 स्थलों पर आगामी 72 घंटे एवं 120 घंटे के लिए जलस्तर के रूप में बाढ़ पूर्वानुमान प्रसारित किया जाता है।
- विभाग द्वारा जल प्रबंधन की आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बिहार में बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों तथा सूचनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं, आपदा विभाग तथा जिला प्रशासन एवं लोगों तक ऑन-लाईन के माध्यम से रीयल टाइम में पहुंचाया जा रहा है।

योजनाओं के सूत्रण, समीक्षा, निरीक्षण एवं प्रगति का प्रबोधन

- विभाग द्वारा योजनाओं के सूत्रण, समीक्षा, निरीक्षण एवं प्रगति के प्रबोधन, सिचाई एवं बाढ़ संबंधित सूचनाओं के प्रेषण में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
- विभाग की योजनाओं के प्रगति का अनुश्रवण मुख्यालय द्वारा रीयल टाइम में ऑन-लाईन किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता स्तर से कनीय अभियंता तक के पदाधिकरियों द्वारा योजनाओं के टेण्डेरिंग, कार्यादेश, भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, जियोटैग फोटोग्राफ, कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं, मशीन और श्रमबल की उपलब्धता इत्यादि से जुड़ी जरूरी सूचना मुख्यालय तक रियल टाइम में पहुँचाया जा रहा है जिससे योजनाओं का प्रबोधन सूक्ष्म स्तर पर किया जा रहा है।
- बाढ़ अवधि के दौरान उपयोग में लायी जाने वाली बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का विभिन्न केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भंडारों में उपलब्धता एवं खपत का भी रियल टाइम मोनिटरिंग किया जा रहा है।

विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि

नियुक्ति

अभियंत्रण सवंर्ग की क्षमता वृद्धि के लिए माह दिसम्बर, 2023 में सहायक अभियंता के पद पर विभाग में रिक्तियों को भरने हेतु 145 पदों पर सीधी नियुक्ति की गयी है।

प्रोन्नति

महोदय, वर्ष 2023-24 में विभाग अन्तर्गत सभी पदों पर काफी संख्या में प्रोन्नति दी गई।

- 259 सहायक अभियंता (असैनिक) को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति दी गई।
- इसी प्रकार 96 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को अधीक्षण अभियंता(असैनिक) के पद पर तथा 21 अधीक्षण को मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति दी गई ।
- 289 कनीय अभियंता (असैनिक) को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नत किया गया है।
- अभियंता प्रमुख के तीन पदों पर भी प्रोन्नति दी गई है।

महोदय,

जल संसाधन विभाग अपने मौलिक कार्य जैसे वृहद् एवं मध्यम सिंचाई, बाढ़ से सुरक्षा, तटबंध का निर्माण और जल निस्सरण की योजनाओं के निर्माण, उसके रख-रखाव एवं संचालन कार्य के अतिरिक्त पेयजल, पर्यटन, धार्मिक एवं पर्यावरणीय महत्व वाली बड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी अपना सक्रिय योगदान कर रहा है।

वर्ष 2024-25 के बजट में विभाग के लिए माँग सं०-49 के अन्तर्गत कुल 4398.5179 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। स्कीम व्यय हेतु 3212.63 करोड़ रुपए तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत 1185.8879 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

वाल्मीकिनगर में बहुउद्देशीय सभागार एवं अतिथि गृह का निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में भवन निर्माण विभाग के माँग सं०-03 के अन्तर्गत स्कीम व्यय हेतु 20.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है।

महोदय,

ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण राज्य में वर्षा के पैटर्न में काफी उतार चढ़ाव महसूस किया जा रहा है। जिसके कारण जल संसाधन विभाग की चुनौती एवं प्रासंगिता काफी बढ़ गई है। लोगों की भी विभाग से अपेक्षायें काफी बढ़ी है।

अपनी बातें समाप्त करने से पहले मैं एक बार पुनः यह कहना चाहूँगा कि हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हम अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति से सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन से संबंधित जन-कल्याण एवं जनोपयोगी कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने एवं सभी चुनौतियों से निपटने में हम सफल होंगे। माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करते हुए सदन से अनुरोध है कि प्रस्ताव के अनुसार विभाग की माँग प्रस्तावों की स्वीकृति देने की कृपा करेंगे। सदन से अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग के लिए प्रस्तावित बजट उपलब्ध कराया जाए। विभाग सभी कार्यक्रमों को स-समय पूरा करने के प्रति दृढ़संकल्पित है।

धन्यवाद !

परिशिष्ट–2

शिक्षा विभाग

माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य (2024–2025)

(दिनांक– 20.02.2024)

जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारो का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। हर किसी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, और माँ पहली पाठशाला की गुरू होती है। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, जिसकी सहायता से बड़ी से बड़ी कठिनाईयों का सामना कर सकते है। शिक्षा से अपने जीवन में सही गलत में भेद कर सकते है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने सपने पुरे कर सकते है। इससे जीवन को नये दशा और दिशा दे सकते है।

राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खास कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों–बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है। वर्त्तमान में कुल बजट का बड़ा भाग लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। विभाग का ये लगातार प्रयास है कि बिहार के हर बच्चे का समग्र एवं सृजनात्मक विकास हो और प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक बिहार अपने प्राचीन गौरव को हासिल कर सके।

विभाग द्वारा सभी सरकारी **विद्यालयों के अनुश्रवण की व्यवस्था** बनाने के उदेश्य से राज्य स्तर पर एक केन्द्रीयकृत कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किया गया है। जिसमें शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु आम जन के लिए टॉल फ्री नंबर–14417 तथा 1800 3454 417 जारी किया गया है। सेन्टर के स्थापित होने से क्षेत्र की समस्याओं का द्रुत गति से निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सहायता से प्रतिदिन 40,000 प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करवाया जा रहा है।

विद्यालय में अध्ययनरत कमजोर बच्चों के शैक्षिक स्तर को सुधारने हेतु वर्ग 3 से वर्ग 8 के लिए **मिशन–दक्ष** कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत शिक्षकों द्वारा कमजोर छात्रों को चिहिन्त कर विद्यालय की गतिविधि के बाद विशेष कक्षा का संचालन किया जाता है।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभाग द्वारा छात्रों की शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिये अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषय के शिक्षकों के सहायता से विद्यालय समय के बाद **विशेष कक्षा** का संचालन किया जा रहा है। इच्छुक छात्र/छात्रा नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त विशेष कक्षाएँ में भाग लेते है।

कम्प्यूटर लैब का अधिष्ठापन BOO (Build-Own-Operete) मॉडल के आधार पर किया गया है, जिसके अन्तर्गत चिन्हित एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर के साथ–साथ ICT Instructor एवं Night Guard की सेवा प्रदान की गई है। राज्य के सभी मध्य विद्यालय में 10 कम्प्यूटर तथा माध्यमिक विद्यालय में 20 कम्प्यूटर लगा कर सभी छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए ICT Lab की स्थापना की गई है।

विद्यालयों के लगातार निरीक्षण एवं अनुश्रवण करने के फलस्वरूप राज्य के सभी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति के आशातीत वृद्धि हुई है। विद्यालय में बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए Sitting Capacity बढ़ाने हेतु **प्रीफैब स्ट्रक्चर (फर्निचर सहित)** का निर्माण कराकर छात्र/छात्राओं को बैठने की सुविधा प्रदान की गई है।

विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों के माध्यम से राज्य के सरकारी **विद्यालयों में साफ–सफाई** हेतु एक व्यवस्था कायम की गई है। जिसके अन्तर्गत एजेन्सी के स्टाफ के माध्यम से विद्यालय के वर्ग कक्ष, प्रागंण, शौचालय इत्यादि की साफ–सफाई करवाई जा रही है।

राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों के रख–रखाव, जीर्णोद्धार एवं रंगाई–पोताई कार्य आवश्यकता अनुसार शीघ्रता से करवाने के लिए विभाग द्वारा जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियंत्रण में **अभियंत्रण कोषांग** का गठन किया गया है। इस कोषांग के द्वारा जिले के सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर विद्यालय के रख–रखाव का कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही राज्य के 20 माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों को चयनित कर **उन्हें "मॉडल विद्यालय"** के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2023 में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल 1,04,648 **अध्यापकों की नियुक्ति** की गई है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् पटना द्वारा सभी प्रशिक्षण संस्थानो एवं विपार्ड की सहायता से प्रति सप्ताह 20,000 प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के लिए 06 दिवसीय एवं 15 दिवसीय **आवासीय प्रशिक्षण** का संचालन किया जा रहा है। अभी तक 2,93,678 प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 09 से 12 छात्र/छात्राओं के लिए **विशेष वर्ग संचालन एवं मासिक परीक्षा** का आयोजन का प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों का खेल–कूद के लिए **खेल का मैदान** विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के विशिष्ट शिक्षकों के लिए **सक्षमता परीक्षा** आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को प्राधिकृत किया गया है।

मुख्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग के सचिवालय एवं निदेशालयों को ई–ऑफिस से जोड़ा गया है तथा कार्यालय के सभी संचिकाएँ ई–ऑफिस के माध्यम से संचालित की जा रही है।

परिवहन विभाग बजट अभिभाषण वर्ष 2024–25 की मुख्य विशेषता

1. **मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजनाः–** विभागीय अधिसूचना सं0–8803, दिनांक–23.11.2023 द्वारा राज्य में प्रखण्डों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना को लागू की गई है। इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखण्डों को छोड़कर शेष 496 प्रखण्डों में प्रति प्रखण्ड अधिकतम 7 लाभुकों (दो अनुसूचित जाति, दो अतयन्त पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सामान्य वर्ग) को बस के क्रय पर प्रति बस 5,00,000/– (पाँच लाख रू0) का अनुदान का भुगतान किया जायेगा। जिस प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से ज्यादा होगी, उस प्रखण्ड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जायेगा।

2. **पी0एम0ई0 बस सेवा योजनाः–** विभागीय अधिसूचना सं0–9204, दिनांक–06.12.2023 द्वारा बिहार के प्रमुख शहरों यथा–पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियाँ शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने हेतु "पी0एम0ई0 बस सेवा " योजना लागू की गई है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा "पी0एम0ई0 बस सेवा " योजना के तहत बिहार के 06 शहरों में यथाः– पटना–150, मुजफ्फरपुर–50, गया–50, दरभंगा–50, पूर्णियाँ–50 एवं भागलपुर–50 सहित कुल 400 इलेक्ट्रिक बसें परिचालन किये जाने का योजना है। इस योजना के तहत उक्त 06 शहरों के बस पड़ावों का निर्माण किये जाने का योजना है।

3. **पूर्णकालिक दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठनः–** राज्य के अन्तर्गत वाहन जनित दुर्घटना के पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत देय मुआवजा के त्वरित भुगतान हेतु राज्य में सात पूर्णकालिक दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है। इसके लिये मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अर्हता प्राप्त सात सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति अध्यक्ष पद पर की गई है।

इस कदम से मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का त्वरित लाभ दुर्घटना पीड़ितों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली की संशोधित प्रक्रिया के अनुरूप उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(क) पटना, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा एवं दरभंगा प्रमण्डल में प्रत्येक के लिये एक–एक

(ख) भागलपुर एवं मुंगेर प्रमण्डल के लिये एक–एक

(ग) पूर्णियाँ एवं सहरसा प्रमण्डल के लिए एक

4. **बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023**:– विभागीय अधिसूचना सं0–9172, दिनांक–05.12.2023 द्वारा परिवेशीएं प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ––बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'' लागू की गई है, जो अधिसूचना निर्गत तिथि से पाँच वर्षो तक प्रभावी है। इस नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन, हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (मालवाहक वाहन), भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहन) आदि के क्रय में प्रोत्साहन राशि एवं टैक्स में छूट निर्धारित शर्तों के साथ दी गई है। तिपहिया वाहन (यात्री एवं मालवाहन) में केवल टैक्स में छूट का प्रावधान है।

इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु विभिन्न कोटि के चार्जर चार्जिंग स्टेशनों पर स्थापित किये जाने हेतु उपकरण के क्रय पर तथा अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा। भू–स्वामित्व, स्थापना का प्रकार, संचालन, संधारण तथा उपयोग के आधार पर राज्य में चार्जिंग स्टेशन के अंतर्गत निजी चार्जिंग स्टेशन, अर्द्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन एवं सार्वजनिक स्टेशन का मॉडल क्रियान्वित किये गये हैं।

5. **Scrapping Centre**:– पुराने वाहनों को Scrap करने के लिए निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना हेतु 14 आवेदकों को औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं एक आवेदक को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इस स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से 15 वर्ष पुराने वाहना अथवा अन्यथा अनुपयोगी वाहन को Scrap कराने वाले वाहन स्वामियों को समकक्ष नये वाहन क्रय करने पर उसके लिए देय मोटर वाहन कर में छूट की सुविधा प्रदान की जायेगी एवं पूर्व से लंबित देनदारियों में एकमुश्त छूट प्रदान की जायेगी।

परिशिष्ट–4

सूचना एव जन–सम्पर्क विभाग
बजट वक्तव्य के मुख्य बिन्दु

❖ सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग गौरवशाली बिहार के निर्माण हेतु न्याय के साथ विकास की अवधारणा को सरजमीं पर उतारने के लिए कृत संकल्पित है।

❖ सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का यह विभाग जनहित में विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर जन जागरूकता का कार्य कर रहा है।

❖ सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के लिए **वर्ष 2024–25** में **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में रु0 1,53,23,97,000/– (एक अरब तिरपन करोड़ तेईस लाख संतानवे हजार)** एवं **राज्य स्कीम मद के लिए रु0 1,01,00,00,000/– (एक अरब एक करोड़) कुल–2,54,23,97,000/– (दो अरब चौवन करोड़ तेईस लाख संतानवे हजार)** रुपये की राशि स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

❖ सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण–संवर्द्धन के लिए क्रियान्वित किये जा रहे "जल–जीवन–हरियाली अभियान" एवं "समाज सुधार अभियान" का भी सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। शराब के सेवन के दुष्परिणामों से संबंधित WHO की रिपोर्ट एवं महात्मा गाँधी के विचारों को समाहित करते हुए फोल्डर का वितरण राज्य के प्रत्येक घर–घर तक कराया गया। इससे नशा, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी बुराईयों के विरुद्ध समाज में नई चेतना फैल रही है।

❖ राज्य स्कीम (योजना) अंतर्गत विभाग द्वारा सामान्य प्रचार–प्रसार के लिए विशेष प्रचार योजना, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार के लिए विशेष अंगीभूत योजना, जनजातीय क्षेत्रों में प्रचार के लिए जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन सुविधा के लिए पत्रकार पेंशन योजना, पत्रकारों के बीमा के लिए बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना एवं बिहार संवाद समिति जैसे कार्यक्रम संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना से 783 तथा पत्रकार पेंशन योजना से 48 लाभान्वित हुए हैं।

❖ Information Technology का उपयोग करते हुए e-platform पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा (I) e-Advertisement, (II) Social Media Communication Hub की स्थापना, (III) Common Integrated Website का संचालन तथा (IV) PR Agency का उपयोग जैसे नवाचारी कार्य किये जा रहे है।

❖ सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार के सभी विभागों हेतु **Common Integrated Website** संचालित है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से युक्त यह एक **Dynamic Website** है, जिसे संबंधित विभागों द्वारा बड़ी आसानी से प्रयोग में लाया जा रहा है।

परिशिष्ट–5

63

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

संसदीय कार्य विभाग एक गैर योजना विभाग है। इस विभाग का मुख्य कार्य विधान मण्डल के संयुक्त बैठक एवं अन्य बैठकों का आयोजन करवाना/दोनों सदनों की बैठक हेतु कार्यक्रम तैयार करना/विधान मण्डल के प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/निवेदनों/आश्वासनो के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभागीय परामर्श समितियों का गठन करना तथा उनकी बैठकों का आयोजन करना/विधान मण्डलीय सदस्यों/मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना/विधायी कार्यों के सन्दर्भ में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना इत्यादि।

प्रस्तावित बजट प्राक्कलन 2024–25 के लिये स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का है। संसदीय कार्य विभाग में किसी तरह का राजस्व संग्रह नहीं है। वर्ष 2022–23 में ₹2,15,62,000/– वर्ष 2023–24 में ₹2,24,61,000/– का बजट उपबंध है तथा वर्ष 2024–25 में ₹2,72,11,000/– (दो करोड़ बहत्तर लाख ग्यारह हजार) का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

इस विभाग का प्रस्तावित उपबंध वर्ष 2024–25 को स्वीकृत नहीं करने पर विधान मण्डल से संबंधित कार्य यथाः– विधान मण्डल का सत्राहूत/सत्रावसान, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन बाधित हो जायेगा।

अतः वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रस्तावित उपबंध की स्वीकृति आवश्यक है।

8/1/24

अपर मुख्य सचिव।